

In Pursuit of Truth

वर्ष: 19 | अंक: 24
16 से 30 सितंबर 2021
पृष्ठ: 48
मूल्य: 25 रु.

आक्स

पाक्षिक



2024 में 400 पार !

मोदी पर ही
फिर दांव

विपक्षी एकजुटता की कवायद
लेकिन कौन होगा नेता?

भाजपाई राज्यों में नई जमावट
2024 चुनाव की अभी से तैयारी...

Anu Sales Corporation



When time matters,
Real 200 t/h throughput

Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.



**We Deal in Pathology
& Medical Equipment**

Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

M.: 9329556524, 9329556530  Email : ascbhopal@gmail.com

राजकाज

9

चुनौती बनते आदिवासी

मप्र में भील-भिलाला आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आदिवासियों का यह समूह निमाड़-मालवा में है। इस क्षेत्र में आदिवासियों के लिए आरक्षित तीन लोकसभा सीट रतलाम-झाबुआ, धार और खरगोन हैं।

राजपथ

10-11

चुनावी मोड़ में सत्ता-संगठन

निर्वाचन आयोग ने संकेत दे दिया है कि त्योंहारी सीजन के बाद प्रदेश में एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस ने मैदानी मोर्चा संभाल लिया है।

भरशाही

14

कागजों पर 200 करोड़ का मेटेनेंस

मप्र में पिछले डेढ़ दशक में रिकार्ड विकास हुआ है। लेकिन विकास के इस दौर में कई योजनाएं-परियोजनाएं ऐसी भी रही हैं, जो सफेद हाथी बनकर रह गई हैं। ऐसी योजनाओं-परियोजनाओं में सबसे अधिक जल संरचनाएं हैं।

आर्थिकी

16-17

निवेशकों की पहली पसंद मप्र

कोरोना संक्रमण के दौर में चौथी पारी शुरू करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को भांप लिया था कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश ही मप्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रख सकता है। इसलिए उन्होंने निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा दी थी।



2024 में लोकसभा चुनाव होना है। इसके लिए विपक्ष जहां एकता की कवायद में जुटा हुआ है, वहीं भाजपा जमावट में। भाजपा ने 2024 में 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य को पाने के लिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर ही दांव लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मोदी के दिशा-निर्देशों पर नई रणनीति बनाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी रणनीति का हिस्सा राज्यों में मुख्यमंत्री बदलना भी है।



राजनीति

30-31

विपक्षी एकता असंभव क्यों?

देश में भाजपा और नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष ने एकजुटता के कई प्रयास किए लेकिन सभी विफल रहे। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी एकता की कवायद फिर से शुरू हो रही है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जानकारों का मानना है...

महाराष्ट्र

36

राणे से किसको नुकसान...?

नारायण राणे की राजनीति का मौजूदा दौर कब तक ऐसे ही कायम रहेगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि भाजपा भी उनको तभी तक सपोर्ट करने वाली है जब तक उद्धव ठाकरे को डैमेज करने में वो सक्षम हैं। उद्धव ठाकरे की ही तरह नारायण राणे लगे हाथ उनके चचेरे भाई राज ठाकरे को भी नुकसान...

बिहार

38

पीएम मटीरियल नीतीश कुमार

सपने सभी देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी। लेकिन अगर उज्वल भविष्य का सपना वर्तमान को अंधकारमय करने लगे तो उसे सपना नहीं 'नॉनसेंस' कहते हैं। इस 'नॉनसेंस' शब्द का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार की...

6-7 अंदर की बात

40 विदेश

41 महिला जगत

43 कहानी

44 खेल

45 फिल्म

46 व्यंग्य



धर्म का तड़का...फायदा किसका...?

वि नोद बक्सरी का एक शेर है...

वादों में फिर से लगने लगा धर्म का तड़का
राम-रहीम के नाम पर फायदा किसका ?

पिछले कुछ दशक से देश की राजनीति में धर्म को आधार बनाकर चुनाव लड़ने की परिपाटी तेजी से बढ़ी है। जैसे ही चुनाव आते हैं राजनीतिक पार्टियां धर्म को आधार बनाकर घोषणाएं करने लगती हैं। इसका फायदा राजनीतिक पार्टियों को ब्रूब हो रहा है, लेकिन आम जनता के हाथ आज भी बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टमरी, महंगाई ही लग रही है। दरअसल, राजनीतिक पडितों को मालूम है कि धर्म भारतीयों की कमजोर नब्ज की तरह है। इसलिए समस्याओं से जूझ रहे भारतीय मतदाताओं को दिशा भ्रमित करने के लिए धर्म का मामला उछाल दिया जाता है। आगामी दिनों में उपर सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में भगवान राम, कृष्ण और उनके धर्म स्थलों के उत्थान के नाम पर बड़ी-बड़ी घोषणाएं होने लगी हैं। देश की जनता भी इस धर्म प्रवाह में बहने लगी है और बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टमरी, महंगाई की मार को भूलने लगी है। भले ही ऐसी दिशा भ्रमित घोषणाओं से जीत-हार तय होगी, लेकिन इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। एक विचारक ने चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव बताया था, पर दुर्भाग्य से अब हमारे देश में चुनाव के मौके पर त्योहारों जैसा आत्मीय माहौल नहीं होता। नेताओं के बीच विषममन का ऐसा झिलझिला शुरू होता है कि लोगों का मन खट्टा हो जाता है और व्यवस्था के प्रति अविश्वास गहराने लगता है। एक बार फिर से धर्म का तड़का लगाकर विषममन होने लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार चुनावी माहौल में धर्म का तड़का किसको फायदा देगा। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए नेताओं ने अभी से दांव चलने शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और विभिन्न राज्यों में भाजपा के कतिपय सांसद, विधायक और स्थानीय नेता भी हिंदूत्व के एजेंडे को बढ़ावा देने के इस काम में पूरे मनोयोग से जुटे हैं। एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत यह कहने से चूकते नहीं हैं कि देश में जो मुसलमान हैं वे हिंदुओं के वंशज हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा राम और कृष्ण भक्ति के नाम पर मुसलमानों को अपने से अलग कर रही है। इतना ही नहीं, संघ परिवार के कई आला नेता तो खुलेआम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की उद्घोषणा कर रहे हैं। इस सबके चलते समाज में वैमनस्य का वातावरण तो बन ही रहा है, साथ ही उन लोगों में भी हताशा का भाव भी पैदा हो रहा है। सबका साथ सबका विकास के वादे के साथ केंद्र की सत्ता में आई सरकार विकास को भूल गई है। अब लोगों को विकास के बदले जो मिल रहा है वह है रोज-रोज की सांप्रदायिक बयानबाजियां, धमकियां, दंगे-फसाद और धर्मांतरण की ओछी हरकतें। इससे न तो देश का विकास होना है और न ही जनता का। इस बात को राजनीतिक पार्टियों के साथ ही आम जनता को भी समझना होगा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट, नकारात्मक औद्योगिक और विनिर्माण विकास दर, खेती की जमीन घटने से पैदा हुए कृषि संकट और किसानों की आत्महत्या की ताजा घटनाओं ने भी सरकार के विकास के एजेंडे के ढोल की पोल खोल दी है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी जाति-धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर इसी तरह राजनीतिक पार्टियां ढंढं कराती रहीं तो देश में अशांति का माहौल बनेगा।

- राजेन्द्र आगाल

पाठक
अक्षर

वर्ष 19, अंक 24, पृष्ठ-48, 16 से 30 सितंबर, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लॉट नम्बर 150, जेन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,

एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल- 462011 (म.प्र.),

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718 MPEPL/642/2021-23

ब्यूरो

मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, कोलकाता:- इंद्रकुमार,

जयपुर:- आर.के. बिनानी, छत्तीसगढ़:- संजय शुक्ला,

मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे

098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया

094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार

098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली :- ईसी 294 माया इन्क्लेव

मायापुरी-फोन : 9811017939

जयपुर :- सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर

(राजस्थान) मोबाइल-09829 010331

रायपुर :- एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,

फोन : 0771 2282517

भिलाई :- नेहरू भवन के सामने, सुपेला,

रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015

इंदौर :- 39 श्रुति सिल्टर निगानिया, इंदौर

मोबाइल - 7000123977

स्वातधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 150, जेन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।



उपचुनाव का इंतजार

भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस उपचुनावों पर है। दोनों पार्टियां अपनी स्टाब बनाने और बचाने के लिए इन उपचुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं। पार्टियां अपने-अपने दावेदारों पर मंथन कर रही हैं। अब बस दोनों पार्टियों को उपचुनाव की तारीखों का इंतजार है।

● **महेश शिवदरे**, भोपाल (म.प्र.)

पैरेंट्स की दुविधा

कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन प्रदेश में स्कूल खोल दिए गए हैं। संक्रमण के कारण स्कूलों को भी निर्धारित गाइडलाइन का पालन करना होगा। फिलहाल तो कई पालक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पसोपेश में फंसे हुए हैं। अभी उनकी प्राथमिकता ऑनलाइन क्लासेस हैं।

● **इस्लाम खान**, इंदौर (म.प्र.)

आम आदमी को कर्ंट

मप्र में बिजली चोरी बड़ी वजह है जिसके कारण यहां उपभोक्ताओं को महंगी बिजली पड़ती है। मप्र देश में सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक है। लेकिन यहां 36 प्रतिशत से अधिक बिजली चोरी हो रही है। जिसका ब्रामियाजा आम आदमी भुगत रहा है।

● **सुनील बागल**, सीहोर (म.प्र.)



आतंक के खिलाफ लड़ाई

तालिबान की वापसी से सबसे अधिक नुकसान अमेरिका को पहुंचा है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को एक आतंकी गुट के हाथों पराजय झेलनी पड़ी। अमेरिका को खरदेड़ने में तालिबान को मिली कामयाबी से वैश्विक जिहादी मुहिम से जुड़े अन्य धड़ों को नई ऊर्जा मिलेगी। अफगानिस्तान की अस्ता में तालिबान की वापसी ने भारत की चुनौतियां बहुत बढ़ा दी हैं। वैसे भी अमेरिकी पराभव के साथ भारत के खिलाफ चीन-पाकिस्तान रणनीतिक गठजोड़ और मजबूत ही होगा। अन्य देशों को यह समझना होगा कि यदि अफगानिस्तान में तालिबान जैसे संगठनों का राज होता है तो ये दुनिया के लिए बहुत चिंतनीय है। इसके लिए सभी को साथ मिलकर आगे आना होगा।

● **नीलम कुशवाहा**, राजगढ़ (म.प्र.)

मजबूत हो कांग्रेस

कांग्रेस को अपने आप को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। बीते दो सालों में युवा नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के सिलसिले में तेजी आई है और ये कहीं न कहीं पार्टी के साथ ही गांधी परिवार के लिए भी खतरा की घंटी है। आए दिन कोई न कोई नेता कांग्रेस से भाजपा या अन्य पार्टियों में शामिल हो रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस आलाकमान से कांग्रेसी खुश नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष नेता ही कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हों। पार्टी से महिला कांग्रेस नेताओं की खानगी भी काफी बढ़ी है।

● **भरत खेनी**, नई दिल्ली

बच्चों पर ध्यान दे सरकार

भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का पीक गुजर जाने के बाद से लेकर अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बजाय बढ़ते ही दिख्राई दे रहे हैं। ब्रासकर बच्चों का ब्रास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए टीके का कोई इंतजाम नहीं हो सका है। सरकार को जल्द से जल्द छोटी उम्र के बच्चों के लिए भी टीके का इंतजाम करना चाहिए, ताकि कोरोना के डर को कम किया जा सके।

● **पंकज राजौरा**, जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जॉन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



आप की डिरेल होती गाड़ी

उत्तराखंड में अपने दम पर सरकार बनाने का सपना देख रही आम आदमी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इन दिनों खासा परेशान बताया जा रहा है। पार्टी सूत्रों की मानें तो आप के उत्तराखंड प्रभारी और दिल्ली विधानसभा के सदस्य दिनेश मोहनिया ने अरविंद केजरीवाल को भरोसा दिलाया था कि कांग्रेस और भाजपा के कई कद्दावर नेता आप में आने को आतुर हैं। मोहनिया ने ही रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने और राज्य को आध्यात्मिक प्रदेश बनाने सरीखे सुझाव केजरीवाल को दिए थे। जानकारों का दावा है कि आप की पॉलीटिकल अफेयर्स कमेटी (पीएसी) में प्रदेश को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा किए जाने को लेकर एक वरिष्ठ नेता ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उनकी बात को केजरीवाल ने नजरअंदाज कर डाला। बड़ी धूमधाम से देहरादून में केजरीवाल ने यह घोषणा तो कर डाली लेकिन जनता का फीका रिस्पॉन्स देख आप पार्टी के नेता खासे हतप्रभ हैं। जानकारों की मानें तो मोहनिया एंड टीम के लाख प्रयास करने के बाद भी आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय को अपनी तरफ खींच पाने में विफल रही। सूत्रों का दावा है कि केजरीवाल को पूरा भरोसा दिलाया गया था कि उपाध्याय आप में शामिल होने की हामी भर चुके हैं।

संकट में सोरेन परिवार

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों खासे चिंतित बताए जा रहे हैं। कारण है केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और इन्फॉर्मेट डायरेक्ट्रेट का उन पर कसता शिकंजा। रांची के सत्ता गलियारों में खासी चर्चा है कि मुख्यमंत्री सोरेन और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के खिलाफ इन दोनों एजेंसियों ने खासा मसाला तैयार कर लिया है जिसकी बिना पर शीघ्र ही ये एजेंसियां कोई बड़ा एक्शन ले सकती हैं। दरअसल सोरेन परिवार पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य के लोकपाल समक्ष एक याचिका डाल गंभीर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोप गत वर्ष लगाए थे। लोकपाल ने इस याचिका के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने को कहा था। खबर गर्म है कि पिछले एक बरस से गहरी छानबीन में जुटी सीबीआई ने अब राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए राज्यसभा के सभापति की इजाजत लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक इसी प्रकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए सीबीआई राज्य के गवर्नर से संपर्क करने वाली है। सोरेन समर्थकों का कहना है कि ऐसा सबकुछ भाजपा आलाकमान के इशारे पर राज्य सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है।



संकट मोचक की भूमिका से त्रस्त रावत

कांग्रेस आलाकमान की कार्यशैली अनोखी है। अगले वर्ष की शुरुआत में ही पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी नेतृत्व हर कीमत पर उत्तराखंड में कांग्रेस की वापसी और पंजाब में अपनी सरकार का दूसरा टर्म चाहता है। दोनों ही राज्यों में ऐसा होने की पूरी संभावना भी है। लेकिन आलाकमान की कार्यशैली ऐसा होने न देने की तरफ इशारा कर रही है। उत्तराखंड में पार्टी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के दम पर चुनाव मैदान में उतरने जा रही है, लेकिन रावत को पार्टी नेतृत्व ने पंजाब कांग्रेस के झमेले में बुरी तरह उलझाकर रखा है। रावत पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ-साथ पंजाब प्रांत के प्रभारी भी हैं। सूत्रों का कहना है कि रावत को आश्वस्त किया गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में जैसे ही वे सफल होंगे उन्हें प्रभारी पद से मुक्त कर दिया जाएगा। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हरीश रावत ने येन-केन प्रकारेण कैप्टन अमरिंदर सिंह को मना नवजोत की ताजपोशी करा ही डाली, लेकिन बेचारे रावत अभी तक पंजाब प्रभारी पद से मुक्ति नहीं पा सके हैं। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह के मध्य दिनों दिन विवाद गहराने के चलते रावत को पंजाब के मोर्चे पर बने रहने को कहा गया है।

नहीं रास आ रहा तमिलनाडु

तमिलनाडु की राजनीति पिछले कई दशकों से द्रमुक और अन्नाद्रमुक के मध्य सिमटी रही है। राष्ट्रीय दलों की स्थिति यहां बदहाल है। कांग्रेस की अंतिम सरकार यहां 1967 तक रही थी। भाजपा का कमल यहां कभी खिल नहीं पाया। 2014 के बाद से ही भाजपा इस दक्षिणी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन उसे खास सफलता मिल नहीं पाई है। दूसरी तरफ लगातार गलत कारणों के चलते तमिलनाडु भाजपा प्रदेश इकाई के नेता मीडिया की सुर्खियों में छापे रहते हैं। राज्य विधानसभा चुनावों में द्रमुक के हाथों मिली करारी पराजय के बाद भाजपा ने तमिलनाडु का विभाजन कर एक नए राज्य कोंगूनाडू बनाने की बात छेड़ विवाद पैदा कर डाला था। अब अपने एक महासचिव का सेक्स वीडियो सामने आने से भाजपा बैकफुट पर आती नजर आ रही है। सूत्रों की मानें तो तमिलनाडु भाजपा के महासचिव केटी राधवन का वीडियो सामने आते ही प्रदेश इकाई में जबरदस्त घमासान मच गया है।

जगन पर निगाहें

आंध्र प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाने को बैचन भाजपा हर कीमत पर राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को अपनी जकड़ में लेना चाहती है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि जगन एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने को राजी हो जाते हैं तो आंध्र की राजनीति में भाजपा को मजबूत होने का आधार मिल जाएगा। पार्टी ने इसके पहले कांग्रेस की बड़ी नेता डी पुरदेश्वरी को 2014 में भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। वर्तमान में पुरदेश्वरी भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव हैं। आंध्र प्रदेश में पार्टी को वे आशातीत सफलता दिला पाने में सफल नहीं हो सकी हैं। खबर गर्म है कि अब भाजपा जगनमोहन को साधने में जुट गई हैं। वाईएसआर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय रेड्डी संग भाजपा के कई नेताओं का संपर्क लगातार बना हुआ है। चर्चा जोरों पर है कि भाजपा की तरफ से वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विजय रेड्डी को केंद्र में मंत्री बनाने का प्रस्ताव भी दे दिया गया है।

40-70 का खेल

शीर्षक पढ़कर आप आश्चर्यचकित जरूर होंगे, लेकिन प्रदेश में ऐसे खेल कई जगह चल रहे हैं। यहां जिस मामले की बात हो रही है, वह शिक्षा से संबंधित है। दरअसल, प्रदेश के सबसे बदनाम विश्वविद्यालयों में शामिल एक विश्वविद्यालय में यह खेल चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के कुलपति के काले कारनामों की फाइल दबाए रखने के एवज में एक बड़े साहब के कहने पर यह खेल चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि एक विभाग के बड़े अधिकारी ने कुलपति महोदय पर दबाव बनाकर अपनी पत्नी को बड़े वेतन पर पदस्थ करवाया है। बताया जाता है कि बड़े साहब की पत्नी विश्वविद्यालय में 40 हजार रुपए मासिक के वेतन पर कार्य कर रही थीं। इसी दौरान साहब की नजर विश्वविद्यालय के कुलपति के काले कारनामों की फाइल पर पड़ी। फिर क्या था साहब ने कुलपति महोदय को जांच के नाम पर डराना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उनसे सौदा किया कि तुम्हारी जांच फिलहाल रुकी रहेगी, इसके एवज में मेरी पत्नी को बड़े वेतन वाले पद पर रखा जाए। फिर क्या था, कुलपति महोदय ने साहब की पत्नी को परामर्श देने के लिए अपने पास 70 हजार रुपए मासिक के वेतन पर रख लिया है। फिलहाल दोनों तरफ सोने पर सुहागा वाली स्थिति है, लेकिन कई लोग इस भाईचारे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और शिकायत-शिकायतों का दौर चल पड़ा है।

त्रिदेवियों की कारस्तानी

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों त्रिदेवियों की खूब चर्चा हो रही है। ये तीनों देवियां पुलिस महकमे में सब इंसपेक्टर हैं। इनकी पदस्थापना प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी की सीमा से सटे एक जिले के जिला मुख्यालय में है। तीनों एक ही बैच की हैं, इसलिए इनमें गहरी दोस्ती भी है। लेकिन इन तीनों की कारस्तानियों से उक्त जिले के लोग और वरिष्ठ अधिकारी परेशान हैं। तीनों देवियां अपनी वर्दी और महिला होने की आड़ में जमकर अड़ीबाजी कर रही हैं। आलम यह है कि ऐरे-गैरे नत्थू खैरे कोई भी हो वह इनके चंगुल से नहीं बच पा रहा है। स्थिति यह है कि अगर कोई इनकी अड़ीबाजी में आड़े आता है तो ये त्रियाचरित्र दिखाने से भी नहीं चूकती हैं। इनकी शिकायतें जिले के पुलिस मुखिया तक भी पहुंची है, लेकिन सीधे-साधे और महिला प्रेमी ये साहब उन त्रिदेवियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने पुलिस के मुखिया के पास लिखित में शिकायत भेजी है। अब देखना यह है कि सरकार के सुशासन पर दाग लगा रहें इन देवियों पर पुलिस के मुखिया किस तरह का अंकुश लगाते हैं।



अब नई पारी की तैयारी

अपनी कड़क और तथाकथित ईमानदार छवि के लिए ख्यात 1985 बैच के एक आईएएस अधिकारी जल्द ही नई पारी खेलते दिखेंगे। दरअसल, ये साहब कुछ समय बाद रिटायर होने वाले हैं। साहब के रिटायरमेंट से पहले ही उनकी नई पारी की पटकथा लिखी जाने लगी है। सूत्रों का कहना है कि साहब रिटायरमेंट के बाद राजनीति में अपना हाथ आजमाएंगे। साहब की मंशा को भांपते हुए कांग्रेस ने उनके लिए रेड कारपेट बिछा दी है। दरअसल, साहब जिस जिले के मूल निवासी हैं, उसी जिले से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले एक बड़े नेताजी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि रिटायरमेंट के बाद उक्त आईएएस अधिकारी कांग्रेस ज्वाइन करें। बताया जाता है कि इन दोनों में पहले से ही काफी नजदीकी है। इसलिए संभावना बढ़ गई है कि साहब रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस का हाथ थामकर राजनीति की नई पारी शुरू करेंगे। गौरतलब है कि वर्तमान समय में कई सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बैंकडोर से कांग्रेस की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये साहब अब खुले तौर पर राजनीति का हिस्सा बनने का मन बना चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में यह चर्चा भी जोरों पर है कि अपनी सेवाकाल के दौरान किसी की नहीं सुनने वाले ये साहब राजनीति में खरे उतर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि राजनीति में हर एक की सुननी पड़ती है। लेकिन साहब का मिजाज कभी भी ऐसा नहीं रहा है।

अफसरों का महिला प्रेम

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में वैसे तो अफसरों का महिला प्रेम हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन इन दिनों दो अफसरों की चर्चा खूब हो रही है। इनमें से एक हैं 1999 बैच के आईएएस अधिकारी। ये साहब कलेक्टर के दौरान भी अपने चरित्र को लेकर काफी चर्चा में रहे। इन दिनों वे जिस विभाग के मुखिया हैं उस विभाग में पदस्थ एक महिला अधिकारी से काम समझ रहे हैं। इसके लिए वे 1 से डेढ़ घंटे रोजाना उक्त महिला के साथ व्यस्त रहते हैं। लोग हैरान हैं कि आखिरकार इतने वरिष्ठ अधिकारी को अब काम समझने की नौबत क्यों आ रही है। ये साहब हाल ही में दिल्ली से लौटे हैं। वहीं एक विभागाध्यक्ष हैं, जिन्होंने ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। इन साहेबान ने अपनी महिला सहकर्मी को प्रतिनियुक्ति पर लाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। इन्होंने न केवल जोर लगाया बल्कि उक्त महिला को अपने साथ प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ भी करा लिया है। ऐसे में अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आईएएस अफसरों को महिला सहकर्मियों से इतना लगाव क्यों है। वैसे तो हकीकत सभी जानते ही हैं।

अनुदान पर अनुदान

वाकई मप्र अजब है, गजब है। यहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे नई सरकार गठित हुई है, कई मंत्री और उनके नाते-रिश्तेदार, भाई-भतीजे ऊपरी कमाई में जुट गए। इसके लिए तरह-तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन दिनों एक राज्यमंत्री के रिश्तेदार का मामला सामने आया है। उक्त मंत्रीजी के रिश्तेदार ने तो आवेदक से अनुदान पर ही अनुदान मांग लिया है। दरअसल, मंत्रीजी के पास कई ऐसे विभाग हैं, जो उस विभाग के अंतर्गत आने वाली जातियों को विभिन्न तरह के अनुदान दिए जाते हैं। ऐसे ही अनुदान के लिए एक जरूरतमंद ने आवेदन किया था। उक्त आवेदन में अपना काम जल्द कराने के लिए मंत्रीजी के रिश्तेदार से गुहार लगाई। फिर क्या था, मंत्रीजी के उक्त रिश्तेदार ने कहा कि आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन आपको अनुदान में मिलने वाली राशि में से मुझे भी अनुदान देना होगा। यह केवल एक विभाग की कहानी नहीं है, बल्कि लगभग हर विभाग में इसी तरह अनुदान पर अनुदान लिया जा रहा है।



औरत की सारी ताकत शादी को बचाने में खप जाती है, भले ही इसके लिए उसे अपने सपनों की बलि देकर आंसू छौंकना पड़े या किसी बाबा से भभूत लेनी पड़ी। इस बात का एहसास अब मुझे भी हो गया है। तलाक काफी खराब शब्द है।

● आयशा मुखर्जी



वे नेता जो विदेशी होटल में रह रहे हैं, उन्होंने अपने ही लोगों से धोखा किया। अब वे चाहते हैं कि गरीब अफगानी विद्रोह करें। मैं अफगानिस्तान के लिए अंतिम क्षणों तक लड़ता रहूंगा। मैंने अपने गार्ड से कह दिया है कि अगर मैं घायल हो जाऊं तो मुझे सिर में दो गोली मार देना, क्योंकि मैं तालिबान के सामने घुटने नहीं टेकना चाहता। मेरे साथ पूरा अफगानिस्तान है।

● अमरुल्लाह सालेह



हमें इंग्लैंड द्वारा भारत दौरे को पूरा करने के लिए वापसी वाली उस भावना को नहीं भूलना चाहिए जब 2008 में 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के कारण सीरीज को बीच में ही रोक दिया गया था। कुछ दिन बाद वे फिर वापस आए थे। जबकि वे यह कहने के पूरी तरह हकदार होते कि हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। हम वापस नहीं आएंगे।

● सुनील गावस्कर



सरकार लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, किसानों से घबराई हुई है, इसलिए किसानों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, हम तीनों कृषि कानून खत्म कराए बिना घर नहीं बैठने वाले। यह आंदोलन पूरे देश के किसानों का है।

● राकेश टिकैत



‘हॉलीवुड में ग्लोबल मोनोपली को क्रिएट कर के दूसरी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाया गया है। वो हमारी स्क्रीन पर कब्जा कर रहे हैं। हम मलयालम फिल्म के डब वर्जन के बजाय लायन किंग या जंगल बुक के डब वर्जन को देखेंगे। हमें पहले अपनी फिल्मों को एंजॉय करने की जरूरत है, चाहे वह मलयालम, तमिल, तेलुगु या पंजाबी हो। हमें अपने लोगों और अपनी इंडस्ट्री को अपनी प्रायोरिटी देनी चाहिए और हॉलीवुड फिल्मों को कम देखना चाहिए। यह एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का तरीका है।’

● सुष्मिता सेन

वाक्युद्ध

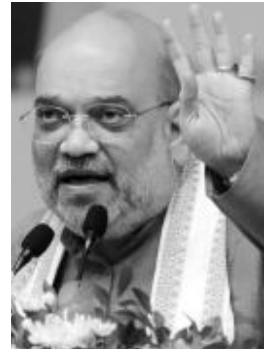


मैं कश्मीरी पंडित हूँ। मेरे पूर्वज भी कश्मीरी पंडित थे। इसलिए मेरा कश्मीर से बहुत लगाव है। लेकिन भाजपा ने कश्मीर को तबाह करने का बीड़ा उठाया है। मैं अपने कश्मीरी पंडित भाईयों से वादा करता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूंगा। क्योंकि सरकार की आर्थिक नीतियों ने देवी लक्ष्मी की शक्तियों को कम किया है।

● राहुल गांधी

हैरानी के साथ यह आश्चर्यजनक भी लगता है कि राहुल गांधी को आखिरकार कश्मीरी पंडित अपने लगे। अभी तक उन्हें शायद मालूम भी नहीं था कि वे कश्मीरी पंडित हैं। देश में सबसे अधिक बार कांग्रेस की सरकार रही है, फिर ऐसे में कश्मीर और वहां के पंडितों की दुदर्शा के लिए उनकी पार्टी ही तो जिम्मेदार है।

● अमित शाह



मप्र में भील-भिलाला आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आदिवासियों का यह समूह निमाड़-मालवा में है। इस क्षेत्र में आदिवासियों के लिए आरक्षित तीन लोकसभा सीट रतलाम-झाबुआ, धार और खरगोन हैं। इसी अंचल की एक लोकसभा

सीट खंडवा में उपचुनाव भी होना है। इस सीट पर आदिवासी वोट बेहद निर्णायक हैं। हालांकि यह सीट ओबीसी वोटों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। पिछले दो दशक में मालवा-निमाड़ के

आदिवासी अंचल में भाजपा अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पार्टी ने रतलाम-झाबुआ की आदिवासी सीट को जीता था। कांग्रेस के कद्दावर नेता कालिलाल भूरिया इस क्षेत्र से चुनाव नहीं जीत पाए थे। उनके बेटे विक्रान्त भूरिया विधानसभा का चुनाव हार गए थे। राज्य में आदिवासियों के लिए विधानसभा में कुल 47 सीटें आरक्षित हैं। 2008 में लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के परिसीमन से पहले विधानसभा की कुल 41 सीटें ही आदिवासियों के लिए आरक्षित थीं। राज्य में 22 प्रतिशत आदिवासी हैं। आदिवासियों की जनसंख्या में दशकीय बढ़ोतरी 25 फीसदी से अधिक की देखी गई है।

राज्य में कुल आदिवासी विकासखंडों की संख्या 89 है। एक तरह से देखा जाए तो आदिवासी वोटर विधानसभा की 90 सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस की स्थिति आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर हुई है। इसकी बड़ी वजह आदिवासी वोटों का विभाजन रहा है। खासतौर से महाकौशल के आदिवासी इलाकों में। यहां गोंड आदिवासी हैं। आदिवासियों की आबादी के लिहाज से गोंड नंबर दो पर आते हैं। पचपन लाख से अधिक गोंड आदिवासी हैं। प्रदेश की राजनीति में यह सर्वविदित तथ्य है कि गोंडवाना के नाम के राजनीतिक दलों को कांग्रेस के नेताओं ने ही आगे बढ़ाया।

साल 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उपयोग कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए किया था। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव नए परिसीमन के अनुसार हुए। इन चुनावों में भाजपा आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 में से 29 सीटें जीतने में सफल रही थी जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी पकड़ को मजबूत बनाकर रखा। कांग्रेस सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आदिवासियों के लिए आरक्षित 30 सीटें जीतने में सफल रही थी।

चुनौती बनते आदिवासी



जयस संगठन में फूट से भाजपा को मिल सकता है लाभ

मप्र में विधानसभा के चुनाव के लिए अभी दो साल हैं। लेकिन, पिछले चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में हुए नुकसान का खामियाजा भाजपा को अपनी पंद्रह साल पुरानी सरकार को गंवाकर भुगतना पड़ता है। अगले चुनाव में सत्ता गंवाने का खतरा उठाने की स्थिति में पार्टी नहीं है। राज्य में विधानसभा के चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2023 में हैं। इससे पहले पार्टी को स्थानीय निकाय के चुनाव में भी जाना है। एक लोकसभा और एक विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे भी पूरी तरह से आदिवासी वोटों पर निर्भर हैं। कांग्रेस ने 6 अगस्त को बड़वानी में अधिकार यात्रा कर अपनी ताकत का अहसास करा दिया है। भाजपा यह मानकर चल रही है कि जयस आदिवासी संगठन की देर-सबेर कांग्रेस से दूरी बनेगी। संगठन के 5 लाख से अधिक युवा सदस्य हैं। इनका असर पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी है। गत दिनों संगठन ने एक बड़ा प्रदर्शन आदिवासी अत्याचार के खिलाफ किया था। कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने इसका नेतृत्व किया था। अलावा कांग्रेस पर यह दबाव बनाए हुए हैं कि खंडवा लोकसभा सीट पर उसके युवा कार्यकर्ता को टिकट दी जाए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस में फूट भी पड़ सकती है।

गृहमंत्री अमित शाह का 18 सितंबर में जबलपुर दौरा है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में कार्यक्रम है। गृहमंत्री जनजातीय गौरव समारोह में जननायक शंकर शाह और रघुनाथ की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। भाजपा ने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह की रखी है जिसमें गोंड आदिवासियों को जोड़ा जा सके। शंकर शाह और रघुनाथ के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाई

जाएगी। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। महाकौशल अंचल में एक मात्र आदिवासी लोकसभा सीट मंडला की है। शहडोल लोकसभा सीट में विंध्य का भी कुछ हिस्सा आता है। लेकिन गोंड आदिवासी सामान्य सीटों पर निर्णायक हैं। चाहे वह जबलपुर की सीट हो या कोई दूसरी। छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा आदिवासी हैं। इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट पर ही सफलता मिली थी। भाजपा ने सामान्य वर्ग की इस सीट पर आदिवासी चेहरे को उम्मीदवार बनाया था जिसके चलते पार्टी जीत के काफी नजदीक पहुंच भी गई थी। कांग्रेस आदिवासियों पर होने वाली घटनाओं को लगातार तूल दे रहा है। नीमच में एक आदिवासी युवक को कार से बांधकर घसीटने की घटना ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया।

भाजपा को महाकौशल से ज्यादा चिंता मालवा-निमाड़ की होती है। मालवा निमाड़ के इलाके में आदिवासी समुदाय को हिंदुत्व की धारा से जोड़ने का प्रयास राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके अनुष्ठांगिक संगठन कई दशकों से कर रहे हैं। आदिवासियों को वनवासी नाम का संबोधन उन्हें भगवान श्रीराम से जोड़ने के उद्देश्य से दिया गया। धार-झाबुआ के घने आदिवासी इलाकों में हनुमान चालीसा बांटने और पाठ करने के कई कार्यक्रम चले। इस बार की जनगणना में संघ की पूरी कोशिश है कि आदिवासी धर्म के कॉलम में अपने आपको हिंदू अंकित कराएं। लेकिन, आदिवासी आरक्षण खत्म होने के डर से अपने को हिंदू नहीं कहते हैं।

● लोकेंद्र शर्मा

मग्न में इन दिनों भाजपा के रंग-रंग पूरी तरह चुनावी नजर आ रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपनी टीम के साथ चुनावी मोड में आ गए हैं। सरकार और संगठन एक तीर से तीन निशाने लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यानी 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ ही भाजपा ने 2023 में होने वाले विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है।

निर्वाचन आयोग ने संकेत दे दिया है कि त्र्यौहारी सीजन के बाद प्रदेश में एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस ने मैदानी मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा इन उपचुनावों

को सत्ता का सेमीफाइनल मानकर तैयारी कर रही है। इसलिए पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में है और ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिससे उपचुनाव की 4, विधानसभा की 200 और

लोकसभा की सभी 29 सीटों को जीता जा सके। भाजपा की एक तीर से तीन निशाने वाली रणनीति को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने तैयार किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा अब इस कोशिश में लगी हुई है कि प्रदेश में फिरसे ऐसी स्थिति निर्मित न हो। इसलिए भाजपा के रणनीतिकारों ने अभी से चुनावी मैदान संभालने का खाका तैयार किया है। अब इसी रणनीति पर पार्टी का हर नेता 2024 तक जनता के बीच सक्रिय रहेगा।

प्रदेश में भले अभी चुनाव न हों, चार सीटों के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान न हुआ हो, लेकिन चुनावी मुद्दों की गर्माहट अभी से महसूस होने लगी है। 2003 के विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों के सहारे भाजपा कांग्रेस को घेरकर सत्ता तक पहुंची थी, अब उन्हीं मुद्दों के सहारे कांग्रेस ने भाजपा की घेराबंदी शुरू कर दी है। प्रदेश में हुई बारिश के बाद खस्ताहाल सड़कें एक बार फिर मुद्दा बन गई हैं। इनके अलावा ग्वालियर-चंबल में बाढ़ और बारिश से पुल, पुलियों के बह जाने, बिजली के भारी भरकम बिल और बढ़ती महंगाई को कांग्रेस ने जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है। विपक्ष के तेवरों को लेकर भाजपा ने भी जवाबी हमलों की तैयारी तेज कर दी है। भाजपा ने लोगों से जुड़ने के लिए पूरे एक साल के कार्यक्रमों की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के 2003 से पहले के शासन में बिजली और सड़क के हालातों और अब के हालातों के तुलनात्मक आंकड़े भी पेश किए जा

चुनावी मोड में सत्ता-संगठन



सत्ता-संगठन का समन्वय

2018 और फिर दमोह चुनाव से सबक लेकर सत्ता-संगठन ने इस बार समन्वय की राह को मजबूती से पकड़ा है। हर सरकारी योजना में भाजपा के कार्यकर्ताओं की शिरकत को तय किया जा रहा है। मकसद ये कि जो भी व्यक्ति सरकारी योजना का हितग्राही है, वह भाजपा का वोटर भी बन जाए। अभी तक कभी इस लाइन पर कोई पार्टी नहीं चली, लेकिन अब भाजपा ने इसे ही लक्ष्य बनाकर काम शुरू किया है। इस कारण मुफ्त राशन से लेकर हर सरकारी जनहितैषी योजना के हितग्राहियों को पार्टी कार्यकर्ता भी एप्रोच कर रहे हैं। किसी न किसी तरह हितग्राही से संवाद व संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसका असर 2023 के चुनाव में दिखेगा। गौरतलब है कि भाजपा को कैडर बेस पार्टी माना जाता है। इस कारण पार्टी निरंतर कार्यक्रमों के माध्यम से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखती है। इस बार पार्टी ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ मैदान में सक्रिय कर रही है।

रहे हैं। प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि खराब सड़कों को तत्काल सुधारा जा रहा है। बिजली के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि कांग्रेस 18 साल में बूढ़ी हो गई है और अब उसे मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस सरकार की तुलना में आज प्रदेश के स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे और एमडीआर रोड बेहतर हालत में हैं। परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों के खराब होने पर उनके सुधारने का प्रावधान है।

2018 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा ने सबक लिया है कि वह हमेशा चुनावी मोड में रहेगी। चुनाव छोटा हो या बड़ा पार्टी उसे युद्ध की तरह लड़ेगी। इसलिए वर्तमान समय में मग्न की शिवराज सरकार के साथ ही संगठन और संघ भी मोर्चे पर सक्रिय हैं। सत्ता और संगठन ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और नेताओं को उपचुनाव की जिम्मेदारी देकर काम पर लगा दिया है। वहीं आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है, वहीं संगठन ने सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। उधर, संघ के स्वयंसेवक क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।

भाजपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी

आलाकमान ने शिवराज सरकार, प्रदेश भाजपा संगठन और संघ को उपचुनाव की चारों सीटों को जीतने के साथ ही 2023 में विधानसभा की 230 में से 200 और लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा रणनीति बनाकर मैदानी मोर्चा संभालने जा रही है। यही कारण है कि पिछले दिनों प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जिलों के साथ ही मोर्चा प्रकोष्ठों का गठन कर जल्द से जल्द मैदानी मोर्चा संभालने का निर्देश दिया है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में कांग्रेस कभी-कभार नजर आ रही है। वहीं भाजपा पूरी तरह सक्रिय है। वहीं मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संघ निरंतर फीडबैक ले रहा है। यानी इस बार पार्टी पूरी शिद्दत के साथ मैदानी मोर्चे पर है।

तीन विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव की दहलीज पर खड़े प्रदेश में भाजपा में सत्ता और संगठन को 2023 और 2024 पर चिंता और चिंतन ज्यादा है। भाजपा अभी भले ही सत्ता में हो, लेकिन सच ये है कि 2018 का चुनाव भाजपा हार गई थी। भाजपा में सत्ता और संगठन इस सच को पूरी तरह समझ रहा है, इस कारण उपचुनाव के साथ मुख्य चुनाव की तैयारी के लिए अभी से ताकत झोंकना शुरू हो गया है। शीर्ष नेतृत्व से भी लाइन साफ है कि चिंता-चिंतन के साथ बूथ स्तर तक नेटवर्क मजबूत किया जाए। यही कारण है कि पहली बार भाजपा के मंडल और बूथ स्तर तक के कार्यक्रमों में दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। वह भी एक-दो बार नहीं, बल्कि बार-बार। बूथ स्तर तक के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और दूसरे दिग्गज नेता लगातार पहुंचे हैं। मंडल की बैठकों से लेकर हर कार्यक्रम को **विकेंद्रीकृत** कर दिया गया है। चाहे अन्न उत्सव हो या फिर कुशाभाऊ ठाकरे जयंती हर कार्यक्रम को जिले से लेकर बूथ और मुख्यालय तक एक साथ आयोजित और संचालित किया जा रहा है। मकसद यही है कि मुख्यालय से लेकर बूथ तक वाइब्रेशन बना रहे। कार्यकर्ता चुनावी मोड में रहें और नेटवर्किंग बढ़ती जाए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की नई रणनीति के



तहत अब मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को भी हर मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। उपचुनावों के जरिए मिशन-23 की तैयारी में अपने सारे कोने कसते हुए अब मोर्चा-प्रकोष्ठों को भी मैदान में उतरने को कहा है। वर्ष 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रदेश व देश के लिए निर्णायक बताते हुए संगठन और सरकार ने सभी मोर्चों को एकजुट होकर काम करने की नसीहत दी है। दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों का महत्व समझाते हुए सत्ता और संगठन ने सभी मोर्चा-पदाधिकारियों से कहा कि बिना किसी संकोच के सभी मोर्चा-प्रकोष्ठ सरकार की योजनाओं और कामों के प्रचार-प्रसार में जुट जाएं। सरकार के काम नीचे तक पहुंचाने का काम संगठन का है। प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उसका भ्रमजाल तोड़ने का काम हमारे मोर्चा-प्रकोष्ठ मिलकर करें। मोर्चे का हर पदाधिकारी पार्टी का प्रवक्ता है, उसे संगठन की लाइन और सरकार के काम याद रहना चाहिए। मोर्चा पदाधिकारियों की बातों में हमेशा संगठन की लाइन और सरकार की योजनाएं जनता के बीच पहुंचना चाहिए।

मप्र की 230 विधानसभा सीटों के जातिगत आंकड़ों के आधार पर भाजपा रणनीति बनाकर

मोर्चा संभालने जा रही है। इसलिए भाजपा जातियों और समाज को जोड़ने का अभियान भी शुरू करेगी। इसकी शुरुआत 18 सितंबर को जबलपुर से होगी, जहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अमर शहीद राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बहाने भाजपा की कोशिश आदिवासी **वोटों को लुभाने** की है। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह में आदिवासी सम्मेलन का आयोजन करा चुके हैं। तब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। यह पूरी कवायद आदिवासी वोटों को अपने पक्ष में लाने की हो रही है। कांग्रेस जहां जयस की मदद से विधानसभा 2018 में भाजपा को नुकसान पहुंचा चुकी है। वहीं भाजपा की कोशिश 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोटों को साधने की है। विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश को लेकर पहले ही भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ चुके हैं। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 6 सितंबर को बड़वानी से आदिवासी अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। इसी का जवाब भाजपा 18 सितंबर को जनजातीय समाज को जोड़ीं अभियान से देने जा रही है।

● कुमार राजेन्द्र

ओबीसी-आदिवासी वोट बैंक पर फोकस

यूं तो चुनावों में हर बार जातिगत कार्ड अहम रहता है, लेकिन इस बार ओबीसी की आंच और अजा-जजा वर्ग पर कांग्रेस के दांव-पेंच के कारण भाजपा में सत्ता-संगठन के लिए यह ज्यादा अहम हो गया है। ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण की बात हो या फिर सवर्ण को 10 फीसदी आर्थिक आरक्षण का मुद्दा हो, कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए इन पर कदम उठाए। कांग्रेस गई, तो भाजपा सरकार ने इन मुद्दों की अहमियत समझी। अब 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट के स्टे के बीच भाजपा-कांग्रेस में खींचतान है। दूसरी ओर सवर्ण आरक्षण का मुद्दा थमा है, लेकिन अजा व जजा वर्ग के लिए हितकारी योजनाओं से लेकर कदमों को लेकर भी भाजपा-कांग्रेस के बीच जंग के हालात हैं। दोनों दल इस पर आमने-सामने हैं। कांग्रेस अपने 15 महीने के शासन में इन वर्गों को लेकर उठाए कदमों को बताती है, तो भाजपा अपने कामों को गिना रही है। प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 82 सीटें अजा व जजा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इनमें 35 सीट अजा और 47 सीट अजजा वर्ग के लिए हैं। जबकि 31 अन्य सीट पर आदिवासी वोटर किसी की भी जीत-हार में अहम भूमिका निभाते हैं।

मप्र में कमलनाथ सत्ता वापसी के लिए एक बार फिर 'एकला चलो' की राह छोड़ संगठन के भरोसे दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय राजधानी भोपाल से लेकर प्रदेशभर में कांग्रेस ने

कांग्रेस का लक्ष्य 2023

आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। महंगाई, सड़क, बिजली, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। वहीं भाजपा की तरह कांग्रेस भी जातिगत फॉर्मूले की रणनीति बनाकर काम कर रही है। आंकड़ों के जाल से ऐसे फॉर्मूले तलाश किए जा रहे हैं, जो सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा दिला सकें। मप्र में पिछले तीन दशक के आंकड़े बताते हैं कि आदिवासी वर्ग ने जिधर करवट ली है, उधर का पलड़ा भारी रहा है। बीते दिनों विधानसभा सत्र के दौरान आदिवासी मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधने से लेकर कमलनाथ की आदिवासी अधिकार यात्रा तक इसी कवायद का हिस्सा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस मप्र में आदिवासी मुद्दों को लेकर सरकार पर आक्रामक हो सकती है।

दरअसल, 2011 की जनगणना बताती है कि आदिवासी वर्ग की आबादी करीब 23 प्रतिशत है। आदिवासी के तहत प्रदेश में 23 जनजातियां निवास करती हैं। इसमें सबसे ज्यादा भिलाला 60 लाख, गोंड 51 लाख, कोल 6.5 लाख, कोरकू 6.5 लाख, सहरिया 6 लाख हैं। प्रदेश में आदिवासी वर्ग की आबादी लगभग 1.75 करोड़ अनुमानित है। प्रदेश में आदिवासी प्रभाव वाली 47 विधानसभा सीटें हैं। सामान्य की सीटें ऐसी भी हैं, जहां आदिवासी मतदाता निर्णायक की भूमिका में है। 2018 विस चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन की वजह आदिवासी सीटों के परिणाम में बढ़ा बदलाव था। भाजपा 32 से घटकर 16 पर आ गई थी, वहीं कांग्रेस 14 से सीधे 29 तक पहुंच गई थी।

1990 में आदिवासी सीटों पर भाजपा की जीत ने भाजपा की सुंदरलाल पटवा सरकार के लिए रास्ता बनाया था, लेकिन आदिवासी वर्ग 1993 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ लौट आया, जिसके चलते कांग्रेस को फिर सत्ता मिल गई। करीब 10 साल तक यह वर्ग कांग्रेस के साथ रहा। 1998 में भी कांग्रेस की सरकार बरकरार रही, लेकिन 2003 के चुनाव में आदिवासी वर्ग फिर से भाजपा की तरफ मुड़ गया। नतीजा कांग्रेस की सत्ता से विदाई के रूप में सामने आया। इसके बाद से आदिवासी वर्ग कुछ आंकड़ों में हेरफेर के साथ 2008 और 2013 में भाजपा के साथ ही रहा, लेकिन 2018 में आदिवासी प्रभाव वाली सीटों की संख्या आधी होते ही भाजपा के हाथ से सत्ता एक बार फिर चली गई और इसका फायदा मिला कांग्रेस



जातिगत कार्ड पर इस बार ज्यादा जोर

विधानसभा चुनाव 2023 अभी दूर है, लेकिन सियासी तैयारी शुरू हो गई है। तीन विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव की दहलीज पर खड़े प्रदेश में भाजपा में सत्ता और संगठन को 2023 पर चिंता और चिंतन ज्यादा है। भाजपा अभी भले ही सत्ता में हो, लेकिन सच ये है कि 2018 का चुनाव भाजपा हार गई थी। भाजपा में सत्ता और संगठन इस सच को पूरी तरह समझ रहा है, इस कारण उपचुनाव के साथ मुख्य चुनाव की तैयारी के लिए अभी से ताकत झाँकना शुरू हो गया है। शीर्ष नेतृत्व से भी लाइन साफ है कि चिंता-चिंतन के साथ बूथ स्तर तक नेटवर्क मजबूत किया जाए। प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 82 सीटें अजा व अजजा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इनमें 35 सीटें अजा और 47 सीटें अजजा वर्ग के लिए हैं। वहीं 52 फीसदी ओबीसी आबादी अलग महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसलिए इन तीनों ही वर्गों की धुरी पर चुनावी सियासत चल रही है। आगामी उपचुनावों से लेकर मुख्य चुनाव तक यह तीनों वर्ग अहम रहना है।

को। कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2020 मार्च में ज्योतिदित्य सिंधिया के कांग्रेस से अलग होती ही सत्ता परिवर्तन हुआ और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने।

हालांकि कांग्रेस की एक मुश्किल है, जो उसे आदिवासी वर्ग की तरफ मुड़ने में खासी परेशानी बन सकती है। कांग्रेस तीन दशक में किसी आदिवासी नेता को पार्टी का चेहरा बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। दलबीर सिंह, दिलीप सिंह भूरिया, शिवभानु सिंह सोलंकी और जमुना देवी जैसे नेताओं को कांग्रेस ने कभी कमान नहीं सौंपी। इनके न होने पर किसी आदिवासी नेता का कद भी गुटबाजी के चलते नहीं बढ़ सका है। दिलीप सिंह भूरिया ने

आदिवासी नेतृत्व को मौका देने की आवाज बुलंद की थी, तो उन्हें पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था।

कमलनाथ बतौर मुख्यमंत्री डेढ़ साल तक सत्ता में रहते हुए भी आदिवासी वर्ग के लिए कुछ विशेष नहीं कर सके। कमलनाथ ने नीमच में आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली, वहीं भोपाल के मानस भवन में इस यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया। अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कमलनाथ आगे बढ़ रहे हैं वहीं उनकी नजर कुछ दिनों बाद कुछ महीनों बाद होने वाले उपचुनाव की सीटों पर भी है जिनमें अधिकतर आदिवासी प्रभाव वाली सीटें हैं।

आदिवासी चेहरे के मामले में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में भी कमजोर स्थिति थी। उमंग सिंघार और हनी सिंह बघेल को कैबिनेट में लिया गया, लेकिन उनका सियासी कद प्रदेश स्तर का न होने से इस वर्ग को कांग्रेस प्रभावित नहीं कर सकी। हालांकि अब कमलनाथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं की याद दिला रहे हैं। वे **खुली चुनौती** दे रहे हैं कि भाजपा के पास राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई आदिवासी चेहरा हो तो बताए ?

कमलनाथ जानते हैं कि 2018 के विस चुनाव में आदिवासी वर्ग ने भाजपा से मुंह मोड़ लिया था, जिसके चलते उसके हाथ से सत्ता फिसल गई थी। कांग्रेस दावा करती है कि किसी भी आदिवासी से सियासी शक्तिशयत का नाम पूछें, तो जिसे राजनीति में जरा भी रुचि नहीं होगी, वह भी इंदिरा गांधी का नाम जरूर लेता है। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी वर्ग के गौरवशाली योगदान की याद ही कमलनाथ इस सवाल को उछालने के लिए दिलाते हैं कि भाजपा के पास कितने नाम हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी हो। ये सवाल आदिवासी और कांग्रेस के वर्षों पुराने संबंधों को याद दिलाने की कोशिश है।

● अरविंद नारद

मप्र में इन दिनों ओबीसी आरक्षण सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रदेश की 50 फीसदी आबादी को खुश करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां कोशिश में जुटी हुई हैं। इसी कोशिश में भाजपा ने मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर मामले को गर्मा दिया है क्योंकि पहले से ही एक आयोग बना हुआ है। जिस पर कांग्रेस का कब्जा है।

ओबीसी आरक्षण पर चल रही राजनीति के बीच अब मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाने को लेकर घमासान शुरू हो गया है। शिवराज सरकार ने मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को बना दिया, इसके

बाद कांग्रेस ने कहा है कि शिवराज सरकार जनता को गुमराह कर रही है। इसके अध्यक्ष तो पहले से जेपी धनोपिया हैं, फिर

शिवराज सरकार नया आयोग कैसे बना सकती है। हम कोर्ट में जाएंगे। वहीं सूत्रों का कहना है कि नया पिछड़ा वर्ग आयोग पुराने से अलग होगा। नया आयोग ओबीसी की योजनाओं की मॉनीटरिंग करेगा साथ ही ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने और जातियों को जोड़ने के लिए अभियान चलाएगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में इसका ऐलान किया था। अब सरकार ने मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक गौरीशंकर बिसेन को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। गौरीशंकर बिसेन बालाघाट से विधायक हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाते हैं। सरकार अब इस आयोग के माध्यम से प्रदेश की आधी आबादी यानी 50 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए काम करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार कहते हैं कि मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग दोनों अलग-अलग हैं। हमारे लिए दोनों बराबर और सम्मानीय हैं। मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।

प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण को लेकर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है, इसके बावजूद भी घमासान मचा हुआ है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। सरकार ने दो दिन पहले राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष भाजपा विधायक गौरीशंकर बिसेन को नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें मंत्री का दर्जा भी दे दिया है। इस बीच मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने इस नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मप्र सरकार ने भी पिछड़ा वर्ग के दो आयोगों को लेकर स्थिति साफ की है कि मप्र

आयोग को लेकर रार



एक आयोग दो अध्यक्ष

सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण देकर भाजपा ने मारी बाजी

प्रदेश में ओबीसी पर हो रही राजनीति में फिलहाल भाजपा ने बाजी मार ली है। शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी कर दिया है। बता दें कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने राज्य में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का ऐलान किया था। जिसके बाद सरकार ने अध्यादेश लाकर मार्च 2019 में बढ़ा हुआ आरक्षण लागू भी कर दिया। हालांकि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने याचिकाएं दाखिल हुईं और कोर्ट ने बड़े हुए आरक्षण के फैसले को स्टे कर दिया। अब राज्य सरकार ने कानून के जानकारों से राय ली। जिसमें यह बात सामने आई कि मप्र में पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने को लेकर कोई रोक नहीं है, सिर्फ जो 6 याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं उन्हीं पर 14 फीसदी आरक्षण रखने का अंतरिम आदेश दिया गया है। इसलिए प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का कानून लागू है और सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में इस आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। जिसके बाद सरकार ने आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया है।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अलग-अलग हैं।

भाजपा नेताओं का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने जाते-जाते अपनों को उपकृत करने के लिए आयोगों में नियुक्ति दे दी थी। लेकिन मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सहित सभी आयोगों की गतिविधियां पिछले डेढ़ साल से ठप हैं। ऐसे में सरकार ने ओबीसी का फायदा पहुंचाने के लिए मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है। इस आयोग के गठन से ये फायदा होगा कि आयोग पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को जोड़ने की अनुशंसा कर सकेगा। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं की मॉनीटरिंग कर सकेगा। क्रीमीलेयर की सीमा के संबंध में अनुशंसा कर सकेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण को लेकर सलाह देगा और एक तरह से यह आयोग पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए काम करेगा।

पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन पर

कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो कांग्रेस अड़ंगा लगाती है। खुद कांग्रेस ने कभी किसी वर्ग का कल्याण नहीं किया। हमने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए आयोग का गठन किया तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मप्र सरकार की अक्ल पर तरस आ रहा है। हमारे लीडर कमलनाथ ने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के दौरान जेपी धनोपिया को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया था। दुर्भाग्यवश कांग्रेस की सरकार चली गई और शिवराज सिंह ने बदले की भावना से उन्हें अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया। इस निर्णय के खिलाफ हम हाईकोर्ट गए, जहां से स्टे मिल गया। लिहाजा, स्टे के अनुसार हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया ने निर्णय का पालन किया। सरकार ने उस निर्णय की अवमानना की।

● जितेंद्र तिवारी

मप्र में पिछले डेढ़ दशक में रिकार्ड विकास हुआ है। लेकिन विकास के इस दौर में कई योजनाएं-परियोजनाएं ऐसी भी रही हैं, जो सफेद हाथी बनकर रह गई हैं। ऐसी योजनाओं-परियोजनाओं में सबसे अधिक जल संरचनाएं हैं। बिना प्लान के

बनी अधिकांश जल संरचनाएं बेकार पड़ी हुई हैं। अधिकांश तो अतिक्रमण की चपेट में आ गई हैं। गौरतलब है कि सरकारी आंकड़ों में

प्रदेश के सभी जिलों में तालाब, चेकडैम और स्टाप डैम का जाल बिछा हुआ है। इसके बावजूद प्रदेश में सिंचाई और पेयजल की समस्या बनी रहती है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश की अधिकांश जल संरचनाएं बिना प्लान के बनी हुई हैं। यही नहीं इन जल संरचनाओं के मेंटेनेंस के नाम पर हर साल 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसका खुलासा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव के एक पत्र से हुआ है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने 11 अगस्त को जारी पत्र में कहा है कि जल संग्रहण संरचना की मूल डिजाइन और मूल परिणामों का ठीक से विश्लेषण नहीं किया गया। तालाब स्टाप डैम और चेक डैम के जीर्णोद्धार नवीनीकरण के मामले में ना प्लानिंग दिख रही है और ना ही तकनीकी इनपुट है। मॉनीटरिंग सिस्टम भी कमजोर रहा। इससे जल संरचनाओं में अनियमितताएं होना दिख रही हैं। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत से कहा है कि पूर्व में स्थित तालाबों और विभिन्न योजनाओं में दशकों पहले बनाए गए तालाब स्टाप डैम और चेक डैम बिना प्लान के हैं, इसलिए यह रचनाएं परिणाममूलक नहीं बनी। उल्लेखनीय है कि जल संरचनाओं के नाम पर प्रदेशभर में हर साल औसतन 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।

उमराव ने पत्र में विभाग की भरशाही के साथ ही जल संरचनाओं के उद्देश्य पर सवाल उठाया है। पत्र में कहा गया है कि जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण के बाद भी मत्स्य, सिंचाई उत्पादन और सिंचाई क्षमता से ग्रामीण समुदाय और ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के ठोस प्रयास नहीं हुए। इस रणनीति के तहत कार्य करने पर दशकों बाद विभाग में एक बार फिर प्रभावी रणनीति बनाने की जरूरत समझी गई है। वित्तीय प्रबंधन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 15वें वित्त आयोग कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी सांसद विधायक निधि आदि से

कागजों पर 200 करोड़ का मेंटेनेंस



मप्र में सिंचाई और पेयजल के लिए सरकार ने सैकड़ों तालाब, स्टाप डैम और चेक डैम का निर्माण कराया है। हर साल इन पर मरम्मत के नाम पर 200 करोड़ से अधिक खर्च किए जाते हैं। लेकिन विभाग के प्रमुख सचिव ने ही इन जल संरचनाओं पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि ये बिना प्लान के बनाए गए हैं, इसलिए बेकाम के हैं।

जल संचय में पिछड़ा मप्र

जानकारी के अनुसार बारिश के पानी को स्टाप डैम, तालाब जैसी संरचनाएं बनाकर सहेजने के मामले में मप्र पिछले एक दशक में फिसड्डी साबित हुआ है। 2009 से 2015 के बीच वाटरशेड की 517 परियोजनाएं केंद्र ने मप्र के लिए मंजूर की। इन योजनाओं को 2017 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इनमें से सिर्फ 204 ही पूरी हो पाई हैं। बाकी योजनाएं या तो फंड के अभाव में अधूरी पड़ी हैं, या फिर उनकी शुरुआत ही नहीं हो पाई है। जबकि केंद्र सरकार इनके लिए अभी तक 1479 करोड़ रुपए बहा चुकी है। इसका खुलासा केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास के तहत बारिश के पानी को रोकने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। 2017 से इसे मनरेगा में शामिल कर लिया गया। केंद्र सरकार द्वारा भरपूर राशि जारी किए जाने के बाद भी मप्र में पिछले एक दशक में बहुत काम नहीं किया गया।

करना होगा। ग्रामीणों की जन भागीदारी अनिवार्य रहेगी। पहले चरण में बड़े जीर्णोद्धार में 1 साल से अधिक समय लगाने वाले कार्य नहीं लिए जाएं।

सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में अधिकांश

जल संरचनाएं ऐसी हैं जिन पर हर साल जीर्णोद्धार के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि उनका कोई उपयोग नहीं है। दरअसल, कागजी जीर्णोद्धार कर सरकार को चपत लगाई जा रही है। जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण कार्य मनरेगा जैसी योजना में शामिल किया है, फिर भी आवश्यक लेबर उपलब्ध नहीं हुई और ना ही तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए ठोस प्लान बनाया गया। ग्रामीण समुदाय का कोई योगदान नहीं रहा।

सूत्रों के अनुसार वाटरशेड योजनाओं में पहले केंद्र द्वारा 90 फीसदी और राज्यों द्वारा 10 फीसदी राशि मिलाई जाती थी। लेकिन 2016 में केंद्र सरकार ने इसे बदलकर 60-40 का अनुपात कर दिया। केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद राज्यों ने वाटरशेड योजनाओं पर काम करने में तेजी नहीं दिखाई और काम पिछड़ता चला गया। मनरेगा के तहत वर्षा जल संचय के लिए तालाब, स्टाप डैम बनाने के मामले में भी मप्र का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है। 2018-19 में देश में कुल 302478 निर्माण कार्य पूरे किए गए, जिसमें से सिर्फ 6 फीसदी यानी 18823 ही मप्र में बने। यही हाल 2017-18 में रहा, तब देश में कुल 370357 जल संरचनाएं बनीं जिसमें से मप्र में 19644 ही बन पाई जो कि देश की 5.30 प्रतिशत ही थीं। जबकि मप्र की तुलना में राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों ने बेहतर काम किया।

● प्रवीण कुमार

सड़कों को विकास का प्रतीक माना जाता है। लेकिन मद्र के माननीयों पर विकास का भूत कुछ इस कदर सवार हुआ है कि वे बिना सोचे-समझे सड़क निर्माण की घोषणा कर देते हैं। यही नहीं सड़कों के निर्माण के लिए वे सरकार

पर दबाव बनाते हैं। इसका असर यह देखने को मिल रहा है 'माननीयों' की सिफारिश पर 1,200 से अधिक सड़कों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई हैं। इससे लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का पूरा बजट गड़बड़ा गया है। विभाग न तो पूरी सड़कें बना पाया है और अब न तो उसके पास जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने का पैसा है।

पीडब्ल्यूडी विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में पिछले चार साल से सड़कों के निर्माण पर माननीयों का सबसे अधिक जोर रहा है। आज आलम यह है कि विधायकों, नेताओं के दबाव में स्वीकृत हुई सड़कों ने पीडब्ल्यूडी का पूरा गणित गड़बड़ा दिया है। दरअसल, दोनों सरकारों ने पिछले चार साल में तकीबन 1200 से अधिक सड़कों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। बजट

के अभाव में अधिकांश सड़कें बन ही नहीं पाई हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के सूत्रों के अनुसार पिछले चार साल में माननीयों द्वारा घोषित जिन 1200 से अधिक सड़कों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है बजट के अभाव में यह सभी सड़कें नहीं बन पाई हैं। अब इन सड़कों के लिए सरकार को 5 हजार करोड़ से अधिक की जरूरत है, जबकि विभाग को सिर्फ 2700 करोड़ रुपए ही बजट में मिले हैं। ऐसे में विभाग के सामने समस्या यह है कि अब आधे बजट में इन सड़कों का निर्माण कैसे होगा। विभागीय सूत्रों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग को 500 करोड़ रुपए भुगतान करना है। ठेकेदार ने विधानसभा मुख्य और उपचुनाव से पहले सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव का काम कराया था। वहीं पीडब्ल्यूडी के ईएनसी अखिलेश अग्रवाल का कहना है कि जैसे-जैसे बजट मिलता जाएगा, सड़कों का निर्माण होगा। ठेकेदारों का भुगतान भी किया जाएगा।

पर्याप्त बजट नहीं मिलने से विभाग की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। हालत यह है कि बारिश में खराब हुई सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए विभाग के पास पैसा नहीं है। लोक निर्माण विभाग की करीब एक हजार किमी सड़कें बारिश में खराब हुई हैं।

माननीयों की सड़कों ने बिगाड़ा गणित



खराब सड़कों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस सड़क पर

जिस तरह 2003 में भाजपा ने प्रदेश की खराब सड़कों को मुद्दा बनाया था, उसी तरह कांग्रेस ने बारिश से खराब हुई सड़कों को मुद्दा बनाकर सड़क पर सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा शासनकाल में संभवत पहली बार बारिश से जिस तरह सड़कों की हालत खस्ता हुई है ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं रही। प्रदेश में दूरदराज के अंचलों को छोड़िए राजधानी और बड़े शहरों की सड़कें ही चलने लायक नहीं हैं। एक आंकलन के अनुसार राजधानी की 50 फीसदी सड़कें जर्जर हो गई हैं। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद भी सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। भाजपा विधायक अजय विश्णोई जहां तंज कस चुके हैं, कांग्रेस को तो बिन मांगे मुराद मिल गई है वह आक्रामक है। इधर, विपक्ष के तेवरों को लेकर भाजपा ने भी जवाबी हमला तेज कर दिया है। भाजपा ने लोगों से जुड़ने के लिए पूरे एक साल के कार्यक्रमों की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के 2003 से पहले के शासन में बिजली और सड़क के हालातों और अब के हालातों के तुलनात्मक आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी करने में विभाग को बजट का जुगाड़ करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा वाली एक दर्जन सड़कें प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। वित्त विभाग ने खाली खजाने के चलते कई सड़कों को होल्ड पर रखा है। नई सड़कें बनाने पर सरकार ने रोक लगा रखी है। दो साल में सरकार ने सिर्फ 127 करोड़ रुपए की 120 सड़कें बनाने की ही मंजूरी दी है। कांग्रेस के 18 महीने की सरकार में 450 सड़कों की मंजूरी दी गई है।

विधानसभा चुनाव-2018 में शिवराज सरकार ने करीब 500 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी थी। यह सभी सड़कें विधायकों के दबाव में सरकार ने निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इन सड़कों के निर्माण के लिए अब धीरे-धीरे टेंडर जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि अब पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव सिर पर हैं। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के चलते शिवराज सरकार ने 108 सड़कों की घोषणा की थी। इन सभी सड़कों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। अब धीरे-धीरे इन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अभी सिर्फ एक-दो किमी वाली सड़कों के निर्माण के लिए चयन किया गया है।

मद्र में भले अभी चुनाव न हों, 4 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान न हुआ हो, लेकिन चुनावी मुद्दों की गर्माहट अभी से महसूस होने लगी है। 2003 के विधानसभा चुनाव में जिस 'बीएसपी' को मुद्दा बनाकर भाजपा कांग्रेस को घेरकर सत्ता तक पहुंची थी, अब उन्हीं मुद्दों के सहारे कांग्रेस ने भाजपा की घेराबंदी शुरू कर दी है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आक्रामक है और भाजपा के कई विधायकों ने भी सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है। परेशान भाजपा जनता को कांग्रेस के दिग्विजय शासन की याद ताजा करने की कोशिश कर रही है। तर्क दिया जा रहा है कि तब जैसी स्थिति अब नहीं है। गौरतलब है कि 2003 में भाजपा ने 'बीएसपी' यानी बिजली, सड़क और पानी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था। इस साल प्रदेश में हुई बारिश के बाद खस्ताहाल सड़कें एक बार फिर मुद्दा बन गई हैं। इनके अलावा ग्वालियर चंबल में बाढ़ और बारिश से पुल, पुलियों के बह जाने, बिजली के भारी भरकम बिल और बढ़ती महंगाई को कांग्रेस ने जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है।

● राकेश ग़ोवर

निवेशकों की पहली पसंद मप्र



6 कोरोना संक्रमण के 18 माह के दौरान देशभर में विकास का पहिया धम सा गया था, लेकिन इस दौर में भी निवेशकों ने मप्र में जमकर निवेश किया। मप्र औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के पास इस समय लगातार उद्योगपति निवेश की जमीन मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। मप्र के प्रति निवेशकों के आकर्षण को देखते हुए औद्योगिक जगत में मप्र को इन्वैस्टगढ़ कहा जाने लगा है। दरअसल, प्रदेश सरकार की नीतियों और सुविधाओं के कारण निवेशकों का आकर्षण मप्र में बढ़ा है। आज प्रदेश के हर क्षेत्र में देश-विदेश के निवेशक निवेश कर रहे हैं।

को रोगा संक्रमण के दौर में चौथी पारी शुरू करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को भांप लिया था कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश ही मप्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रख सकता है। इसलिए उन्होंने निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछा दी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरी लहर

थमते ही प्रदेश में निवेश करने वालों की कतार लग गई है। पिछले 18 माह में प्रदेश में जहां 16,707 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, वहीं 47,186 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। इस दौरान सरकार ने 879 एकड़ औद्योगिक भूमि भी आवंटित की है।

मप्र हमेशा से निवेशकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमणकाल में देशभर में सबसे अधिक निवेशकों ने मप्र का रुख किया। इस कारण मप्र में औद्योगिक विकास की गति तेजी से बढ़ी है। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशन और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह के मार्गदर्शन में उद्योग विभाग के अधिकारी प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला के नेतृत्व में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए नीति पर निरंतर काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि कोरोना संक्रमणकाल में मप्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है।

अगर प्रदेश में औद्योगिक निवेश का आंकलन करें तो पिछले 3 सालों में इस वर्ष प्रदेश में अधिक निवेश हुआ है। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019-20 में 258 निवेशकों ने 6600 करोड़ रुपए का निवेश किया था, वहीं उस साल 630 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। वर्ष 2020-21 में 384 निवेशकों ने 11 हजार करोड़ रुपए का

निवेश किया था और निवेशकों को 840 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। जबकि वर्ष 2021-22 में 31 अगस्त तक 495 निवेशकों ने 5707 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस साल अभी तक 832 एकड़ जमीन निवेशकों को आवंटित की गई है।

उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला का कहना है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता प्रदेश में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करना भी है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमणकाल के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए विभाग ने औद्योगिक इकाइयों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। विभागीय सूत्रों से मिले आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में जहां वर्ष 2019-20 में 15,850 लोगों को औद्योगिक इकाइयों में रोजगार मिला है, वहीं 2020-21 में

वित्त विभाग ने रोकी उद्योग की चाल

मप्र में कोरोना संक्रमण के बावजूद प्रदेश में औद्योगिक निवेश की रफ्तार तेज है। यह रफ्तार और तेज होती अगर वित्त विभाग में उद्योग विभाग की फाइलें न रुकतीं। सूत्रों का कहना है कि उद्योग विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव वित्त विभाग में 2-3 माह तक लटके रहते हैं। इससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रभावित हो रहा है। बताया जाता है कि विगत दिनों वित्त विभाग के प्रमुख सचिव ने विभाग के दो आईएस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। गौरतलब है कि सरकार ने विभाग में प्रमुख सचिव के अलावा दो और आईएस अधिकारी पदस्थ कर रखे हैं ताकि विभाग की गति तेज रहे, लेकिन अधिकारी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि वित्त विभाग में अनुशंसा के लिए आने वाली फाइलें लटकी रहती हैं। वहीं विभाग के मंत्री भी कुछ ऐसी ही स्थिति में नजर आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जिस फाइल पर चढ़ावा नहीं मिलता है, मंत्रीजी उस फाइल को रोके रहते हैं। ऐसे में प्रदेश में विकास की गति अवरुद्ध हो रही है। उधर, मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को समन्वय के साथ विकास में काम करने का निर्देश दे रखा है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है।

22,000 और 2021-22 में अब तक 25,186 लोगों को रोजगार मिल चुका है।

कोरोनाकाल में जहां लोगों का रोजगार छिना, आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई वहीं अब सुखद यह है कि धीरे-धीरे सब कुछ पटरी पर लौटने लगा है। लोगों को रोजगार मिलने के साथ निवेशकों ने मप्र की ओर रुख किया है। पिछले 15 दिन में प्रदेश को 18 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री से अलग-अलग मुलाकात में यह प्रस्ताव दिए हैं। कोई यहां नए उद्योग लगाना चाहता है तो कोई यहां स्थापित अपनी इकाइयों का विस्तार चाहता है। इनमें टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रस्ताव प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री से अर्न इंडिया मेन्युफैक्चरिंग, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अविगना प्राइवेट लिमिटेड, सागर ग्रुप और विहान इंटरप्राइजेज के पदाधिकारी निवेश प्रस्ताव के साथ मिले। निवेशकों को आश्चर्य कि उन्हें सरकार की ओर से भूमि सहित अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उद्योग नीति के अंतर्गत दी जाने वाली रियायतों के वे हकदार होंगे। उद्योगपतियों और निवेशकों से मिले इन प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार अर्न इंडिया मेन्युफैक्चरिंग ने एलडी लाइट्स और स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स की 200 करोड़ रुपए लागत की इकाई स्थापित करने को तैयार है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा होशंगाबाद में 400 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय से कैसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना में सहयोग का प्रस्ताव मिला है। विहान इंटरप्राइजेज का 185 करोड़ रुपए के निवेश से प्रसंस्करण इकाइयों और संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव। यह उद्योग सीहोर जिले में बुधनी के निकट ग्राम बासापुर-जर्गपुर में लगाना प्रस्तावित है। अविगना प्राइवेट लिमिटेड का कृषि और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया है। सागर ग्रुप का 1000 करोड़ रुपए से भोपाल में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल प्रारंभ करने की कार्ययोजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव मिला है।

कोरोना संक्रमणकाल, लॉकडाउन की मुश्किलों से उद्योग अब उबरने लगे हैं। मप्र औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के पास इस समय लगातार उद्योगपति निवेश की जमीन मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। इंदौर-उज्जैन रीजन इन दिनों निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। आत्मनिर्भर देश और प्रदेश की दिशा में बन रहे माहौल को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी कमर कसते हुए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के आसपास इंदौर व उज्जैन संभाग में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का रोडमैप तैयार किया है। निगम इस रीजन में दो बड़े और



एथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता योजना

प्रदेश सरकार ने एथेनॉल एवं जैव ईंधन के उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता योजना जारी किए जाने का निर्णय लिया है। उत्पादन से जुड़े प्लांट एवं मशीनरी में किए गए पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक, पेट्रोलियम तेल उत्पादन कंपनियों को इकाई द्वारा उत्पादित एथेनॉल प्रदाय करने पर 1.50 रुपए प्रति लीटर की वित्तीय सहायता वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक से 7 वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी। इकाइयों के लिए भूमि क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 साल के लिए विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। गुणवत्ता प्रमाणन प्रतिपूर्ति गुणवत्ता प्रमाणन लागत का 50 प्रतिशत या 1 लाख रुपए जो भी कम हो, दी जाएगी। 100 प्रतिशत पेटेंट शुल्क की प्रतिपूर्ति 5 लाख रुपए तक की सीमा तक की जाएगी। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सुविधा के लिए इक्विपमेंट पर 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान, जो 1 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा तक होगा, प्रदान किया जाएगा। उद्योग के लिए निजी/आवटित अविकसित शासकीय भूमि पर पानी, बिजली, सड़क अधोसंरचना विकास के लिए परियोजना पर हुए व्यय के 50 प्रतिशत, जो प्रत्येक मद के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए की सीमा तक होगा, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए एमपीआईडीसी, भोपाल नोडल एजेंसी होगी।

दो छोटे औद्योगिक क्षेत्र तैयार कर रहा है। जानकारी के अनुसार बड़ा निवेश क्षेत्र रतलाम के समीप तैयार हो रहा है। यहां 2 हजार एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क और 3 हजार एकड़ में मल्टी प्रॉडक्ट औद्योगिक क्षेत्र व 1 हजार एकड़ में मंदसौर, नीमच में मल्टी प्रॉडक्ट व टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं। इस तरह 6 हजार एकड़ के नए औद्योगिक क्षेत्र की योजना बन चुकी है।

एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक रोहन सक्सेना ने बताया, तीनों जिलों में विभाग के आला अफसरों ने जमीन तय कर दी है। नीमच में तो भीलवाड़ा की चार टेक्सटाइल कंपनियां शिफ्ट हो रही हैं। इनके लिए स्थानीय प्रशासन ने जमीनें चिन्हित कर उद्योग विभाग को हस्तांतरित कर दी है। वर्तमान में औद्योगिक निवेश का बहुत अच्छा वातावरण बना है। मांग के अनुरूप तैयार जमीनों के लिए निवेशकों को इंतजार करना पड़ रहा है। मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में से अधिकांश में बुकिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा बेटमा के समीप पीथमपुर-7 में करीब 3500 एकड़ में औद्योगिक टाउनशिप व उज्जैन में भी लघु-सूक्ष्म उद्योग का खाका तैयार होकर काम भी शुरू हो

चुका है। इस तरह एक्सप्रेस-वे के आसपास 10 हजार एकड़ से ज्यादा के औद्योगिक क्षेत्र तैयार हो रहे हैं। इनमें अगले तीन सालों में 70 हजार से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की योजना तैयार की गई है। इसका निर्माण शुरू हो गया है। इससे दिल्ली-मुंबई के बीच की दूरी को कम कर 12 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह एक्सप्रेस-वे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मप्र, गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों से गुजरेगा। मप्र में यह पश्चिम में रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ व आलीराजपुर जिलों से गुजरेगा। सरकार ने इसके लिए मुख्य क्रॉसिंग मंदसौर जिले के गरोठ के समीप दिया है। यहां से दोनों ओर जाने में 6-6 घंटे का समय लगेगा। सरकार ने इसका फायदा लेने और स्थानीय संसाधनों आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए यह योजना तैयार की है। इसका लाभ इंदौर व धार के समीप विकसित हो रही बेटमा औद्योगिक टाउनशिप को भी मिलेगा। यह रीजन सेंटर में होने से यहां लॉजिस्टिक हब में अच्छी संभावना भी है।

● सुनील सिंह

लो कतंत्र के लिहाज से भारत दुनिया के लिए एक मिसाल की तरह है। बड़ी आबादी के साथ अपने देश में क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी हैं। राज्यों में सक्रिय राजनीतिक दल इन्हीं आकांक्षाओं के आधार पर अपनी सियासत करते हैं। वे अपने राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के मनमाने इस्तेमाल को अपना अधिकार समझते हैं। विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त की। दरअसल, छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह के खिलाफ राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने राज्यों में पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के अपने फायदे के लिए दुरुपयोग के सच को नए सिरे से सामने ला दिया है। अपने खिलाफ दर्ज मामलों में गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट गए। उन्हें राहत मिली भी, लेकिन इस प्रकरण ने शासन-प्रशासन के कामकाज को लेकर अनेक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

राजनेताओं के पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के साथ गठजोड़ की समस्या नई नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह समस्या दूर होने के बजाय और अधिक गंभीर होती जा रही है। राज्य सरकारें पुलिस और प्रशासनिक अफसरों का अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के मामले में एक-दूसरे से होड़ करती नजर आती हैं। गुरजिंदर पाल सिंह छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार में शक्तिशाली पुलिस अफसर माने जाते थे। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद वह नई सरकार के निशाने पर आ गए। उन पर आरोप है कि उन्होंने भूपेश बघेल सरकार गिराने की साजिश रची। उन्हें निलंबित किया गया और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। जैसा इस मामले में हुआ अथवा हो रहा है **वैसे ही प्रसंग** अन्य अनेक राज्यों में भी रह-रहकर सामने आते रहते हैं। राज्यों में सरकारें बदलने के साथ पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के मनमाने इस्तेमाल का एक दूसरा सिलसिला शुरू हो जाता है। जब भी राज्यों में सत्ता परिवर्तन होता है तो या तो अफसरों के एक वर्ग का व्यवहार बदल जाता है या फिर उनके प्रति नई सरकार के रवैये में परिवर्तन आ जाता है।

पुलिस और नौकरशाही का यह राजनीतिकरण चिंतित करने वाला चलन बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी छत्तीसगढ़ के घटनाक्रम के संदर्भ में अपनी इसी चिंता को व्यक्त किया है। यह मामला इसलिए और अधिक ध्यान खींचने वाला है, क्योंकि निलंबित पुलिस अफसर गुरजिंदर पाल सिंह पर राज्य सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने और समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप में राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। राजद्रोह एक अत्यंत गंभीर आरोप है।



राजनेताओं की पुलिस व अपराधियों से मिलीभगत

राजनेताओं की पुलिस व आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों से मिलीभगत से बने त्रिकोण की जड़ें इसलिए मजबूत हो रही हैं, क्योंकि पुलिस या तो दबाव में या फिर स्वार्थवश अपना काम सही तरह से करने से इंकार कर रही है। अगर पुलिस लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाए कि उसके लिए हर नागरिक समान है तो न केवल उसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि लोकतंत्र को भी मजबूती मिलेगी। पुलिस का उद्देश्य तो अपनी ऐसी छवि का निर्माण करना होना चाहिए कि लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें। सुरक्षा की ऐसी भावना सशक्त समाज के निर्माण के साथ देश के तेज विकास में भी सहायक बनेगी।

इसका राजनीतिक फायदे के लिए मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह गौर करने लायक है कि इस कानून का जितनी सहजता से इस्तेमाल किया जाता है उतना ही मुश्किल इसे साबित कर पाना होता है। ऐसे विरले ही मामले होंगे जिनमें कोई राज्य सरकार किसी पर राजद्रोह के आरोप को उच्चतम न्यायालय के स्तर तक साबित कर पाई हो। फिर भी यह कानून मौजूद है और राज्य इसका मनमाने ढंग से दुरुपयोग कर रहे हैं।

पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के मनमाने इस्तेमाल को लेकर समस्या इसलिए और अधिक गंभीर हो गई है, क्योंकि खुद पुलिस और प्रशासनिक अफसर न तो अपनी छवि को लेकर गंभीर हैं और न इसे रोकने के इच्छुक दिखते हैं। राजनेताओं और पुलिस-प्रशासनिक अफसरों का

गठजोड़ अपने-अपने हितों की पूर्ति के लिए एक-दूसरे का पूरक बनकर काम करता है। राज्य सरकारों को पुलिस और नौकरशाही का साथ इसलिए भी रास आता है, क्योंकि इससे वे अपने चुनावी हितों को भी पूरा करती हैं। ताजा उदाहरण बंगाल का है, जहां चुनाव के बाद हिंसा के तमाम मामले सामने आए और अदालतों को भी इसमें दखल देना पड़ा। उच्च न्यायालय ने हिंसा के इन मामलों की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी है। यह वक्त ही बताएगा कि इन मामलों में किसी अफसर की जिम्मेदारी तय हो पाती है या नहीं? यह सवाल इसलिए, क्योंकि अतीत में ऐसे चुनिंदा मामले ही सामने आए, जिनमें दोषी पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को कड़ी सजा मिली हो।

राजनेताओं और पुलिस-प्रशासन का यह गठजोड़ आम आदमी को निराश करने के साथ ही उसका भरोसा तोड़ने वाला है। लोगों का विश्वास इसलिए कम होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस राजनीतिक एजेंडे के तहत काम करती है। ऐसे में यह अपेक्षा कठिन है कि जो लोग **राजनीतिक रूप से सताए** हुए हैं उन्हें पुलिस से सहायता आसानी से हासिल हो पाती होगी। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण ने जनता की रही-सही आस भी तोड़ने का काम किया है। आपराधिक छवि और प्रवृत्ति वाले लोगों की राजनीति में सक्रियता और उन्हें पुलिस व नेताओं से मिलने वाला संरक्षण केवल लोकतंत्र को ही दूषित नहीं करता, बल्कि शासन-प्रशासन को भी कमजोर करता है और लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था को भी डिगाता है। इस पर अंकुश के लिए उच्चतम न्यायालय ने कई निर्देश दिए हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही है।

● धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया

म प्र जल्द ही देश का ऐसा राज्य बनने की राह पर है, जिसमें अपनी जरूरत के अलावा देश के कई अन्य महत्वपूर्ण संस्थान मद्र की सौर ऊर्जा से ही रोशन होंगे। इसकी वजह है प्रदेश में इस क्षेत्र में तेजी से काम किया जाना। फिलहाल प्रदेश के आगर-शाजापुर-नीमच के 1500 मेगावाट के नए सोलर पार्क को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। यही नहीं प्रदेश में करीब चार मेगावाट की सौर ऊर्जा की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन सभी के पूरा होने पर मद्र में अगले साल तक करीब छह हजार मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मद्र देश में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्रदेश बन जाएगा। अभी मद्र से आगे तीन राज्य हैं।

खास बात यह है कि आगर-शाजापुर-नीमच में लगने वाले प्लांट में तैयार होने वाली बिजली की दरें प्रति यूनिट 2 रुपए 14 पैसे तय कर दी गई हैं। इस प्लांट के लिए अब जल्द ही राज्य सरकार सोलर पार्क लगाने वाली 6 कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करेगी। सरकार हर हाल में इस प्लांट से मार्च 2023 तक उत्पादन शुरू करना चाहती है। इसके अलावा सरकार द्वारा ऑकारेश्वर बांध के जलग्रहण क्षेत्र के 12 वर्ग किमी में 600 मेगावाट के विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पार्क के निर्माण की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए सर्वे होने के बाद अब टेंडर का प्रारूप तैयार करने का काम किया जा रहा है। ऑकारेश्वर के साथ ही मुरैना में 1400 मेगावाट और छतरपुर में 950 मेगावाट के सोलर पार्क के निर्माण की भी तैयारी है। जमीन मिलते ही इन पर भी काम शुरू होगा। मुरैना में तीन हजार हैक्टेयर जमीन चाहिए, इसमें से 1800 हैक्टेयर चिन्हित कर ली गई है। छतरपुर में 1900 हैक्टेयर में से 1500 हैक्टेयर जमीन आवंटित हो गई है, शेष 400 हैक्टेयर जमीन पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में आ रही है। यदि यह जमीन नहीं मिलती है तो छतरपुर में 950 मेगावाट प्रोजेक्ट को 750 मेगावाट कर दिया जाएगा।

आगर-शाजापुर और नीमच सोलर प्रोजेक्ट को लेकर विभाग का अनुमान है कि इस नए सोलर पार्क से 25 साल में सरकार के 7600 करोड़ रुपए बचेंगे। साथ ही 5250 करोड़ रुपए का निजी निवेश होगा। इस पार्क के लिए 6 कंपनियों के नाम तय किए गए हैं इनमें आगर के 550 मेगावाट सोलर पार्क के लिए बीम पाव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और अवाडा एनर्जी लिमिटेड, शाजापुर के 450 मेगावाट के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल तथा तले टट्टाई सोलर

मद्र में इस समय बिजली कटौती को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस बीच सुखद समाचार यह है कि प्रदेश में सोलर एनर्जी का दायरा बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि प्रदेश को सोलर पावर स्टेट कहा जाने लगा है।

सोलर पावर स्टेट का तमगा



15 वर्ष तक मिलेगी 93 मेगावाट परमाणु बिजली

मद्र पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और भारत सरकार के न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) के मध्य गत दिवस 93 मेगावाट बिजली क्रय करने के लिए एक पावर परचेस एग्रीमेंट (पीपीए) काकरापार में हस्ताक्षरित हुआ। मद्र को गुजरात स्थित काकरापार परमाणु विद्युत गृह से उत्पादित होने वाली बिजली में से 93 मेगावाट बिजली 15 वर्षों तक मिलेगी। मद्र को प्राप्त होने वाली बिजली की वर्तमान दर 2.289 प्रति यूनिट है। पावर परचेस एग्रीमेंट पर मद्र पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से मुख्य महाप्रबंधक प्रमोद चौधरी और काकरापार के स्टेशन डायरेक्टर एबी देशमुख ने हस्ताक्षर किए। पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से यह एग्रीमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 99वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में किया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि इस पावर परचेस एग्रीमेंट से मद्र को 15 वर्षों तक सस्ती दर पर 93 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रदूषण रहित उपलब्ध होने वाली बिजली से कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी।

प्रोजेक्ट और नीमच के 500 मेगावाट सोलर पार्क के लिए टीपी सौर्या लिमिटेड, मुंबई तथा अल जोमेह एनर्जी एंड वॉटर कंपनी, दुबई शामिल हैं। मद्र में सौर ऊर्जा की 5 हजार मेगावाट की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। प्रदेश की पहली रीवा सौर परियोजना के लिए गठित कंपनी रमस

द्वारा आगर, शाजापुर, नीमच, छतरपुर, ऑकारेश्वर तथा मुरैना में स्थापित होने वाली इन परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया है। आगरा में 550 मेगावाट, शाजापुर में 450 मेगावाट, नीमच में 500 मेगावाट, छतरपुर में 1500 मेगावाट, ऑकारेश्वर फ्लोटिंग ऑकारेश्वर बांध स्थल पर 600 मेगावाट और मुरैना में 1400 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सौर पार्कों की स्थापना की कार्यवाही चल रही है।

प्रदेश में अब तक 30 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस वर्ष प्रदेश के 700 शासकीय भवनों पर 50 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफ टॉप लगाना प्रस्तावित है। सोलर रूफ टॉप संयंत्रों से उत्पादित बिजली की दरें 1 रुपए 38 पैसे प्राप्त हुईं। सरकार का प्रयास है कि रूफटॉप संयंत्र घर-घर लगाए जाएं ताकि उपयोग के लिए बिजली सस्ती दरों पर मिले। शासकीय भवनों पर सौर संयंत्र ऐसे मॉडल पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें हितग्राही को विभाग अथवा संस्था को कोई पैसा नहीं देना है। संयंत्र विकसित करने वाला सस्ती बिजली उपलब्ध कराएगा।

मद्र को एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने का तमगा पहले ही मिल चुका है। यह है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। यह रीवा जिले की गुढ़ तहसील में 1,590 एकड़ (6.4 वर्ग किलोमीटर) के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे जुलाई 2018 में 750 मेगावाट क्षमता के साथ चालू किया गया था। परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, मद्र ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सौर ऊर्जा निगम का एक संयुक्त उद्यम है।

● विकास दुबे

मप्र की केन-बेतवा लिंक परियोजना में एक के बाद एक पेंच फंसाता जा रहा है। हालत यह है कि एक समस्या का समाधान हो नहीं पता है और दूसरी खड़ी हो जाती है। अब इसकी राह में

नया पेंच जमीन का फंस गया है। वन महकमे ने जरूरत से दो हजार हैक्टेयर जमीन कम देने का अंडगा लगा दिया है। इसकी वजह से परियोजना के लिए जरूरी 6017 हैक्टेयर जमीन में से दो साल की कवायद के बाद

4 हजार हैक्टेयर जमीन ही मिलने का रास्ता साफ हो पाया है। यह जमीन पन्ना नेशनल पार्क के पास है। इसमें भी अभी बड़ा पेंच फंसा हुआ है। इसके लिए परियोजना के बदले जमीन देने के नियमों में बदलाव करना होगा या फिर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विशेष आदेश जारी करना होगा तभी इस परियोजना को मंजूरी मिल पाएगी। दरअसल केन-बेतवा लिंक परियोजना में पन्ना नेशनल पार्क की 6017 हैक्टेयर जमीन डूब में आएगी, जिसमें 4200 हैक्टेयर कोर एरिये का और 2 हजार हैक्टेयर के करीब बफर एरिये का क्षेत्र है।

इस मामले में जल संसाधन विभाग को कोर एरिया के बदले जमीन मिल सकती है, लेकिन बफर एरिया के तहत आने वाली जमीन का जो क्षेत्र है, उसके बदले में जमीन मिलना मुश्किल है। इस मामले में सिंचाई विभाग का मानना है कि ऐसे वन क्षेत्र में पौधरोपण किया जाना चाहिए, जहां पर वनों की उजाड़ स्थिति हो। सिंचाई विभाग इस जमीन पर होने वाले वनों के नुकसान के एवज में 10 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर पौधरोपण के लिए बतौर एडवांस राशि जमा कराने को तैयार है। फिलहाल वन विभाग ने इस प्रस्ताव को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया है, अब इस मामले में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ही अंतिम निर्णय करना है।

इस परियोजना से मप्र के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले को सीधा फायदा मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से कई जिले लाभान्वित होंगे। वहीं, पड़ोसी राज्य उप्र के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले को इसका फायदा मिलेगा। इस परियोजना से मप्र के बुंदेलखंड

केन-बेतवा लिंक परियोजना में फंसा पेंच



अंचल के तहत आने वाले इन 9 जिलों में 8 लाख 11 हजार हैक्टेयर असिंचित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी। इसी तरह से उप्र की चार लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई सुविधा में वृद्धि हो जाएगी। जिसकी वजह से दोनों ही राज्यों में 12 लाख हैक्टेयर भूमि में दो-तीन फसलें लेने की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा करीब 41 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिल जाएगी। वर्ष 2017-18 में लगाए गए अनुमान के मुताबिक परियोजना की लागत करीब 35 हजार 111 करोड़ रुपए थी, जिसमें अब वृद्धि होना तय है। इसमें कुल लागत का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष राशि राज्यों को देनी होगी। इस परियोजना से बाघ विचरण का क्षेत्र कम होना तय है। इसकी वजह है परियोजना से आसपास के इलाके के जंगल में हर मौसम में पानी भरा रहेगा। इसके अलावा नेशनल पार्क के आसपास अगर दो हजार हैक्टेयर जमीन नहीं मिलती है तो भी बाघ विचरण इलाके में कमी आना तय है। इससे पन्ना नेशनल पार्क का क्षेत्रफल तीन हजार हैक्टेयर के लगभग कम होने का अनुमान है।

अक्टूबर माह में केन-बेतवा लिंक परियोजना के शिलान्यास की तैयारी की जा रही है। उप्र का सिंचाई विभाग जोर-शोर से इसकी तैयारियों में जुटा है। सिंचाई विभाग अक्टूबर माह से इसका निर्माण कार्य आरंभ कराने की तैयारी में है। पिछले दिनों दिल्ली से आई विशेषज्ञों की टीम झांसी जिले में स्थानीय अभियंताओं के साथ

सर्वे में जुटी है। वहीं, दिल्ली की विशेषज्ञ एजेंसी की भी मदद ली जा रही है। यह परियोजना लंबे समय तक राजनीतिक विवादों के चलते अटकी रही। 10 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद मप्र और उप्र सरकार के बीच सहमति बन सकी। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए इन दिनों सर्वे समेत अन्य कार्य कराए जा रहे हैं।

बुंदेलखंड क्षेत्र की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना की मूल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में इसे दो चरणों में पूरा किया जाना था। जल संसाधन मंत्रालय ने मूल परियोजना रूपरेखा में परिवर्तन करते हुए अब दोनों चरणों को एक साथ मिला दिया है। जल संसाधन, नदी विकास मंत्रालय द्वारा केन-बेतवा लिंक के प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाने का फैसला मप्र सरकार के आग्रह पर किया गया है। इसके कारण इस परियोजना के संबंध में कुछ आवश्यक मंजूरी पर मंत्रालय काम कर रहा है। केन-बेतवा लिंक परियोजना में चार बांध बनाए जाएंगे। ढोढ़न बांध के अलावा तीन और बांध भी मप्र के रायसेन और विदिशा में बेतवा नदी पर बनेंगे। केन नदी पर 77 मीटर ऊंचा व 19633 वर्ग किलोमीटर जलग्रहण क्षमता वाले इस ढोढ़न बांध में 2584 एमसीएम पानी भंडारण की क्षमता होगी। 2613.19 करोड़ की लागत वाले इस बांध से दो बिजली घर बनेंगे जिससे 36 मेगावाट बिजली बनेगी। इस बिजली घर पर 341.55 करोड़ की राशि व्यय होगी।

● बृजेश साहू

लिंक परियोजना के माध्यम से मप्र एवं उप्र के पांच जिलों की कुल 635661 हैक्टेयर भूमि सिंचित होनी है। परियोजना के मुताबिक उप्र के बांदा व मप्र के छतरपुर जिले की सीमा पर ढोढ़न गांव के निकट गंगोई बांध से केन नदी को तीस मीटर चौड़ी कांक्रिट नहर बनाकर आगे ले जाना है। धसान नदी पर एक टनल (सुरंग) बनाकर आगे बढ़ाया जाएगा। हरपालपुर से होकर उप्र के मऊरानीपुर बार्डर से

तीस मीटर चौड़ी बनेगी कांक्रिट नहर

होते हुए ओरछा के निचले हिस्से में स्थित नोट घाट पुल में मिला दिया जाएगा। नहर का पूरा डूब व प्रभावित क्षेत्र मप्र में है। अधीक्षण अभियंता शीलवत उपाध्याय के मुताबिक परियोजना के लिए काम तेजी से किया जा रहा है। जल्द ही शिलान्यास कराकर काम आगे बढ़ाया जाएगा।

टा इगर स्टेट कहलाने वाला मप्र बाघों की मौत के मामले में भी देश में नंबर-1 है। यहां पिछले 8 महीने में 31 बाघों की जान जा चुकी है। कुछ का शिकार किया गया तो कुछ अपनी मौत मरे। इसमें सबसे ज्यादा 18 मौतें टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई हैं। हाल ही में रातापानी सेंचुरी में भी 2 बाघों के शव मिले थे। बाघों की मौत के मामले में पार्क प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। वन्य प्राणी प्रेमी बाघों की मौत का कारण टाइगर रिजर्व में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति को मानते हैं, जिनका वाइल्ड लाइफ प्रबंधन से कोई लेना-देना नहीं है।

गौरतलब है कि वर्ष 2018 की बाघ गणना में मप्र में सबसे अधिक 526 बाघ पाए गए। वहीं, कर्नाटक में 524 बाघ मिले थे। मप्र से टाइगर स्टेट का दर्जा वर्ष 2010 में छिना था। तब प्रदेश में 257 बाघ बचे थे। वर्ष 2014 की बाघ गिनती में कुछ स्थिति सुधरी थी। महज आठ साल के अंतर से मप्र ने टाइगर स्टेट का खोया तमगा तो पा लिया, पर उसे बरकरार रख पाने में संदेह है। यहां सरकार बाघ बचा नहीं पा रही है। इनमें से ज्यादातर बाघों की मौत का कारण क्षेत्र को लेकर लड़ाई (टेरीटरी फाइट) है। जानकारों का मानना है कि बाघों की संख्या बढ़ी है तो क्षेत्र को लेकर लड़ाई लाजमी है। हालांकि तीन मामले शिकार के भी सामने आए हैं। वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉ. सुदेश वाघमारे बताते हैं कि प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ गई है इसलिए उनका रहवास क्षेत्र भी बढ़ाना होगा। अभी क्षेत्र कम है, इसलिए बाघों में लड़ाई होती है। कुछ दुर्घटना और शिकार के मामले भी हैं। जिनमें वन विभाग को चौकन्ना रहने की जरूरत है।

पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ आलोक कुमार का कहना है कि बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से उनमें टेरिटोरियल फाइट होती है। इसमें कमजोर बाघ घायल होकर या तो इलाका छोड़ देता है या मर जाता है। जो कि प्राकृतिक है। टेरिटोरियल फाइट रोकने के लिए सेंचुरी बनाकर नए इलाके की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में फरवरी 2009 में बाघ विहीन हो गया था। यहां बाघों के कुनबे को बढ़ाने के लिए दो अलग-अलग टाइगर रिजर्व से बाघ-बाघिनों को शिफ्ट किया गया। इसके करीब ढाई साल बाद जंगल में अप्रैल 2012 में एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया। इसके बाद यहां बाघों का कुनबा लगातार बढ़ता गया। वर्तमान में पन्ना में 31 बाघ हैं।

बाघों की मौत का सही कारण नहीं मिलने और मौत को दबाने के लिए हर बार एक घोषणा कर दी जाती है। हाल ही में वनमंत्री विजय शाह ने बुंदेलखंड में नई सेंचुरी घोषित की, जबकि कांग्रेस सरकार की प्रस्तावित 9 सेंचुरी की



6 सालों में 170 बाघों की मौत

बाघों की संख्या, 700 के आसपास होने की संभावना

देश में 'टाइगर स्टेट' के नाम से मशहूर मप्र में इन दिनों बाघों की गणना की प्रक्रिया चल रही है और माना जा रहा है कि इनकी संख्या बढ़कर लगभग 700 हो सकती है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तीन साल पहले वर्ष 2018 में बाघों की गणना में राज्य में 526 बाघ होने की पुष्टि हुई थी और यह संख्या देश में सबसे अधिक थी। इन बाघों में लगभग 60 फीसदी बाघ 'टाइगर रिजर्व' के क्षेत्रों और 40 फीसदी बाघ अन्य वन क्षेत्रों में मौजूद थे। सबसे अधिक 124 बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में थे। सूत्रों ने कहा कि राज्य में बाघों की गणना की प्रक्रिया चल रही है और प्रारंभिक रुझानों के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि लगभग 700 बाघ की संख्या के साथ मप्र एक बार फिर से देश में अव्वल रहेगा। बाघों की गणना राष्ट्रीय स्तर पर भी जारी है और अंतिम आंकड़े आगामी तीन माह में आने की संभावना है। पिछले साल के अंत में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से तेंदुए की आबादी की अखिल भारतीय आंकलन संबंधी रिपोर्ट के अनुसार देशभर में 12 हजार 852 तेंदुए थे। अकेले मप्र में यह संख्या 3 हजार 421 आंकी गई है।

प्रक्रिया टंडे बस्ते में पड़ी हुई है। इसमें सीहोर की सरदार वल्लभ भाई सेंचुरी भी शामिल है।

वन्य प्राणी विशेषज्ञ बताते हैं कि 50 से 60 वर्ग किमी क्षेत्र में अपनी टेरिटरी बनाता है। इसमें एक बाघ के साथ लगभग 2 बाघिन भी रहती हैं। वर्तमान में मप्र में 526 बाघ हैं। वहीं वन क्षेत्र 77,483 वर्ग किमी है, लेकिन खास बात यह है कि 10,174 वर्ग किमी ही टाइगर टेरिटरी के लिए आरक्षित है। जानकारी के अनुसार मप्र में

सबसे ज्यादा टाइगर टेरिटोरियल फाइट कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई। इस दौरान लगभग 25 बाघों की जान गई। वहीं वन्य क्षेत्र की बात करें तो कान्हा के 2051.791 वर्ग किमी में 108 बाघों का बसेरा है। वहीं बांधवगढ़ के 1537 वर्ग किमी में 124 बाघ रहते हैं। जबकि दोनों ही नेशनल पार्क में बाघों की संख्या के आधार पर 5 से 7 हजार वर्ग किमी का वन्य क्षेत्र होना चाहिए। प्रदेश में 526 बाघों के लिए लगभग 32 हजार वर्ग किमी क्षेत्र आरक्षित होना चाहिए, जबकि बाघों के लिए इसका 10 प्रतिशत ही आरक्षित है। हालांकि वन्य क्षेत्र के मामले में मप्र देश का अग्रणी राज्य है। ऐसे में प्रदेश में अन्य टाइगर टेरिटरी बनाने की आवश्यकता है, ताकि बाघों को पनपने का भरपूर मौका मिल सके।

दरअसल वृद्ध बाघ कई बार युवा बाघों से हारने के बाद सैकड़ों किमी तक घूमने निकल जाते हैं। मेटिंग के काल में भी बाघ अक्सर अपनी टेरिटरी छोड़ बाघिन से मिलन को लेकर लंबी यात्राएं करते हैं। इसी दौरान बाघों का अक्सर दूसरे बाघों से संघर्ष होता है। वहीं कई बार युवा बाघ नन्हे शावकों को मार देते हैं, ताकि बाघिन से मेटिंग कर सकें। बाघ टेरिटोरियल फाइट में सबसे ज्यादा संघर्ष इन्हीं कारणों से होता है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों के बसेरे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर विन सेंटर रहीम बताते हैं कि यहां मौजूद 124 बाघों में से 20 ऐसे हैं जो अक्सर उमरिया और शहडोल तक के जंगलों में चले जाते हैं। इस दौरान आसपास के गांवों में भी विचरण करते हैं और कई बार मानव के सामने आ जाने पर उन पर हमला भी कर देते हैं। वहीं जानकार बताते हैं कि मप्र में बाघों के आपसी संघर्ष रोकने के लिए जरूरी है कि प्रदेश में अन्य टाइगर रिजर्व भी बनाए जाने चाहिए, ताकि बाघ सुरक्षित रह सकें।

● नवीन रघुवंशी

म प्र के 98 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी में कटौती करने की तैयारी शिवराज सिंह चौहान सरकार ने की है। बिजली कंपनियों का घाटा कम करने और सब्सिडी को लेकर गठित मंत्रिमंडल समूह ने सरकार को अपनी सिफारिशें दी हैं।

मंत्रिमंडल समूह ने बिजली सब्सिडी में कटौती की सिफारिश सरकार को दी है। मंत्रिमंडल समूह के मुताबिक जो लोग इंदिरा ग्रह ज्योति योजना के दायरे में आते हैं अभी इन्हें महीने में 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपए का बिल देना पड़ता है। जबकि

101 से लेकर 150 यूनिट तक जितनी बिजली खर्च हुई उसका पैसा निर्धारित घरेलू उपभोक्ताओं की दर के अनुसार

देना पड़ता है। इस पर सरकार की 4786 करोड़ रुपए की सब्सिडी लगती है।

मंत्रिमंडल समूह ने सरकार को सिफारिश की है कि 100 यूनिट के लिए तो 100 रुपए लिए जाएं, लेकिन यदि 101 यूनिट हो जाए तो एक से 101 यूनिट तक का बिल वास्तविक घरेलू दर पर ही लिया जाए। अभी घरेलू दर औसतन 8 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट है। मंत्रिमंडल ने अपनी सिफारिश राज्य सरकार को दी है। मंत्रिमंडल समूह में इंदिरा किसान ज्योति और इंदिरा ग्रह ज्योति योजना का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेई के नाम करने की सिफारिश भी सरकार को की है।

बिजली सब्सिडी में कटौती और इंदिरा ग्रह ज्योति योजना का नाम बदले जाने को लेकर की तैयारी पर कांग्रेस भड़क उठी है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है कि यदि इंदिरा ग्रह ज्योति योजना का नाम बदला जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि सिर्फ योजना का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। सरकार को तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय हुए फैसलों और सस्ती बिजली की योजना को जारी रखना होगा। यदि सरकार योजना में बदलाव करती है तो कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। असल मंत्रिमंडल समूह ने बिजली कंपनियों का घाटा कम करने के लिए और सरकार पर पड़ने वाले भार को सीमित करने के लिए कई अहम सुझाव राज्य सरकार को दिए हैं। बिजली सब्सिडी में कटौती के साथ किसानों की सब्सिडी घटाने के भी साथ प्रस्ताव शामिल हैं। सब्सिडी आधार से जोड़ने और एक कार्ड पर एक ही सब्सिडी दिए जाने की सिफारिश की गई है। साथ ही मंत्रिमंडल समूह में सभी तरह की सब्सिडी बंद कर एक किसान को साल में एक बार 50,000 सीधे सब्सिडी के रूप में देने की भी

गरीबों की सब्सिडी में होगी कटौती...

मग्न में बिजली कुछ लोगों के लिए मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन की कहावत बनी हुई है, वहीं अधिकांश लोगों के लिए महंगाई की मार। ऐसे में बिजली कंपनियां निरंतर घाटे में दबती जा रही हैं। इसको देखते हुए सरकार ने गरीबों की सब्सिडी पर कैंची चलाने की योजना बनाई है। यानी गरीबों को जो सब्सिडी मिल रही है, उसमें सीमाएं तय की जा रही हैं।



बिजली कटौती ने कांग्रेस को दिया मौका

प्रदेश में बिजली कटौती जारी है कांग्रेस इसका मुद्दा बना रही है। वहीं भाजपा के विधायक नारायण त्रिपाठी और राकेश गिरी बिजली कटौती पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। इससे कांग्रेस को बल मिला है। कैबिनेट की बैठक में भी इस पर लंबी चर्चा हुई। बिजली के बड़े बिलों को लेकर सरकार आलोचना के केंद्र में है। दरअसल बिजली कंपनी के बिगड़े मैनेजमेंट का दुष्परिणाम आम बिजली उपभोक्ता को झेलनी पड़ रही है। आलम ये है कि बारिश न होने से सूख रहे फसलों की सिंचाई के लिए न तो गांवों में बिजली मिल पा रही है और न ही उमस भरी रात में चैन की नींद ले पा रहे हैं। शहर और तहसील मुख्यालयों पर तो बिजली मिल रही है, लेकिन गांव में हालत विकट है। कंगाल कंपनियां न तो कोयला खरीद पा रही हैं और न ही मार्केट से बिजली खरीद पा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल से 8 से 10 घंटे ही बिजली टुकड़ों में मिल पा रही है। मग्न राज्य विद्युत नियामक आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि बिजली कटौती की सूचना आम लोगों का अधिकार है। ये कंपनियों की जवाबदारी भी है। बिजली मामलों के जानकारी अधिवक्ता एके अग्रवाल के मुताबिक कंपनियां घोषित कटौती की बजाय तकनीकी फाल्ट का हवाला देकर बिजली कटौती कर रही है। प्रदेश सरकार का दावा है कि जनरेटिंग कंपनियों सहित अनुबंध और सेंट्रल कोटा मिलाकर उसके पास 22 हजार मेगावाट बिजली की उपलब्धता है, लेकिन 10 हजार मेगावाट बिजली सप्लाई करने में ही हालत खराब है। मग्न पावर जनरेशन कंपनी की ताप विद्युत इकाइयों की कुल क्षमता लगभग 5400 मेगावाट है। पर वर्तमान में कोयले की कमी, वार्षिक मेंटेनेंस के चलते महज 1700 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो पा रहा है। लगभग इतनी ही बिजली जल विद्युत संयंत्रों, विंड और सोलर से मिल पा रही है। शेष बिजली सेंट्रल कोटे से लेनी पड़ रही है।

सिफारिश की है। पहले कनेक्शन पर प्रति हॉर्स पावर 1500 रुपए, दूसरे पर 2000 हजार, तीसरे पर 2500 और चौथे पर 3000 राशि लेने का सुझाव भी दिया गया है।

बिजली सब्सिडी कम करने के मंत्रिमंडल समूह के सुझाव पर मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने बिजली कंपनियों में जमकर भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस सरकार के कारण ही बिजली कंपनियां करोड़ों के घाटे में पहुंची। भाजपा सरकार कंपनियों को

घाटे से उबारने में लगी, जो जरूरी कदम होंगे वह उठाए जाएंगे। दरअसल बिजली कंपनियों का सरकारी विभागों के पास ही 1575 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें 90 फीसदी की राशि नगरीय विकास और पंचायत ग्रामीण विकास की है। ऐसे में विभागों की वसूली के साथ सरकार पर निकल रही देनदारियों को कम करने के लिए अब सरकार कुछ नए कड़े फैसले लेने की तैयारी में है।

● श्याम सिंह सिकरवार

बुदेलखंड के चार जिलों बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट में एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) द्वारा बेतवा नदी में खनन पर लगाई गई रोक ने चित्रकूटधाम मंडल की यमुना और केन नदियों में खनन करा रही कई बड़ी कंपनियों और अन्य पट्टाधारकों की नींद उड़ा दी है। इन्हें खतरा सता रहा है कि बेतवा की तर्ज पर एनजीटी का चाबुक यहां पर भी न चल जाए। एनजीटी के आदेश की प्रति

तलाश कर पट्टाधारक कानूनविदों और पर्यावरण विशेषज्ञों की पनाह में पहुंचकर उनसे राय मशविरा कर रहे हैं। एनजीटी की शर्तों के मुताबिक, जुलाई माह से तीन माह के लिए खनन बंद है। यह अगले माह शुरू हो जाएगा। यमुना और केन में लगभग एक सैकड़ा खदानें हैं। हर साल लगभग एक अरब रुपए राजस्व के रूप में आता है। इससे कई गुना ज्यादा पट्टाधारक कमाते हैं।

पूरे बुदेलखंड में बालू, मौरंग, गिट्टी, पत्थर इत्यादि खनिज की खदानें हैं। सबसे ज्यादा खनन बालू का हो रहा है। नियम कानूनों को दरकिनार कर पट्टाधारक नदियों की जलधारा में मशीनों से गहराई तक खनन कर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एनजीटी, सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट कई बार सख्त आदेश और दिशा-निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आई। कुछ दिन पहले नदियों में हो रहे खनन को लेकर एनजीटी में रिट-याचिका दायर की गई थी। काफी दिनों तक चली सुनवाई के बाद एनजीटी ने अपने आदेश संख्या 673/2018 में बेतवा नदी में दोनों तरफ 100-100 मीटर दूरी तक हर तरह के निर्माण, खनन, अतिक्रमण पर रोक लगा दी। कहा कि इससे नदियों में प्रदूषण हो रहा है। एनजीटी के इस आदेश का हवाला देकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उप्र, झांसी के मुख्य अभियंता (बेतवा) ने हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर में स्थित बेतवा नदी के दोनों ओर (जहां मार्जिनल तटबंध नहीं बने हैं) में नदी किनारे से 100 मीटर दूरी तक के क्षेत्र को फ्लड प्लेन जोन के रूप में चिह्नित करने का आदेश दिया है।

यहां हर तरह के निर्माण, अतिक्रमण, व्यावसायिक गतिविधियों, पट्टा नीलामी और प्रदूषण करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बेतवा के लिए हुए इस आदेश से अब यमुना और केन में खनन करने वाले बेचैन हो उठे हैं। उन्हें यह खौफ सता रहा कि यमुना और केन आदि नदियों में भी यह रोक न लग जाए। केन और यमुना नदियों में भी बेतवा की तर्ज पर दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी तक खनन पर प्रतिबंध

‘लाल सोना’ के सौदागरों पर लगाम



केन व यमुना के पट्टाधारकों में खलबली

उरई और हमीरपुर में बेतवा खदानें बंद होने के आसार की खबरें मिलने पर चित्रकूटधाम मंडल में केन, यमुना और बागै आदि नदियों की खदानों के पट्टाधारक असमंजस्य में हैं। एक तरफ उनके लिए यह राहत होगी कि बालू की खपत-डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। हमीरपुर और उरई के ट्रक यहां लोड होने आएंगे। दूसरी तरफ चिंता यह है कि खदानों की नीलामी में प्रतिस्पर्धा (काम्पटीशन) बढ़ जाएगी। हमीरपुर और उरई में बेतवा खदानों के पट्टे लेने वाले केन और यमुना की खदानें हथियाने की जुगत भिड़ाएंगे।

लगा तो सबसे ज्यादा असर बांदा और हमीरपुर जिलों में पड़ेगा। इन्हीं दोनों जिलों में केन और यमुना नदियों में आधा सैकड़ा से ज्यादा खदानें हैं। हमीरपुर में बेतवा पर रोक के बाद केन और यमुना में खनन का दबाव बढ़ेगा।

बांदा जिले में लगभग 20 खदानें चल रहीं हैं। इनके पंचवर्षीय पट्टे वर्ष 2023 और 2024 तक हैं। यहां लगभग 30 करोड़ रुपए रायल्टी-राजस्व खनिज विभाग को मिल रहा है। इसके अलावा अवैध खनन, ओवर लोडिंग आदि में होने वाला जुमाना आदि का राजस्व भी करोड़ों रुपए में है। केन नदी की लाल मौरंग अपनी अलग पहचान रखती है। इसकी मांग उप्र सहित तमाम राज्यों में है। इसलिए केन की खदानें पट्टे पर हथियाने के लिए देश की बड़ी-बड़ी कंपनियां कूद पड़ीं हैं। लखनऊ, रामपुर, अलीगढ़, इटावा, आगरा, चित्रकूट, वाराणसी, कानपुर नगर की कंपनियों सहित राजस्थान, पटना (बिहार), मप्र के इंदौर, मुरैना, सतना आदि जिलों की कंपनियां यहां बालू खदानों के पट्टे लिए हुए हैं।

खनिज विभाग और खदान पट्टाधारक बालू उपभोक्ताओं का जमकर आर्थिक शोषण कर रहे हैं। 10 गुना से भी ज्यादा दरों पर बालू बेची जा रही है। बालू की सरकारी रॉयल्टी दर मात्र 150 रुपए प्रति घन मीटर है, जबकि नीलामी में कंपनियों ने 800 रुपए प्रतिघन मीटर की दर पर खदानें ले रहीं हैं। इसके अलावा भी तमाम खर्च हैं जो उपभोक्ता से ही वसूले जा रहे हैं। पर्यावरण पैरोकारों की राय में एनजीटी को केन और यमुना नदियों में भी तत्काल प्रभाव से खनन पर रोक

लगानी चाहिए। यहां के हालात बेतवा नदी से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। भारी-भरकम मशीनों से नदियों की जलधारा में हो रहे अंधाधुंध और अवैध खनन से चित्रकूटधाम मंडल की 50 लाख से ज्यादा आबादी पर पर्यावरण प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। कुछ करोड़ लागत के लिए नागरिकों की सेहत और प्राण से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

ललितपुर में राजघाट बांध से लेकर हमीरपुर तक बेतवा नदी की लंबाई लगभग साढ़े तीन सौ किलोमीटर है। एनजीटी के आदेश के बाद नदी की यह पट्टी नो डेवलपमेंट जोन बन जाएगी। यहां खनन के पट्टे नहीं होंगे। किसी काम के लिए यहां एनओसी नहीं दी जाएगी। न ही नक्शा पास होगा। अवैध निर्माण पर कानूनी और सीआरपीसी की कार्रवाई होगी। इस पट्टी पर स्थित अवैध निर्माण को बाढ़ से क्षति होने पर कोई हर्जाना या मुआवजा नहीं मिलेगा। न ही यहां बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जाएंगे। हमीरपुर में बेतवा नदी में तकरीबन 125 खदानें हैं। इनमें 28 खदानों के पट्टे चल रहे हैं। यहां बेतवा की लंबाई करीब 134 किलोमीटर है। बालू-खनिज से सालाना दो अरब रुपए से ज्यादा राजस्व आता है। इस वर्ष मार्च तक 2 अरब 22 करोड़ 51 लाख रुपए खनिज राजस्व आया है। जालौन (उरई) जनपद में बेतवा नदी पर 9 बालू खदानें चल रहीं हैं। इनका क्षेत्रफल लगभग 450 एकड़ है। खनिज विभाग के मुताबिक यहां लगभग एक अरब 70 करोड़ रुपए सालाना रॉयल्टी-राजस्व आता है।

● सिद्धार्थ पांडे



2024 में 400 पार ! मोदी पर ही फिर दांव

2024 में लोकसभा चुनाव होना है। इसके लिए विपक्ष जहां एकता की कवायद में जुटा हुआ है, वहीं भाजपा जमावट में। भाजपा ने 2024 में 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य को पाने के लिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर ही दांव लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मोदी के दिशा-निर्देशों पर नई रणनीति बनाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी रणनीति का हिस्सा राज्यों में मुख्यमंत्री बदलना भी है।

● राजेंद्र आगाल

अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर का एक मशहूर कथन है- 'Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.' यानी कि नेतृत्व किसी और से वह

करवाने की कला है जो आप करना चाहते हैं और क्योंकि वह इसे करना चाहता है। भाजपा और संघ की नजरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कथन पर पूरी तरह खरे उतर रहे हैं। इसीलिए भाजपा ने मोदी है तो मुमकिन है नारा दिया है। और अब इसी नारे के दम पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य

निर्धारित कर एक बार फिर से मोदी पर दांव लगाने की तैयारी हो चुकी है। उधर, नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य को पाने के लिए जमावट शुरू कर दी है। पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल और अब राज्यों में अपनी मर्जी के सिपहसलार तैनात कर रहे हैं। इससे भाजपा के साथ ही विपक्ष में भी उथल-पुथल मची हुई है।



भाजपा के लिए अगला लोकसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, यह तो गुजरात के मुख्यमंत्री को बदलने से ही स्पष्ट हो चुका है। सबसे पहले इस क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से त्रिवेन्द्र सिंह रावत को हटाया गया था। उनके स्थान पर आए तीरथ सिंह रावत भी बहुत जल्द ही रवाना कर दिए गए। कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा जैसे कद्दावर नेता को भी मजबूरी में ही हटना पड़ा। असम में अधिकांश विधायकों का समर्थन हिमंता बिस्वा सरमा की तरफ होने की वजह से वहां भी सर्वानंद सोनोवाल को बदला गया, जिन्हें अब केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है। अब गुजरात में ऐसे विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया है जो पहली बार चुनाव जीतकर आए हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाए जाने से पार्टी में नाराजगी भी है, लेकिन सबको विश्वास है कि मोदी कोई ऐसा-वैसा दोव नहीं चलते हैं। इसलिए पार्टी ने भूपेंद्र पटेल को सहर्ष स्वीकार कर लिया है।

विपक्ष की लामबंदी

दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली करारी हार ने भाजपा के आत्मविश्वास को ध्वस्त कर दिया है। भाजपा के लिए भलाई की चिंता करते हुए कई वरिष्ठ नेता अब खुलकर सामने आए हैं, जिन्होंने बंगाल चुनाव के पहले तक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को अपने दायरे में रहने की नसीहत देते हुए अपना काम प्रारंभ कर दिया है। 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर देश के राजनीतिक दलों में अभी से हलचल महसूस की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ एक राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की कोशिशों में बीते कुछ महीनों से काफी तेजी आई है। एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर हुई विपक्षी नेताओं और मोदी सरकार विरोधी बुद्धिजीवी वर्ग की एक बैठक में भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की कवायद की गई थी। हालांकि, इस बैठक के अगले ही दिन सफाई भी दे दी गई थी कि इस मीटिंग में किसी नए राजनीतिक मोर्चे को बनाने के प्रयास नहीं

कैसा है मौजूदा राष्ट्रीय परिदृश्य

दरअसल, राष्ट्रीय स्तर पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे सके, ऐसे नेता का अभाव है। कांग्रेस अपने आंतरिक मतभेदों में उलझी है तो अन्य विपक्षी दल भी अपने-अपने राज्यों में सिमटे हुए हैं। ऐसे में सर्वमान्य विपक्षी नेता को लेकर बड़ी खाई है। चाहे शरद पवार की बात करें या चंद्र बाबू नायडू, अखिलेश यादव, मायावती, उद्धव ठाकरे या अन्य किसी क्षेत्रीय नेता की, प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में उनकी सामर्थ्य कम है। चाहे बंगाल में भाजपा को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। ऐसे सियासी हालात में जब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के एकछत्र नेता की कमी है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी में संभावनाएं नजर आती हैं। अब सवाल यह है कि जमीनी लड़ाई लड़कर जीत हासिल करने की ताकत किस नेता की ज्यादा है तो वह निसंदेह राहुल की तुलना में दीदी की ज्यादा है। हालिया बंगाल चुनाव में दीदी ने जिस तरह अकेले किला लड़ाया और हैट्रिक बनाने का रास्ता साफ किया, वह उनका कद बढ़ाने वाला है। वहीं राहुल गांधी ने भी केरल व तमिलनाडु पर फोकस किया। केरल में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन तमिलनाडु में वह डीएमके के साथ कामयाबी पा रहे हैं। दरअसल बंगाल चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने आक्रामक प्रचार व रणनीति अपनाते हुए पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस का लगातार तीसरी बार जीत हासिल करना साबित करता है कि उसकी बंगाल में जड़ें उसी तरह जम चुकी हैं, जिस तरह कभी वाम मोर्चे की जमी हुई थी। ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या दीदी बंगाल की कमान अपने पास रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ताल ठोकेंगी या बंगाल की गद्दी किसी ओर को सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति में ताल ठोकेंगी? यह देखना होगा।

किए जा रहे हैं। वहीं, कांग्रेस नेता कमलनाथ के साथ मुलाकात के बाद शरद पवार ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के बिना वैकल्पिक मोर्चा खड़ा करना नामुमकिन है। तीसरे या वैकल्पिक मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच देश के मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कहते हुए दिखे कि उन्हें यकीन नहीं है कि तीसरा या चौथा मोर्चा भाजपा को चुनौती दे सकता है।

वैसे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष बनाने की अपील सबसे पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के दौरान की थी। बंगाल चुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरीं। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया भी इन दिनों अपने दिल्ली दौरे पर विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ही राहुल गांधी से भी मुलाकात की। संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस के इस गठबंधन में शामिल होने के बाद भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक चुनौती खड़ी की जा सकती है। हालांकि, इस खिचड़ी विपक्ष बनाने की राह में अभी भी राष्ट्रीय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक कई रोड़े हैं। आइए जानते हैं कि 2024 चुनाव में खिचड़ी विपक्ष का आइडिया मोदी के आगे क्यों फीका है?

मोदी हटाओ का नारा नाकाफी

2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल डील के नाम पर 'चौकीदार चोर है' का नारा निकाला था। लेकिन, इसे काउंटर करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मैं भी चौकीदार' का जो दांव खेला, उसकी वजह से पूरा विपक्ष बैकफुट पर आ गया। वहीं, इस टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करने को लेकर राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी, सो अलग। संयुक्त विपक्ष की कवायद में जुटे राजनीतिक दल केवल मोदी हटाओ के नारे के सहारे मिशन 2024 को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ये नारा सिर्फ तभी काम करेगा, जब मोदी के खिलाफ

क्या एकजुट हो पाएगा विपक्ष

साल 2014 से अब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और विशेषज्ञों की मानें तो विपक्ष अगर इसी तरह बिखरा रहा तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का पलड़ा भारी रहने वाला है। शायद यही वजह है कि आज देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां धीरे-धीरे एक होने का प्रयास कर रही हैं। दशकों की राजनीति के बाद ऐसा देखने को मिला है जब अलग-अलग विचारधारा के दल एक साथ, एक पार्टी या एक व्यक्ति के विरोध में खड़े हो रहे हैं। यह बिल्कुल करीब 44 साल पहले के भारत की राजनीतिक स्थिति की याद दिलाता है। 70 के दशक में इमरजेंसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध में ऐसे ही देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां एक हो गई थीं, इसमें लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट हर विचारधारा के दल मौजूद थे। लेकिन तब के विपक्ष की एकजुटता और अब के विपक्ष की एकजुटता में जमीन आसमान का फर्क है। तब जो सामंजस्य विपक्ष में दिखता था आज वह गायब है। आज के विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ना चाहता, चाहे वह ममता बनर्जी हों या फिर राहुल गांधी। हालांकि यह दोनों नेता अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि समूचा विपक्ष इनके साथ एक मंच पर खड़ा हो। इसीलिए तो ममता बनर्जी ने 5 दिन का दिल्ली दौरा भी किया, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं से बातचीत की और तो और राहुल गांधी भी चाय पार्टी और संसद में सभी विपक्षी नेताओं को एक साथ कर सरकार को घेरने के लिए राजी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों कोशिशों में कई दल ऐसे भी हैं जो अभी भी इस विपक्षी एकता से काफी दूर मौजूद हैं।

कई मोर्चा में बंटा विपक्ष

राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक ऐसी चीज होती है जो नेताओं को एक साथ रखती भी है और एक दूसरे से दूर भी करती है। ममता बनर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखना। बिल्कुल उसी तरह राहुल गांधी की भी ऐसी ही कुछ महत्वाकांक्षा है। हालांकि इन सबके बीच एक और मोर्चा है जो ऐसी महत्वाकांक्षा रखता है। वह है तीसरा मोर्चा, जिसका खांचा लालू प्रसाद यादव जैसे नेता खींच रहे हैं। बीते दिनों ही लालू प्रसाद यादव ने उग्र के नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से फिर शरद यादव से मुलाकात की और तो और जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लालू के रंग में रंगे नजर आए।



कोई गंभीर आरोप हो और उसमें सीधे उनकी संलिप्तता नजर आए। ऐसा आरोप फिलहाल नरेंद्र मोदी पर नजर नहीं आता है।

विपक्ष के पास वैकल्पिक मॉडल नहीं

2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार अपनी विचारधारा और एजेंडे को आगे बढ़ाती रही है। तीन तलाक, सीएए, राम मंदिर, धारा-370 जैसे मुद्दों को भाजपा ने हमेशा से अपने एजेंडे में रखा और इन्हें पूरा भी कर दिया। भाजपा के पास भविष्य के लिए भी कॉमन सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे दर्जनों मुद्दे हैं, जिसके बल पर वह लोगों को एकजुट करने के हरसंभव प्रयास कर सकती है। लेकिन, भाजपा के खिलाफ बनाए जा रहे गठबंधन वाले विपक्ष के पास भाजपा विरोध ही एकमात्र मुद्दा है। देश के मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए विपक्ष पूरी तरह से एजेंडा विहीन नजर आता है। भारत में 80 से 85 फीसदी तेल आयात किया जाता है। क्या विपक्ष के सत्ता में आने पर भारत में तेल के कुएं खोजे जाएंगे? अगर विपक्ष पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटा भी देती है, तो सरकारी योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा? मोदी सरकार वैसे ही पेट्रोल-डीजल के बढ़े हुए दामों को यूपीए सरकार के दौरान जारी किए गए ऑयल बॉन्ड का नतीजा बताती है।

विपक्ष का मानना- भक्त वोटर नहीं

मोदी के खिलाफ तैयार हो रहा विपक्ष मोदी समर्थकों को मोदी भक्त की संज्ञा देता रहा है। इसके साथ ही विपक्ष का मानना है कि मोदी भक्त वोटर नहीं हैं। लेकिन, अगर हम प्रशांत किशोर की बंगाल चुनाव के दौरान की लीक चैट पर भरोसा करें, तो ये बात स्पष्ट होकर सामने आती है कि वोटरों का करीब 20 फीसदी वोट अकेले मोदी के पास है, जिन्हें आप मोदी भक्त कह सकते हैं। और, इन मोदी भक्तों की बड़ी

तादाद की मौजूदगी सोशल मीडिया पर भी नहीं है। जबकि, विपक्षी पार्टियों को विधानसभा चुनाव में वोट देने वाले भी कई लोग केंद्र में मोदी को वोट देते रहे हैं। इसे हम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार से समझ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार सत्ता में वापसी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर उन्हें हार ही मिली है।

हिंदुत्व के आगे घुटने टेकतीं पार्टियां

देश में कई दशकों से मुस्लिम तुष्टीकरण किया जाता रहा है। अब वो शाहबानो मामले पर राजीव गांधी की सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की बात हो या यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक बताने का मामला हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश की आबादी के सबसे बड़ी हिस्से हिंदुओं के बीच ये नैरेटिव बन गया कि वे हमेशा ही दूसरे पायदान पर हैं। भाजपा अपनी पार्टी के गठन के समय से ही हिंदुत्व को लेकर स्पष्ट विचारधारा के साथ चली है। वहीं, अन्य राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोटबैंक के खिसकने के डर से धर्मनिरपेक्षता का ढोल पीटती रहीं। हालांकि, चुनाव में मिलने वाली लगातार हार के बाद सियासी पार्टियों ने सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन, इसे भी भाजपा ने अपने पक्ष में कर लिया। भाजपा की ओर से प्रचारित किया गया कि ये उसकी पार्टी का ही असर है, जो नेता मंदिरों में जाने लगे। मोदी सरकार और भाजपा जहां खुलकर हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही हैं। वहीं, विपक्ष में कई पार्टियां धर्मनिरपेक्षता को लेकर पहले जैसी मुखर नहीं रहीं। बल्कि, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार करने लगी हैं। ऐसे में वो मोदी से हिंदुत्व के मुद्दे पर तो चुनाव लड़ना दूर की कौड़ी नजर आता है।

विपक्ष का चेहरा कौन ?

नरेंद्र मोदी के खिलाफ सशक्त विपक्ष बनाने की तैयारियां भले ही शुरू हो चुकी हों। लेकिन, विपक्ष का चेहरा कौन होगा, सबसे ज्यादा बहस इसी बात पर होनी है। भाजपा के पास नरेंद्र मोदी के तौर पर निर्विवाद और ताकतवर चेहरा है। लेकिन, विपक्ष में नेतृत्व को लेकर अभी से ही खींचतान दिखने लगी है। ये खींचतान 2024 तक खत्म होती भी नहीं दिखती है। खिचड़ी विपक्ष में हर नेता खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताएगा। विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगा। इस स्थिति में विपक्ष के सामने देशभर में सर्वस्वीकार्य नेता चुनने की बड़ी चुनौती है।

चुनाव हराऊ एंटी-इंकम्बेंसी नहीं

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान पैदा हुई भयावह स्थितियों की वजह से मोदी सरकार पर दबाव बना है। पेट्रोल-डीजल से लेकर घर की रसोई तक में महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के बर्दाश्त करने की सीमा पार हो गई है। लेकिन, क्या ये ऐसे मुद्दे हैं, जिनको लेकर जनता का गुस्सा ढाई साल से ज्यादा समय तक कायम रहेगा? राजनीति में ये आम धारणा है कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है। उस पर मोदी और भाजपा को हवा बदलने में महारत हासिल है, उन्हें चुनाव जीतना आता है। हाल ही में हुए मोदी कैबिनेट विस्तार में इन तमाम मुद्दों पर फेल रहे मंत्रियों के चुन-चुनकर इस्तीफे लिए गए। नरेंद्र मोदी कोरोना से हुई मौतों पर भावुक भी हुए। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इससे बहुतों का नहीं, तो कुछ का दिल बदला ही होगा। 2018 में मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा ने 2019 जो प्रचंड जीत हासिल की, उसके बारे में किसने सोचा था। जबकि, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा तब भी था।

देश में खेला करेंगी दीदी!

बंगाल में खेला होबे नारे के हिट होने के बाद ममता बनर्जी 2024 के लिए भी इसी नारे पर ताल ठोक रही हैं ममता का कहना है कि जब तक भाजपा पूरे देश से साफ नहीं हो जाती, तब तक सभी राज्यों में खेला होगा। भाजपा को देश से खदेड़ने तक खेला चलता रहेगा। ममता बनर्जी कह रही है कि भाजपा को देश से खदेड़े बिना लोकतंत्र को बचाना मुश्किल होगा। हमने बंगाल में एक बार खेला दिखा दिया है। अब देशभर में फिर से भगवा पार्टी को खेला दिखाएंगे। 16 अगस्त को हम खेला होबे दिवस मनाएंगे। दरअसल, टीएमसी के इस नारे ने लोगों को



हर बार नाकाम हो रहा विपक्ष

3 साल पहले 2018 में कर्नाटक में विपक्ष की एकता देखने को मिली थी, जब कर्नाटक में कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे थे। ये नजारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी के साथ आए दलों की याद ताजा करा रहा था। सोनिया मायावती की हंसती-मुस्कुराती तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही थीं, लेकिन बेंगलुरु से शुरू हुई विपक्षी एकजुटता की कहानी कर्नाटक विधानसभा में कुमारस्वामी के विश्वासमत गंवाने के साथ ही खत्म हो गई। 2019 में विपक्ष को एकजुट करने की टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की कोशिशों की तुलना 1996 में सीपीएम के दिवंगत नेता हरकिशन सिंह सुरजीत से की जा रही थी। जब सुरजीत के समर्थन से यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी जिसको कांग्रेस ने समर्थन दिया था। 2019 के चुनावों के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने भी भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की थी, नतीजों से पहले नायडू की कोशिश थी कि अगर आंकड़े भाजपा के पक्ष में नहीं आते हैं और विपक्ष की सरकार बना पाने की कोई संभावना जगती है, तो विपक्ष के सहयोगी दल पहले से तैयार हों। लेकिन भाजपा की लहर ने विपक्षी एकजुटता के सपने को चकनाचूर कर दिया। 2024 से पहले फिर से विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश हो रही है, ममता बनर्जी के मुताबिक अभी 3 साल का वक्त है लेकिन शुरुआत अभी से होनी चाहिए। अब देखना है कि 2024 में विपक्ष के इतिहास रचने का दीदी का दावा परवान चढ़ पाता है या नहीं।

ममता सरकार की ओर खूब आकर्षित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियों के बावजूद भाजपा का सोनार बांग्ला का सपना टूट गया और तीसरी बार बंगाल में दीदी की सरकार बनी।

ममता के चेहरे पर विपक्ष एक होगा ?

बंगाल विजय के बाद विपक्षी राजनीति का केंद्र बनकर उभरीं ममता बनर्जी भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों के गठबंधन का संभावित चेहरा हो सकती हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ममता बनर्जी के चेहरे पर विपक्ष एकजुट होगा। क्या ममता गैर एनडीए मोर्चा खड़ा कर पाएंगी? क्योंकि कोशिशें इससे पहले भी की गई थी लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाईं। ममता कहती हैं कि मैं नहीं जानती 2024 में क्या होगा, लेकिन इसके लिए अभी से तैयारियां करनी होंगी। हम जितना समय नष्ट करेंगे, उतनी ही देरी होगी। भाजपा के खिलाफ तमाम दलों को मिलकर एक मोर्चा बनाना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो लोग हमें माफ नहीं करेंगे।

दीदी जगन मोहन, चंद्रबाबू नायडू, नवीन

पटनायक सबसे अच्छे रिश्ते की बात कह रही हैं। वो कहती हैं ये आज साथ नहीं है, लेकिन कल तो आ सकते हैं। इस बीच विपक्षी नेताओं के मेल मुलाकातों का दौर जारी है। शरद पवार, ममता बनर्जी, रामगोपाल यादव ने आरजेडी चीफ लालू यादव से भी मुलाकात की, ममता 2022 उप चुनाव में भाजपा को हराने के लिए भी सभी दलों से साथ आने की अपील कर रही हैं। मिशन 2024 के तहत टीएमसी सुप्रीमो की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। लेकिन, ये बात ममता बनर्जी को भी पता है कि कांग्रेस को दरकिनार कर आम सहमति बना पाना टेढ़ी खीर है। सोनिया और ममता के मुलाकात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कांग्रेस के बिना यूपीए की कल्पना नहीं की जा सकती है।

जब बात यूपीए की होती है तो राहुल गांधी अधोषित रूप से चेहरा बन जाते हैं तो क्या ममता कांग्रेस को किनारे कर टीएमसी की अगुवाई में यूपीए की सोच सकती हैं, आज की तारीख में तो नहीं, तो क्या ममता एनडीए, यूपीए से अलग कोई तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकती हैं। लेकिन फिर यहां सवाल है कि उस मोर्चे में कितने दल



शामिल होंगे और क्या वो इतने मजबूत होंगे कि भाजपा को टक्कर दे सकें। ममता दीदी अच्छी तरह जानती हैं कि अगर ममता बनर्जी खुद को चेहरा बनाने पर अड़ती हैं, तो 2019 की तरह ये गठबंधन बनने से पहले ही फेल हो जाएगा। इसलिए ममता दीदी कह रही हैं कि अगर विपक्ष की ओर से कोई दूसरा चेहरा भी सामने आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मामले पर चर्चा होगी तो हम इस पर फैसला करेंगे।

लोकसभा जिताने वाले मुख्यमंत्री चाहिए

उप्र का मामला भाजपा नेतृत्व के लिए लगभग आउट ऑफ कंट्रोल भले ही हो गया लगता हो और ये कोई अभी-अभी की बात नहीं है। पूरे पांच साल से यही चल रहा है, लेकिन बेफिक्री इस बात को लेकर तो मोदी-शाह को होगी ही कि कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताकत कायम रहते मजाल नहीं कि उप्र में सत्ता से भाजपा को कोई बेदखल कर दे। वैसे भी उप्र की राजनीति फिलहाल जिस मोड में चल रही है वो तो पूरी तरह भाजपा को ही सूट करती है। अयोध्या में राम मंदिर बन ही रहा है। बाकी लव जिहाद से लेकर जनसंख्या नियंत्रण और एनकाउंटर स्टाइल में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में होने का दावा किया ही जा रहा है, स्थिति तनावपूर्ण भले ही हो। दावा करने वाला भी कोई मामूली आदमी नहीं है, देश के गृहमंत्री अमित शाह हैं और कोरोना काल में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने काम किया उसके तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कायल हो गए हैं। ऐसे कायल कि अब तो भाजपा उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा का वाराणसी मॉडल कहीं दिखाई तक नहीं देता।

योगी आदित्यनाथ वैसे भी लखनऊ से गोरखपुर की बजाय मन ही मन दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। अब इससे अच्छी बात क्या होगी कि लोगों को दिल्ली जाने के लिए बाहर से लखनऊ आना पड़ता है और योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही जमे हुए हैं। भले ही विपक्षी खेमे के नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की नजर 2024 के आम चुनाव के रास्ते प्रधानमंत्री की कुर्सी पर टिकी

हो, लेकिन अब तक जो भी सर्वे आए हैं, ये सारे नेता नरेंद्र मोदी के बहुत बाद भी योगी आदित्यनाथ से पिछड़े हुए ही नजर आते हैं। बहुत भारी मन से ही सही लेकिन अब तो सबको समझ आ जाना चाहिए कि मोदी-शाह भाजपा के शासन वाले हर राज्य में चीफ मिनिस्टर के लिए जो अनिवार्य अहर्ताएं सुनिश्चित करते जा रहे हैं वो करीब-करीब योगी मॉडल ही है। अब भाजपा को मिले बहुमत वाले देश के किसी भी सूबे में वैसा ही नेता चाहिए जो योगी मॉडल के पैमाने पर खरा उतरता हो। हाव-भाव और चाल-ढाल से हिंदुत्व, राष्ट्रवाद कदम-कदम पर छलकता और झलकता नजर आता हो। न खाता, न बही जो वो कहे वही सही... जैसी आम धारणा आसपास बनाकर रखे हुए हो। अगर जातिवादी राजनीति करने का भी आरोप लगता हो तो लगे, चलेगा, लेकिन विजय रूपाणी जैसा तो नहीं चलने वाला जिसने कास्ट न्यूट्रल छवि बना रखी हो। वोट बैंक तक कनेक्शन तो जातीय समीकरणों के जरिए ही बन पाते हैं। अगर ऐसा न होता तो जातीय जनगणना को लेकर इतना शोर क्यों मचता? कुल मिलाकर राज्यों के भी भाजपा नेताओं के लिए नेतृत्व का मैसेज ये है कि उसे विधानसभा चुनाव जिताने वाला नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित कराने वाला मुख्यमंत्री ही चाहिए।

अब ये विजय रूपाणी की बदकिस्मती कहे या कुछ और, लेकिन बात एक ये भी है कि ये सब पश्चिम बंगाल की चुनावी हार का ही नतीजा है। भाजपा अलर्ट मोड में आ गई है, लिहाजा पूरे घर को चुस्त-दुरुस्त कर रही है। हर तरफ नौजवानों का बोलबाला और जलवा कायम करने की तैयारी है, कम से कम ऐसे नेता जो 2024 में बूढ़े न लगे, मोर्चा तो वही संभालेंगे। दरअसल, बंगाल की हार 2015 के बिहार की हार से भी बड़ा जख्म है। बिहार का बदला तो मोदी-शाह ने महागठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार को एनडीए में लाते ही ले लिया था, लेकिन बंगाल की ताजा हार का असर ये है कि वो मुसीबत बनकर दिल्ली तक दस्तक देने लगी है। भाजपा को असली चिंता अब 2024 के आम चुनाव की सताने लगी है।

नर्सरी भी तैयार हो रही है, लेकिन दिल्ली में

जैसे नए-नए आईएस और आईपीएस अफसरों को ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती है, बिलकुल वैसे ही भाजपा के नए नेताओं की नर्सरी दिल्ली में तैयार की जा रही है। विजय रूपाणी भी तो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाजपा में हमेशा नए नेतृत्व को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। और 2014 से ही साफ है कि मार्गदर्शक मंडल के लिए भी सूची पहले से ही तैयार कर ली जाती है। अभी-अभी जो मोदी कैबिनेट में फेरबदल हुआ है वो भी तो ऐसी ही नजरी पेश कर रही है। रविशंकर प्रसाद के खिलाफ टिवटर विवाद तो बस बहाना बना। जैसे कोरोनाकाल में मीडिया को हँडल न कर पाना प्रकाश जावड़ेकर के लिए। या चुनावों में बेकार साबित होने वाले बाबुल सुप्रियो के लिए। मोदी कैबिनेट में अब ऐसे नेताओं को काम दिया गया है जो कामकाज शुरू से सीखें। कामकाज की शैली वो सीखें और जब राज्यों में जाकर अकेले काम करने का मौका मिले तो तब वे वही करें जो नेतृत्व चाहता है। तब तो डबल इंजिन का मतलब भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी नेतृत्व के साथ काम करके सीखेगा वो तो अकेले भी वैसा ही करेगा जैसा नेतृत्व चाहता है। रोजाना और साथ में काम करने का एक फायदा ये भी होता है कि नेतृत्व को सभी के कमजोर नस का भी पता चल जाता है, और वो जीवन भर काम आता है। जब भी कोई इधर-उधर देखे या करने की सोचे, तत्काल प्रभाव से नकेल कसने में आसानी हो। उम्र का लिहाज तो सबसे ज्यादा मोदी-शाह को कर्नाटक में करना पड़ा। जो येदियुरप्पा अभी ही 75 पार चल रहे थे वो 2024 तक तो 80 भी पार कर जाते, सबसे बड़ी वजह यही है कि छंटनी की शुरुआत कर्नाटक से हुई है। उत्तराखंड में हुई डबल छंटनी को थोड़ा अलग रखकर देखना होगा, लेकिन वहां भी पुष्कर सिंह धामी को मौका मिलने की बड़ी वजह उनकी उम्र ही है। अभी वो 45 साल के हैं। योगी आदित्यनाथ से भी चार साल छोटे हैं। मुद्दे की बात ये है कि मोदी-शाह को अब राज्यों में युवाओं के नेतृत्व की दरकार है जो लोकसभा की मैक्सिमम सीटें दिला सकें, ताकि मोदी के लिए 2024 में केंद्र की सत्ता में वापसी तो सुनिश्चित हो ही, शाह के लिए भाजपा के गोल्डन पीरियड का सपना भी पूरा हो सके।

दिल्ली के पिछले दो विधानसभा चुनावों में अभूतपूर्व प्रदर्शन के दम पर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। अगले साल पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही आप को अकाली दल और भाजपा के मुकाबले पहले ही काफी बढ़त मिल चुकी है। वहीं, उप्र विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें, तो आम आदमी पार्टी ने यहां पहले ही चुनावी दस्तक दे दी है। उप्र विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है, तो तकरीबन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है।

बसपा सुप्रीमो मायावती सोशल इंजीनियरिंग के सहारे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एमवाई समीकरण के साथ ब्राह्मण वर्ग को लुभाने, कांग्रेस की ओर से मुस्लिम मतदाताओं में पैठ बनाने और भाजपा ने ओबीसी वोटों को साधने की रणनीति के साथ हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर दिया है। वहीं, उप्र में अपनी सियासी जमीन बनाने की कोशिश में जुटी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी अपने चुनावी हथियार निकाल लिए हैं। हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भाजपा के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे को काउंटर करने की तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने अपने सॉफ्ट हिंदुत्व को देशभक्ति का कलेवर देते हुए भाजपा की मुश्किल बढ़ाने की तैयारी कर ली है।

पिछले महीने ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक शिष्टाचार भेंट की थी। इस मुलाकात से सियासी गलियारों में एक नए राजनीतिक समीकरण की सुगबुगाहट नजर आने लगी थी। हालांकि, सपा और आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन, माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को कुछ शहरी विधानसभा सीटें देकर अखिलेश यादव अपने पक्ष में ला सकते हैं। वैसे भी अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि वो किसी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेंगे और छोटे दलों को साथ लाएंगे। तो, फिलहाल आम आदमी पार्टी की जैसी स्थिति है, उसके हिसाब से अखिलेश यादव के साथ जाने से उसे कम से कम अपना जनाधार खड़ा करने में मदद ही मिल जाएगी। वैसे, संजय सिंह भी गठबंधन को लेकर उप्र के हित में फैसला लेने की बात कहते नजर आ चुके हैं।

इस सियासी खिचड़ी में एक रोचक बात ये भी है कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के जिस जमीन विवाद को सपा सरकार के पूर्व मंत्री ने



सॉफ्ट हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का कॉकटेल

2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी विचारधारा को पॉलिटिकली करेक्ट करना की भरपूर कोशिश की। भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को धड़ाम करने के लिए खुद को हनुमान भक्त के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया था। हनुमान मंदिर में दर्शन से इतर उनकी चुनावी रैलियों की शुरुआत भी जय बजरंगबली और जय हनुमान से होने लगी। केजरीवाल ने साफ कर दिया था कि वो भगवान राम के भी भक्त हैं, लेकिन उनके राम और भाजपा के राम में अंतर है। राम मंदिर पर आए फैसले का उन्होंने स्वागत भी किया था। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को कट्टर हिंदुत्व की पार्टी घोषित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पर केंद्र की मोदी सरकार से सबूत मांगने वाले केजरीवाल ने भाजपा के राष्ट्रवाद के एजेंडे को कमजोर करने के लिए दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत की। अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के अन्य नेता हमेशा से ही ये घोषित करते आ रहे हैं कि हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद पर भाजपा के विचार कट्टर हैं। मनीष सिसोदिया ने तिरंगा यात्रा को हिंदू पहचान, धर्म और राष्ट्रवाद को भाजपा के तरीके से पूरी तरह अलग बताया। अरविंद केजरीवाल के सॉफ्ट हिंदुत्व का मॉडल दिल्ली में तो सफल नजर आ चुका है। अगर उप्र में वो अपने सॉफ्ट हिंदुत्व को कैश करने में कामयाब हो जाते हैं, तो भाजपा के लिए मुश्किलें दोगुनी हो जाएंगी। हालांकि, इन तमाम संभावनाओं में सपा के साथ गठबंधन की शर्त जुड़ी हुई है। क्योंकि, आम आदमी पार्टी ने अभी प्रदेश में पहला कदम रखा है और भाजपा से नाराज मतदाताओं की पहली पसंद फिलहाल अरविंद केजरीवाल तो नहीं हैं।

उठाया था। उसे संजय सिंह ने पुरजोर तरीके से उठाते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी थी। चौंकाने वाली बात ये भी रही कि संजय सिंह के जमीन विवाद का मामला उठाते ही सपा एकदम शांत हो गई थी। इस मामले पर एक तरह से सपा ने पूरा थाल सजाकर आम आदमी पार्टी के सामने रख दिया था। वहीं, आम आदमी पार्टी अब अयोध्या में तिरंगा यात्रा के जरिए रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करने की तैयारी कर रही है, तो ये काफी हद तक एक सोची-समझी रणनीति नजर आती है। उप्र के बहुकोणीय विधानसभा चुनाव को धीरे-धीरे द्विकोणीय किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसमें अपने सॉफ्ट हिंदुत्व का तड़का लगा रही है। सपा और आम आदमी पार्टी की करीबियत बढ़ने से भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा होना तय है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल काफी लोकप्रिय है। फ्री बिजली-पानी और उच्च स्तर के सरकारी स्कूलों के सहारे दिल्ली में केजरीवाल सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं।

कोरोना महामारी के बाद भाजपा के लिए परिस्थितियां काफी हद तक बदल गई हैं। रही-सही कसर किसान आंदोलन ने भी निकाल दी है। उप्र के लखनऊ, कानपुर जैसे महानगरों में आम आदमी पार्टी के नेताओं के पोस्टर पर फ्री बिजली-पानी और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के वादों की झड़ी लगी हुई है। भाजपा से नाराज वोटर एक ठिकाना खोज रहा है और आम आदमी पार्टी के रूप में उसे वो मिल भी सकता है। बशर्ते, सपा के साथ उसका गठबंधन फाइनल हो। फिलहाल जैसी नजदीकियां अखिलेश यादव और संजय सिंह के बीच नजर आ रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उप्र विधानसभा चुनाव 2022 से पहले लोगों को चौंकाया जा सकता है। भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को धड़ाम करने के लिए केजरीवाल ने खुद को हनुमान भक्त के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया था। भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को धड़ाम करने के लिए केजरीवाल ने खुद को हनुमान भक्त के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया था।

● राजेश बोरकर

विपक्षी एकता असंभव क्यों?



कुछ दिनों पहले ही सोनिया गांधी ने 19 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ऑनलाइन मीटिंग के सहारे विपक्षी एकता का प्रदर्शन किया था। इस मीटिंग के दौरान सोनिया गांधी ने कहा था कि सबकी अपनी मजबूरियां भी हैं, लेकिन राष्ट्र हित की मांग है कि हम सब उससे ऊपर उठें। क्या ऐसा संभव है?

देश में भाजपा और नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष ने एकजुटता के कई प्रयास किए लेकिन सभी विफल रहे। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी एकता की कवायद फिर से शुरू हो रही है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि जब भी चेहरे की बात आती है तो विपक्ष की एकता तार-तार हो जाती है। इसलिए इस बार भी विपक्षी एकता की संभावना कम नजर आ रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ साझा विपक्ष की रणनीति लगातार जोर पकड़ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के जरिए 15 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेताओं के समर्थन से मोदी सरकार को घेरने में कोई कोताही नहीं बरती थी। संसद के मानसून सत्र में सभी विपक्षी दलों ने एकसुर में मोदी सरकार और उसकी नीतियों का विरोध किया था। मानसून सत्र के दौरान ही तृणमूल कांग्रेस सुप्रियो ममता बनर्जी भी विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए दिल्ली दौरे पर आई थी। इस दौरे पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल समेत कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी।

कुछ दिनों पहले ही सोनिया गांधी ने 19 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ऑनलाइन मीटिंग के सहारे विपक्षी एकता की ताकत का प्रदर्शन किया था। 2014 और 2019 में जो

बदल गया कांग्रेस का मन

पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज गया है। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्हें यहां से हर हाल में चुनाव जीतना होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस ने भवानीपुर सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारने के फैसला किया है। कांग्रेस भले ही ममता के खिलाफ अपना कैडिडेट न उतार रही हो, लेकिन वाममोर्चा ममता को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस-लेफ्ट गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा था। गठबंधन के तहत इस सीट पर सीपीएम की मीनाक्षी मुखर्जी ने किस्मत आजमाई थी। कांग्रेस और लेफ्ट ने इस सीट पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा था, जिसका नतीजा रहा कि ममता भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार गईं। वहीं, अब उपचुनाव में ममता बनर्जी अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से मैदान में हैं। माना जा रहा है कि दो अहम कारण के चलते कांग्रेस ने ममता को वॉकओवर देना का फैसला किया है। पहला कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन पूरी तरह से फेल रहा और दोनों ही दलों का खाता तक नहीं खुला। इसके अलावा भवानीपुर सीट ममता की परंपरागत है, जहां कांग्रेस ने कैडिडेट न उतारकर 2024 के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच इन दिनों दोस्ती बढ़ रही है। वहीं भाजपा ने यहां से प्रियंका टिबरीवाल को उम्मीदवार बनाकर उतारा है।

विपक्ष बुरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा था, वो मिशन-2024 के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इस मीटिंग के दौरान सोनिया गांधी ने कहा था कि सबकी अपनी मजबूरियां भी हैं, लेकिन राष्ट्र हित की मांग है कि हम सब उससे ऊपर उठें। सोनिया गांधी ने जिन मजबूरियों की बात कही है, साझा विपक्ष की कवायद के सामने चेहरा कौन होगा, महंगाई जैसे मुद्दों पर वैकल्पिक मॉडल क्या होगा जैसी तमाम मुश्किलों से बिल्कुल अलग है। ये वही मजबूरियां हैं, जिन्हें लेकर कहा जा सकता है कि साझा विपक्ष की कोशिश में सभी सियासी दलों का साथ आना 'असंभव' लगता है। ऐसा लगता है कि साझा विपक्ष बनाने की कोशिशें केवल कांग्रेस ही कर रही है। ऐसा लगता है कि साझा विपक्ष बनाने की कोशिशें केवल कांग्रेस ही कर रही है।

हाल ही में कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस के खेमे में शामिल हुई सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा था कि उन्हें कांग्रेस नेतृत्व से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि, कोई शिकायत न होने के बाद भी उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन समान विचारधारा होने की बात कहकर थाम लिया। दरअसल, बीते कुछ समय में तृणमूल कांग्रेस में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए हैं। असम और त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है कि वो भाजपा के सामने खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पेश करे। उप में भी कांग्रेस और बसपा के कई नेता और विधायक सपा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि, इसे अन्य सियासी दलों की

ओर से राजनीतिक शिकार की तरह पेश नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे तमाम नेता इसे विचारधारा की राजनीति कहकर कांग्रेस से किनारे हो रहे हैं।

खैर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लगातार दो बार लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस के नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनकी विचारधारा पर हावी हो रही हैं। लेकिन, सोनिया गांधी की हालिया मीटिंग से उग्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव गायब रहे थे। ऐसा तब हुआ है, जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने खुद अपनी ओर से अखिलेश यादव की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। लेकिन, इस गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। कहना गलत नहीं होगा कि साझा विपक्ष के फॉर्मूले की असल परीक्षा उग्र विधानसभा चुनाव में ही होनी है। लेकिन, सोनिया गांधी की मीटिंग से गायब रहकर सपा ने संदेश दे दिया कि मिशन-2024 में कांग्रेस के साथ गठबंधन के मूड में नहीं हैं।

वहीं, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी साझा विपक्ष की सभी बैठकों में बराबर हिस्सा लेने के बावजूद कांग्रेस को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने साझा विपक्ष के लिए कांग्रेस की अब तक की गई तमाम कोशिशों से दूरी बना रखी है। लेकिन, वो ममता बनर्जी के साथ मेल-मुलाकातों में पीछे नहीं हैं। आम आदमी पार्टी भी उग्र, पंजाब, गोवा, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में तेजी से पैर पसार रही है। उसकी रणनीति भी इन राज्यों में तृणमूल कांग्रेस से मिलती-जुलती है। भाजपा के सामने विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस से ऊपर खुद को प्रोजेक्ट कर रही है। साथ ही कांग्रेस के नेताओं को भी पार्टी में शामिल कर रही है। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में साझा विपक्ष के फॉर्मूले का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। पंजाब में कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। उत्तराखंड में भी कमोबेश यही हाल है। वहां कांग्रेस के सामने भाजपा से बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी बनकर उभर रही है। उग्र में कांग्रेस के खुले ऑफर को भी अखिलेश यादव ने नकार दिया है। कुल मिलाकर इस लिस्ट में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मप्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र भी है। यहां कांग्रेस को चुनौती देने के लिए भाजपा के साथ ही सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी भी अपनी हिस्सेदारी लेने पहुंचेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के साथ ही अन्य राज्यों में ये सियासी दल



ममता व नीतीश को एक मंच पर लाने की तैयारी

देश की राजनीति में एक बार फिर तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर चर्चा होने लगी है। किसान आंदोलन और जाति आधारित जनगणना सहित अन्य मसलों को लेकर गैर कांग्रेसी विपक्षी दल एक मंच पर आने की कोशिश में जुटे हैं। जाहिर है इससे बिहार की राजनीति भी अछूती नहीं रह सकती है। संभावित तीसरे मोर्चे के एक बड़े आयोजन में एनडीए सरकार की प्रबल विरोधी ममता बनर्जी, राकांपा चीफ शरद पवार, शिरोमणि अकाली दल से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जैसे चेहरों को एक साथ आने की तैयारी है। इसमें मजदोर बात यह है कि कार्यक्रम के लिए भाजपा के अन्य सहयोगी जदयू के नेता और बिहार में एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बुलावा मिला है। यह कार्यक्रम हरियाणा के जींद में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इसकी अगुवाई कर रहे हैं। इस आयोजन से जुड़ी कुछ और भी खास बातें हैं। गौर करने वाला एक मसला यह भी है कि नीतीश कुमार हाल में ही चौटाला से मिलने पहुंचे थे और दोनों नेताओं ने अपनी नजदीकी का जिक्र किया था। अब अपनी दोस्ती निभाते हुए नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में भाजपा के तमाम बड़े विरोधियों के साथ मंच शेयर करते हैं या नहीं, यह वक्त बताएगा। यह कार्यक्रम 25 सितंबर को होना है और जदयू के कुछ नेताओं की माने तो नीतीश इसमें नहीं जाएंगे।

अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि साझा विपक्ष का फॉर्मूला सियासी दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आगे असंभव ही नजर आता है।

सपा, आप, बसपा और तृणमूल कांग्रेस सरीखे दल लगातार कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड़ा उग्र में मृतप्राय हो चुकी कांग्रेस में फिर से जीवन फूंकने की कोशिश कर रहीं हैं। लेकिन, उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा अखिलेश यादव ही नजर आ रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी दूसरा सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस के लिए चुनौती पेश करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। कहना गलत नहीं होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच चल रही सियासी खींचतान का फायदा अगर आम आदमी पार्टी को मिल जाता है। तो, राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस के लिए भाजपा से बड़ी सियासी मुश्किल अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे।

महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन सरकार का हिस्सा है। लेकिन, यहां एनसीपी और शिवसेना लगातार कांग्रेस को कमजोर करने की पटकथा लिखने में व्यस्त नजर आते हैं। साझा विपक्ष की कवायद के सहारे सोनिया गांधी कोशिश कर रही हैं कि राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री पद तक का रास्ता बनाया जा सके। लेकिन, उनकी इस कवायद को फिलहाल ममता बनर्जी की ओर से परोक्ष रूप से चुनौती मिल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब जीत जाते हैं, तो इस रेस में वो भी शामिल हो जाएंगे। क्या कांग्रेस का इतना बड़ा दिल होगा कि वो मिशन 2024 के लिए साझा विपक्ष बनाने की कोशिश में तमाम राज्यों में खुशी-खुशी अन्य सियासी दलों के सामने हथियार डाल देगी।

● रजनीकांत पारे

मप्र सहित देशभर में भाजपा नेक्स्ट जनरेशन को आगे ला रही है। संगठन में यह नजारा कुछ सालों से दिख रहा है, वहीं अब सरकार में भी नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में तो इसका प्रयोग किया ही है, अब राज्यों में भी हो रहा है। पार्टी इसी तर्ज पर अभी तक 5 राज्यों के मुख्यमंत्री बदल चुकी है। आगे भी यह बदलाव जारी रहने के संकेत दिए गए हैं।



नई लीडरशिप

ऐसा लग रहा है कि भाजपा अपने मुख्यमंत्रियों को बदलने के मिशन पर है। पिछले 6 महीने में पार्टी अपने 5 मुख्यमंत्री बदल चुकी है। हालांकि, पांचों बदलाव बेहद आसान रहे और कहीं भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इससे पहले जुलाई में बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

65 साल के विजय रुपाणी का अचानक गुजरात मुख्यमंत्री पद से हट जाना हर किसी को चौंका रहा है, लेकिन भाजपा को करीब से देखने वाले इसे पार्टी की नई स्टैटजी बता रहे हैं। जुलाई में ही पार्टी ने उत्तराखंड से 57 साल के तीरथ सिंह रावत और कर्नाटक से 78 साल के येदियुरप्पा को हटाया है। इनकी जगह उत्तराखंड में 45 साल के पुष्कर सिंह धामी और कर्नाटक में 61 साल के बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। वहीं अब गुजरात में भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये चर्चा जोरों पर है कि, मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव देव पर भी संकेत के बादल कभी भी आ सकते हैं।

केंद्रीय नेतृत्व हर एक राज्य की समीक्षा कर रहा है। भाजपा जिन राज्यों में सरकार में हैं, वहां भी समीक्षा की जा रही है और जहां सरकार में नहीं हैं वहां भी समीक्षा की जा रही है। इसी

सिलसिले में बीते कुछ महीनों से मुख्यमंत्रियों को दिल्ली भी बुलाया जा चुका है। मप्र और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से जुलाई में ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फीडबैक लिया था।

भाजपा को करीब से देखने वाले कहते हैं, पार्टी में नेक्स्ट जनरेशन तैयार की जा रही है। यह बदलाव अचानक नहीं किया गया बल्कि प्रधानमंत्री ने खुद अपने मंत्रिमंडल में इसे करके दिखाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 45 साल या उससे कम उम्र के 6 युवा नेताओं को मंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बदलने जैसा कोई भी फैसला अचानक नहीं लिया जा रहा। इसमें पार्टी संगठन का फीडबैक, संघ की राय, प्राइवेट एजेंसी के सर्वे के अलावा बहुत से दूसरे ऐसे सोर्सज हैं, जिनके पॉइंट्स आने के बाद बदलाव किया जा रहा है। मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान,

उत्तराखंड ये सभी ऐसे राज्य हैं जहां पार्टी नई लीडरशिप खड़ी करने पर बहुत जोरों से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ ही संघ भी इसमें लगा हुआ है। ऐसी चर्चाएं हैं कि विजय रुपाणी अमित शाह के बहुत खास थे, इसलिए उन्हें मोदी ने हटा दिया। ये इस बात का संकेत भी देता है कि सिर्फ खास होने से काम नहीं चलेगा। आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा और जो परफॉर्म करेगा वो ही टिकेगा। रुपाणी की प्रशासनिक क्षमता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। अरविंद केजरीवाल के दो दिनों के दौरे ने उन्हें परेशान कर दिया था, इसलिए गुजरात में बदलाव होना तय था।

प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को बहुत करीब से देखने वाले सुधीर रावल कहते हैं कि, भाजपा शासित अधिकतर राज्यों में कम्युनल एंगल ही भुनाने की कोशिश हो रही है।

गुजरात का पैटर्न पूरे देश में लागू कर रही भाजपा

भाजपा गुजरात का पैटर्न पूरे देश में लागू करना चाहती है। इस पैटर्न में बड़ा चेहरा सिर्फ दिखाने के लिए होता है और पूरा काम ब्यूरोक्रेसी के हाथों में होता है। मतलब चीफ सेक्रेटरी सबसे ज्यादा पॉवरफुल होते हैं। ऐसे में जहां भी जो नेता खुद को आगे बढ़ाने में लगा है, वहां उसके पर कतरे जा रहे हैं। वैसे भी भाजपा को बंगाल में बड़ा झटका लगा है। बिहार में भी वे हारते-हारते बचे। इस कारण भी पार्टी लीडरशिप फ्यूचर को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती। दूसरा एक कारण ये भी है कि, भाजपा में अब एक, दो व्यक्तियों की राय बहुत महत्वपूर्ण है।



नेशनलिज्म को बहुत उठाया जा रहा है। गवर्नेस में इवेंट की कार्य संस्कृति पनप रही है। इससे लोक कल्याण के काम नहीं हो पाते। राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने के पीछे एंटी इंकम्बेंसी, गवर्नेस तो एक वजह है ही साथ ही अलग-अलग जगहों से जो फीडबैक लिए जा रहे हैं, वो काफी मायने रख रहे हैं।

गुजरात में अगले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। इसी पैटर्न पर 2017 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया था। चुनावी पंडितों का मानना है कि मुख्यमंत्री बदलकर भाजपा एंटी इंकम्बेंसी के असर को कम करने की कोशिश करती है। हमने पिछले तीन विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखा तो विजय रुपाणी के इस्तीफे की वजह और साफ हो जाती है। पिछले तीन चुनाव में भाजपा की सीटें लगातार कम हो रही हैं और कांग्रेस बढ़त हासिल कर रही है। 2007 में भाजपा ने 117 सीटें जीती थीं, जो 2017 के चुनाव में घटकर 99 बचीं। वहीं, कांग्रेस ने 2007 के चुनाव में 59 सीटें जीती थी, जो 2017 के चुनाव में बढ़कर 77 हो गईं।

दिसंबर 2022 में गुजरात की 182 सीटों पर चुनाव होने हैं। बहुमत का आंकड़ा 92 है और भाजपा के पास फिलहाल 99 सीटें हैं। पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर 5 हजार से कम वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। अगर इस बार एंटी इंकम्बेंसी की वजह से भाजपा की 16 सीटें भी कम हो जाती हैं तो उनकी संख्या 83 बचेगी। इसी तरह 32 ऐसी सीटें ऐसी हैं, जहां तीसरे नंबर वाले प्रत्याशी को मिले वोट जीत-हार के अंतर से ज्यादा हैं। ऐसी 18 सीटों पर भाजपा जीती है। ऐसे में 18 सीटें भी कम होती हैं तो पार्टी का आंकड़ा 81 सीट बचेगा। ऐसे में भाजपा बहुमत के आंकड़े से दूर

कई राज्यों में बदलाव की सुगबुगाहट

देश में भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जो विजय के लिए किसी का भी बलिदान देने में संकोच नहीं करती है। इसकी वजह यह है कि पार्टी और आरएसएस निरंतर अपने नेताओं की काबिलियत का आंकलन करते रहते हैं। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर नेताओं को पद और प्रतिष्ठा मिलती है। गुजरात में अचानक मुख्यमंत्री बदलने के बाद कई राज्यों में इस बात पर चिंतन-मनन शुरू हो गया है कि अगर फिर से काम नहीं हुआ तो कभी भी कुर्सी बदल सकती है। गौरतलब है कि आगामी कुछ सालों के दौरान देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री का बदलना अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए एक बड़ा संदेश है।

रह जाएगी और गुजरात में बना पार्टी का किला ढह सकता है। येदियुरप्पा ने 76 वर्ष की उम्र में 26 जुलाई 2019 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भाजपा ने तय कर रखा है कि 75 वर्ष में नेताओं को रिटायरमेंट देना है, पर येदियुरप्पा इसके अपवाद साबित हुए। उन्होंने कर्नाटक में भाजपा के लिए कई रिकॉर्ड बनाए। वे भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के 18 मुख्यमंत्रियों के साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों में भी सबसे बुजुर्ग रहे। उन पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव बन रहा था। 16 जुलाई को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद से ही अफवाहों का दौर शुरू हो गया था। हालांकि, येदियुरप्पा इन दावों को खारिज करते रहे और 26 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

10 मार्च को उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान यह

बदलाव हुआ था। सूत्रों का कहना है कि इस बदलाव की बड़ी वजह हरिद्वार कुंभ में कोरोना का मिस-मैनेजमेंट रहा था। त्रिवेंद्र से कई साधु-संत भी नाराज हो गए थे और उन्होंने भी इस्तीफे की मांग की थी। भाजपा ने 2016 में असम विधानसभा चुनाव सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में लड़ा। उस समय वे केंद्रीय मंत्री थे। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर असम भेजा गया। भाजपा ने पहली बार असम में अपनी सरकार बनाई थी। सोनोवाल 5 साल मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद भी 2021 के चुनावों में पार्टी ने सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया।

भाजपा नए मुख्यमंत्री के तौर पर सोनोवाल या हिमंता बिसवा सरमा में से एक को चुनने को लेकर पसोपेश में थी। चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित हुए और इसके बाद हिमंता का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित हुआ। इसके बाद 7 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल के समय सोनोवाल को मंत्री बनाया गया। भाजपा के जिन 5 मुख्यमंत्रियों को बदला गया है, उनमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल सबसे छोटा रहा। उन्होंने 10 मार्च को पदभार ग्रहण किया और 2 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। वे तीन महीने भी कुर्सी पर नहीं रह सके। तीरथ गढ़वाल से लोकसभा सांसद थे। दावा यह भी किया गया कि उत्तराखंड में एक साल बाद चुनाव होने थे। इस वजह से चुनाव आयोग किसी भी विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं करवाने वाला था। अगर तीरथ मुख्यमंत्री बने रहते तो उनके लिए विधानसभा सदस्य बन पाना मुश्किल हो सकता था। कानूनन उन्हें 10 सितंबर तक किसी भी स्थिति में विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक था। तीरथ के बाद पुष्कर सिंह धामी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। तीरथ अब भी लोकसभा सदस्य हैं।

● इन्द्र कुमार

कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मॉडल के रुझान तो राहुल गांधी के दौर से पहले ही आने लगे। भूपेश बघेल ने बतौर मुख्यमंत्री वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ दौरे का न्यौता दिया था और उसमें

खास फोकस बस्तर क्षेत्र को लेकर दिखा था। हो सकता है टीएस सिंहदेव को भी राहुल गांधी के दौर को लेकर उम्मीद की कोई किरण नजर आई हो। टीएस सिंहदेव

बघेल की कुर्बानी!

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी के मौजूदा आधे कार्यकाल के दावेदार हैं और सोच रहे होंगे कि अगर भूपेश बघेल की गलतियां राहुल गांधी ने पकड़ ली तो काम बन जाएगा। हो सकता है भूपेश बघेल के मन में भी ऐसी कोई आशंका हो और वैसी नौबत आने से पहले भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी वाड़ा की सहमति लेकर या सलाह से अपने पिता नंदकुमार बघेल की गिरफ्तारी का फरमान जारी कर दिया हो, ये सोचकर कि ये कुर्बानी तो बेकार जाने से रही।

मनुष्य का सोचा हुआ होता कहां है? भले ही वो राजनीति की ही फीलड क्यों न हो। ये तो ऐसा लगता है जैसे उग्र में ब्राह्मणों की नाराजगी से बचने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ओबीसी वोट बैंक को भी नाराज कर दिया हो, जातीय राजनीति के फायदे भी हैं और बड़े नुकसान भी। जरा सी चूक हुई और लेने के देने पड़ जाते हैं। भूपेश बघेल के नजरिए से देखें तो कुर्सी पर पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए तो ये सियासी चाल काफी फायदेमंद लगती है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड़ा के हिसाब से देखें तो नंदकुमार बघेल की गिरफ्तारी से कुर्सी समाज तो नाराज होगा ही, और सोशल मीडिया के जरिए गिरफ्तारी के नाम पर जो नजारा देखने को मिला है। वो महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के वाक्ये से तो बिलकुल ही अलग है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ने पूरे के चक्कर में आधा भी गवां दिया है।

देश के एक मुख्यमंत्री का अपने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और फिर गिरफ्तारी की मंजूरी देना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। राजनीति में ऐसी कुर्बानियां कम ही देखने को मिलती हैं। जब लोग कुर्सी पर जमे रहने के लिए इस्तीफा देने को तैयार न हों, ऐसे में कोई नेता कुर्सी पर रहते हुए अपने पिता की गिरफ्तारी की मंजूरी या आदेश दे और फिर बयान दे, कानून की नजर में सब बराबर हैं। लेकिन नंदकुमार बघेल की एक तस्वीर ही सारा पोल खोल देती है। एक वायरल तस्वीर में नंदकुमार बघेल के लिए थाने का सरकारी



कांग्रेस के हाथ क्या हासिल ?

जातीय विद्वेष वाले बयान देने को लेकर नंदकुमार बघेल के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हुई है, उसके सीधे-सीधे दो लाभार्थी लगते हैं, एक खुद भूपेश बघेल और दूसरी, तात्कालिक तौर पर उनको कुर्सी पर बिटाए रखने के मामले में मेंटोर बनीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा। हाल ही में भूपेश बघेल को दो दिन में ही दो-दो बार रायपुर से दिल्ली बुलाया गया था। दरअसल, जिस दिन वो राहुल गांधी से मिलकर लौट गए थे उस दिन प्रियंका गांधी वाड़ा के दिल्ली में न होने की वजह से मीटिंग नहीं हो पाई थी। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदले जाने के पीछे कोई सियासी दलील नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के अपना वादा निभाने की तत्परता के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने 2018 में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाते वक्त उनके विरोधी दावेदार टीएस सिंहदेव से वादा किया था कि ढाई साल बाद वो उनको कुर्सी पर बिटा देंगे।

फर्नीचर डाइनिंग टेबल और कुर्सी में तब्दील हो जाता है। बेशक कानून की नजर में सब बराबर नजर आते जब छत्तीसगढ़ के हर थाने में गिरफ्तारी के बाद पुलिस हर आरोपी से ऐसे ही पेश आती। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सभी ने तस्वीर पर नाराजगी नहीं जताई है, बल्कि कह रहे हैं कि जब तक आरोप साबित न हों, पुलिस से ऐसा व्यवहार अपेक्षित है। लेकिन तस्वीर देखते ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी का वीडियो आंखों के सामने आ जाता है, जब उनके हाथ में डिनर की थाली है और उनको दो मिनट के लिए भी पुलिस बख्शा देने को तैयार नहीं नजर आ रही है। दोनों ही गिरफ्तारियों के पीछे प्रक्रिया, परिणति और मकसद तो तकरीबन एक जैसे ही हैं। हां, नारायण राणे को तत्परता के चलते 8 घंटे में ही जमानत मिल जाती है, जबकि नंदकुमार बघेल जमानत न मांगकर जेल भेज दिए जाते हैं।

नंदकुमार बघेल के खिलाफ रायपुर के डीडी नगर थाने में आईपीसी की धारा 505 और धारा 153-ए के तहत केस दर्ज किया गया था। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद वो 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। पिता के खिलाफ पुलिस एक्शन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना रहा, 'पिता के रूप में उनको पूरा सम्मान है, लेकिन माहौल बिगाड़ने

वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समाज में सभी वर्गों के बीच समरसता और भाईचारा बने रहना चाहिए, कोई कोई इसमें आड़े आएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'

नंदकुमार बघेल अपने खिलाफ बेटे भूपेश बघेल के एक्शन पर फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं, निश्चित ही आपने पुत्रधर्म और राजधर्म का पालन कर जो मिसाल भारतीय राजनीति में दी है, वह देश में विरले ही देखने को मिलता है मुझे आप पर गर्व है, परंतु मेरा एक ही धर्म है और वह है एससी-एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक लोगों के हक और अधिकार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना। जय मूलनिवासी। असल में नंदकुमार बघेल शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले में एक विरोध प्रदर्शन में लखनऊ में थे और उसी दौरान कहा था, आंदोलन हम करेंगे और ब्राह्मणों को गंगा से वोला भेजेंगे, वो परदेसी हैं, विदेशी हैं, जिस तरह से अंग्रेज लोग आए और चले गए, वैसे ये ब्राह्मण या तो सुधर जाएं या फिर गंगा से वोला जाने के लिए तैयार हों। नंदकुमार बघेल ने ब्राह्मणों से नाराजगी की वजह भी बतायी थी, 'क्योंकि ब्राह्मण विदेशी हैं और हमको अच्छूत मानते हैं। हमारे सारे अधिकार वह छीन रहे हैं, इसीलिए उनसे लड़ाई जरूरी है, उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जाए।'

● रायपुर से टीपी सिंह

महारानी पर दांव

2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है।

इससे पहले ही राज्य में गृह-मात का खेल शुरू हो गया है। मौके की नजाकत को देखते

हुए कांग्रेस ने दांव चला है और महारानी को भाजपा का दमदार चेहरा

बताया है। उधर, भाजपा में भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर घमासान तेज हो गया है।

सेनापतियों ने संभाला मोर्चा

बता दें, हाड़ौती दौरे से एक्शन में आ चुकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हाल ही में दिल्ली में हुई सांसदों की बैठक में भी गई थीं। वहीं कभी मैडम राजे के खास सिपहसालार रहे राजेंद्र राठौड़ तो हाल ही में बोल ही चुके हैं कि, 'राजे ही हैं हमारी नेता।' दूसरी तरफ मैडम राजे के समर्थक भी एक के बाद एक मैदान में उतर रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले कटारिया से अदावत रखने वाले रणधीर सिंह भिंडर ने मैडम राजे से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा है कि, 'अगर वसुंधरा राजे के कहने पर भिंडर को वल्लभनगर से उपचुनाव में मैदान में उतारा जाता है तो भाजपा के कई नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी और ये तय हो जाएगा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे ही भाजपा है। इधर गहलोत कैंप के दोनों खास 'सेनापतियों' द्वारा मैडम राजे के पक्ष में बयान देना वया ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री गहलोत को अंदाजा लग चुका है कि वसुंधरा राजे ही कुछ दिन में भाजपा को लीड करने वाली हैं।

कर नहीं रहा, ये तो एक-दूसरे की कमियां निकाल रहे, पोस्टर फाड़ रहे हैं।' जयपुर में टीम वसुंधरा का ऑफिस खुलने पर डोटसरा ने इशारों इशारों में कहा कि, 'भाजपा नेता नए-नए संगठन और दल बना रहे हैं। राजस्थान की जनता सब देख रही है। मुझे नहीं लगता ही भाजपा आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी।'

गोविंद सिंह डोटसरा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ करना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। डोटसरा से पहले गहलोत सरकार के नंबर दो मंत्री और खास सिपहसालार शांति धारीवाल भी अलवर दौरे के दौरान वसुंधरा राजे की शान में कसीदे पढ़ चुके हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए यूडीएच विभाग में राजे सरकार द्वारा



बनाई गई एक धारा को जादूई धारा बता चुके हैं। धारीवाल के बाद अब गोविंद सिंह डोटसरा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बड़ा चेहरा बताना कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंदेशा पैदा करता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गहलोत कैंप के खासमखास सिपहसालारों डोटसरा और धारीवाल द्वारा मैडम वसुंधरा राजे की तारीफ किया जाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। गहलोत कैंप मरुधरा में भाजपा से फाइट को गहलोत बनाम वसुंधरा करने में जुटा है। इससे एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। जनता में ये मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस सरकार और संगठन मानता है कि वसुंधरा राजे भाजपा में सबसे बड़ी नेता हैं। दूसरा पायलट कैंप को ये बताया जा रहा है कि मरुधरा तो गहलोत और वसुंधरा की सियासी कर्मभूमि है, पायलट कैंप के लिए यहां जगह बनाना मुश्किल है।

वहीं, मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी नेताओं द्वारा मैडम राजे की लगातार तारीफ करना और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक नेताओं द्वारा एकदम से एक्टिव होने के बाद से भाजपा प्रदेश संगठन में मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी टोक रहे नेताओं में जबरदस्त सन्नाटा छाया हुआ है। इन नेताओं की मैडम राजे और उनके समर्थकों के हर एक्शन पर पूरी नजर जरूर है लेकिन इसके जवाब में कुछ कर सकने में असहाय हैं। इधर पायलट कैंप भी पूरे घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं। गहलोत कैंप और वसुंधरा राजे कैंप दोनों की ओर से जारी बयानों पर पायलट कैंप की नजर है। इधर गहलोत कैंप वसुंधरा राजे को भाजपा में स्थापित करने के लिए बयानबाजी कर रहा है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि, 'आखिर सियासत के 'जादूगर' के दिमाग में चल क्या रहा है?

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

राजस्थान कांग्रेस और भाजपा में गुटबाजी जगजाहिर है। दोनों ही दल अपने नेताओं में जारी अंतर्कलह से परेशान हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट में शह-मात का खेल चल रहा है। तो भाजपा में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार सामने आ गए हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा तो कई सवाल खड़े कर गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हाड़ौती दौरे के बाद से एक्शन में हैं। इन सबके बीच अब एक के बाद एक गहलोत कैंप के खासमखास सिपहसालारों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ किया जाना चर्चा का विषय बनी हुई है।

हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास सिपहसालार और सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने अलवर दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की शान में जमकर कसीदे पढ़े थे तो अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटसरा ने मैडम राजे को भाजपा में सबसे बड़ा चेहरा बताया है। गहलोत कैंप के नेताओं का वसुंधरा राजे के प्रति इस तरह अचानक जाता सॉफ्ट कॉर्नर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे इधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भारी बारिश से प्रभावित इलाके हाड़ौती का दौरा कर और समसामयिक मुद्दों पर सरकार को घेरकर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने का संकेत दे चुकी हैं।

दरअसल, गोविंद सिंह डोटसरा ने पूर्व मुख्यमंत्री मैडम राजे की तारीफ की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। डोटसरा ने कहा कि 'राजस्थान में भाजपा खत्म हो रही है, इन पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं है, इनकी लड़ाई को देखते हुए लग रहा है कि किसी दूसरे दल को विपक्ष की भूमिका निभाई पड़ेगी।' प्रदेश भाजपा नेताओं की अंतर्कलह पर निशाना साधते हुए डोटसरा ने कहा कि, 'भाजपा के नेताओं को लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। राजेंद्र राठौड़ कहते हैं मैं बड़ा हूँ, अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कह रहे हैं बड़ा हूँ, सतीश पूनिया तो कहते ही रहते हैं बड़ा।' इसी बीच पीसीसी चीफ डोटसरा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए कहा कि, 'वसुंधरा जी तो दो बार मुख्यमंत्री रहीं हैं, इन सब से तो वो बड़ा चेहरा हैं, इसमें कहने की जरूरत और दो राय नहीं है।' डोटसरा ने कहा कि, 'भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे को नहीं मानता है।'

भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा ने कहा कि, 'भाजपा में जबरदस्त अंतर्कलह है। राजस्थान की जनता सब देख रही है, जनता पूछ भी रही है, प्रतिपक्ष सरकार की कमी खामियां तो उजागर

ना रायण राणे की राजनीति का मौजूदा दौर कब तक ऐसे ही कायम रहेगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि भाजपा भी उनको तभी तक सपोर्ट करने वाली है जब तक उद्धव ठाकरे को डैमेज करने में वो सक्षम हैं। उद्धव ठाकरे की ही तरह नारायण राणे लगे हाथ उनके चचेरे भाई राज ठाकरे को भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं। बल्कि, कहें कि उद्धव ठाकरे से कहीं ज्यादा नारायण राणे तो राज ठाकरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नारायण राणे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये तीनों ही शिवसेना की राजनीति की उपज हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ तीनों ने अपने अलग रास्ते बना लिए। उद्धव ठाकरे ने तो अपनी मर्जी से ऐसी राजनीतिक राह चुनी जो शिवसेना की आक्रामक राजनीतिक शैली के विपरीत रही, लेकिन राज ठाकरे और नारायण राणे की राजनीति ओरिजिनल शिवसेना स्टाइल वाली ही रही है।

देखा जाए तो नारायण राणे के नए तेवर से राज ठाकरे को ज्यादा नुकसान होता लगता है, बनिस्वत उद्धव ठाकरे के। शिवसेना की पुरानी इमेज से इतर नरम छवि गढ़ने का श्रेय उद्धव ठाकरे को ही हासिल है। अगर राज ठाकरे और नारायण राणे भी बाल ठाकरे के बेटे होते तो उद्धव ठाकरे को भी काफी हद तक वैसे ही संघर्ष करना पड़ता जैसे लालू यादव की आरजेडी में उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को करना पड़ रहा है। तब बाल ठाकरे भी तेजस्वी की ही तरह राज ठाकरे या नारायण राणे को भी अपना उत्तराधिकारी बनाए होते, वैसे बाल ठाकरे की स्टाइल वाली राजनीति राज ठाकरे और नारायण राणे आज भी करते हैं। नारायण राणे ने निशाना तो उद्धव ठाकरे को बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट राज ठाकरे पर होता नजर आ रहा है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन अब तो बड़ी मुश्किल से महाराष्ट्र विधानसभा में वो अपना एक ही विधायक भेज पाए हैं।

राज ठाकरे अब अगले साल होने जा रहे महानगरनिगम और जिला परिषद चुनावों की तैयारी कर रहे हैं और चुनावों को अपने बेटे अमित ठाकरे के लिए लांच पैड बनाने की कोशिश में जुटे हैं। 2019 के आम चुनाव में तो राज ठाकरे मोदी विरोध का झंडा बुलंद किए हुए



राणे से किसको नुकसान

थे, लेकिन शिवसेना के साथ गठबंधन टूट जाने के बाद भाजपा और एमएनएस के बीच नजदीकियां बढ़ाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और दोनों पक्षों के नेताओं की कुछ छिपी हुई और कुछ घोषित मुलाकातें किसी म्युचुअल डील के फाइनल की तरफ बढ़ने का इशारा भी कर रही हैं। नारायण राणे की हालिया सक्रियता ने एक तरह से राज ठाकरे की राजनीति को ही, लगता है जैसे किसी बड़े कवर से ढंकने की कोशिश हो रही हो। भाजपा की तरफ से गठबंधन की ऐसी शर्त रखी गई है जो उनकी राजनीतिक जमीन ही ले डूबे। भाजपा गठबंधन से पहले राज ठाकरे पर उत्तर भारतीयों को लेकर अपना रुख सार्वजनिक तौर पर बदलने का दबाव डाल रही है।

राज ठाकरे जिस मझधार में फंसे हैं, ऑप्शन भी कम ही बचे हैं, लिहाजा भाजपा के अलावा किसी के साथ गठबंधन के आसार भी कम ही लगते हैं, लेकिन ये कैसे संभव है कि राज ठाकरे वही मुद्दा छोड़ दें जिसके बूते अभी तक करीब-करीब जीरो बैलेंस के साथ मैदान में बने हुए हैं। अब तक ये सब जैसे भी होता आया हो, आगे भी नारायण राणे कदम-कदम पर उद्धव ठाकरे के साथ-साथ राज ठाकरे के लिए भी सिरदर्द ही साबित होने वाले हैं। कानूनी अड़चनों के खत्म होने और सेहत की दुश्वारियों से उबरकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपनी जनआशीर्वाद यात्रा

शिवसेना के गढ़ कोंकण से ही शुरू की और निशाने पर ठाकरे परिवार रहा। ऐसा भी नहीं कि जवाब नहीं मिला, जवाब भी मुंहतोड़ मिला है।

अज्ञानता का मजाक उड़ाने और थप्पड़ मारने की बात बोलने के बाद अब नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को साफ शब्दों में चेताया है कि जल्द ही शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ पोल खेल मुहिम भी शुरू करने वाले हैं। शिवसेना में बिताए अपनी राजनीति के चार दशकों की दुहाई देते हुए नारायण राणे दावा करते हैं कि वो कई राज जानते हैं। सार्वजनिक रूप से कहते भी हैं, 'रमेश मोरे की हत्या कैसे हुई? उसके पीछे क्या कारण है? अपनी भाभी पर एसिड फेंकने की बात किसने कही थी? ये सभी मामले एक के बाद एक बाहर निकलूंगा।' उद्धव ठाकरे तो रिफेक्ट नहीं करते, शिवसेना की तरफ से मोर्चा संभालते हैं रत्नागिरी से सांसद विनायक राउत, बिलकुल जैसे को तैसा वाले अंदाज में, 'अपने चचेरे भाई अंकुश राणे की हत्या किसने की? उसे किस गाड़ी में ले जाकर कहा फेंका गया? इसकी भी जांच होने की जरूरत है।' और नारायण राणे को विनायक राउत सलाह भी देते हैं, 'दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले राणे को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखने की जरूरत है।'

● बिन्दु माथुर

निकाय चुनावों की अहमियत तो सभी राज्यों में होती है, लेकिन महाराष्ट्र में

इस बार ये खास मायने रखता है क्योंकि ठाकरे परिवार उसी के रास्ते अपनी नई पीढ़ी के भविष्य की नींव रखने का प्लान कर चुका है। नारायण राणे के एक बेटे नितेश राणे कंकावली से विधायक हैं, जबकि दूसरे बेटे निलेश राणे कांग्रेस सांसद रह चुके हैं, 2014 में वो शिवसेना के विनायक राउत से चुनाव हार गए थे। मातोश्री से निकलकर चुनाव मैदान में उतरने का रिकॉर्ड कायम करने वाले आदित्य ठाकरे के बाद, अब उद्धव ठाकरे तेजस ठाकरे को फील्ड में लाने की तैयारी कर रहे हैं और

आगे की लड़ाई अगली पीढ़ी पर फोकस है

निकाय चुनावों को तेजस ठाकरे के लिए सियासी पारी शुरू करने का बढ़िया मौका समझा जा रहा है। ठाकरे परिवार से ही अमित ठाकरे भी निकाय चुनावों की तैयारी में जी जान से जुट गए हैं। अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे हैं। अमित ठाकरे चुनाव कैम्पेन में तो पहले भी शामिल होते रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर उनको पिछले साल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ज्वाइन कराया गया। मुहूर्त के साथ-साथ मौका भी इसके लिए खास चुना गया था, 23 जनवरी यानी शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती।

20 24 के लिहाज से भाजपा के लिए उप्र में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो जो हालात काफी हद तक अभी भाजपा के पक्ष में नजर आ रहे हैं, वो बदल सकते हैं। वहीं, सपा की बात

करें, तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव

की साख दांव पर लगी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर हार का बोझ उन्हें अपने ही कंधों पर उठाना पड़ा। क्योंकि,

कांग्रेस तो वैसे ही प्रदेश में

तकरीबन खत्म हो चुकी थी। वहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन का नुकसान भी सपा के खाते में ही गया था। खैर, इस नफे-नुकसान से इतर बड़ा सवाल तो यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? हाल ही में योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आई थीं। कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार प्रदेश के कई बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाकर बड़ा संदेश देना चाहती है। वैसे, भाजपा जो संदेश देना चाहती है, वो शायद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि, सपा की ओर से अभी तक अखिलेश के चुनाव लड़ने की कोई खबर सामने नहीं आई है।

योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ये दोनों ही नेता मुख्यमंत्री बनने के बाद उप्र विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो, इस बात की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है कि योगी और अखिलेश चुनाव ही न लड़ें। और जनता की अदालत में जाने की जगह फिर से उच्च सदन की राह पकड़ लें। हालांकि, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, तो दोनों ही नेताओं के सामने खुद को साबित करने की चुनौती नहीं है। क्योंकि, ये दोनों ही सांसद रहे हैं, तो योगी और अखिलेश के लिए विधानसभा चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नजर नहीं आती है। लेकिन, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों चुनाव ही न लड़ें और पिछली बार की ही तरह विधान परिषद की राह पकड़ लें।

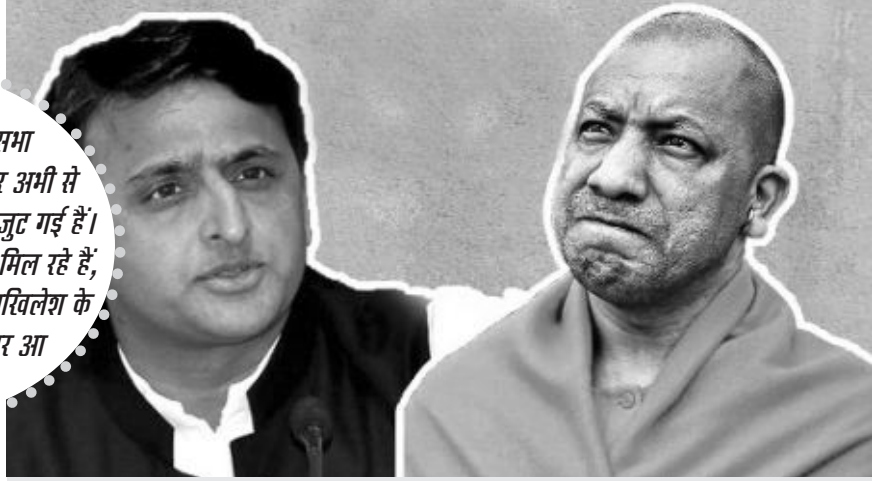
योगी और अखिलेश दोनों ही लंबे समय तक सांसद रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर हैं और गोरखपुर संसदीय सीट से

उप्र

में अगले साल विधानसभा

चुनाव होना है। इसको लेकर अभी से राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। फिलहाल जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे प्रदेश में योगी बनाम अखिलेश के बीच मुकाबला होता नजर आ रहा है।

योगी बनाम अखिलेश



खुद को चक्रवर्ती साबित करेंगे योगी

योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अपराधियों को प्रदेश छोड़ने की चुनौती दे दी थी। भ्रष्टाचार से लेकर माफियाओं तक के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी की जीरो टॉलरेंस नीति काफी सुर्खियों में रही है। एटी रोमियो स्कॉर्ड से शुरुआत कर वो अब जनसंख्या नियंत्रण कानून तक आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी का मानना है कि उन्हें हर तबके के लोग पसंद करते हैं। इस स्थिति में अगर योगी और अखिलेश दोनों नेता चुनाव लड़ते हैं, तो क्या योगी खुद अखिलेश के गढ़ में जाकर खुद को उग्र के चक्रवर्ती साबित करना चाहेंगे? इस सवाल पर कल्पना के घोड़े दौड़ाते ही सियासी थर्मामीटर का पारा फेल होता नजर आने लगता है। अगर योगी आदित्यनाथ ऐसा करते हैं और हार या जीत में कुछ भी होता है, तो प्रदेश के साथ ही देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

1998 से सांसद बनते आ रहे हैं। वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि, 2019 में उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की लोकसभा सीट आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा था। अगर दोनों नेताओं को चुनाव लड़ना होगा, तो ये तय है कि वो अपने कंफर्ट वाली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। कंफर्ट वाली सीट को आसान शब्दों में कहा जाए, तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर संसदीय सीट के अंदर आने वाली किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़कर आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं, अखिलेश यादव भी निश्चित तौर पर ऐसा ही करेंगे। आजमगढ़ जो कभी मुलायम का गढ़ था, उस सीट से अखिलेश के लिए चुनाव जीतने में शायद ही कोई बड़ी बाधा सामने आएगी।

योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक-दूसरे को जुबानी चुनौती देते रहे हैं। 'बाबाजी जाने वाले हैं' और 'उनके अब्बाजान कहते थे' जैसे शब्दबाणों के बीच दोनों ही नेता बयानों के सहारे बढ़त हासिल करने की कोशिश करते नजर आते हैं। अगर मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं, तो अपने कंफर्ट सीट से ही चुनाव

लड़ेंगे। लेकिन, असली चैलेंज तो ये है कि ये दोनों नेता आपस में एक सीट तय कर लें, और वहां से आमने-सामने का चुनाव लड़ें। दोनों नेताओं के बीच होने वाले इस चुनावी संग्राम से काडर में भी जोश बढ़ेगा और मतदाताओं का आनंद भी दोगुना हो जाएगा।

उप्र में भाजपा के सामने सबसे बड़े चैलेंजर के तौर पर समाजवादी पार्टी का नाम ही सामने आ रहा है। और, वैसे भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो उनके सामने सपा के मुखिया होने के नाते मुख्य चैलेंजर अखिलेश यादव ही हैं। अखिलेश यादव भी सपा को भाजपा के सामने मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टी के तौर पर पेश कर रहे हैं। अखिलेश ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किए गए विकास कार्यों के सहारे भाजपा को केवल अपनी सरकार के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाली पार्टी साबित करने में उन्होंने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। चूंकि, चैलेंजर अखिलेश यादव हैं तो क्या वे योगी आदित्यनाथ को मैदान में आने के लिए ताल ठोकेंगे? अगर ऐसा हो जाता है, तो इस बार के उग्र विधानसभा चुनाव की रोचकता कई मायनों में अन्य चुनावों के महत्व को शून्य कर देगी।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

सपने सभी देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी। लेकिन अगर उज्वल भविष्य का सपना वर्तमान को अंधकारमय करने लगे तो उसे सपना नहीं 'नॉनसेंस' कहते हैं। इस 'नॉनसेंस' शब्द का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में

किया, जब उनसे उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने के बारे में पूछा गया। यह संयोग मात्र नहीं हो सकता कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के सपने पर लगाम उसी दिन लगी जिस दिन उनके सहयोगी दल भाजपा में चिराग पासवान धड़े के दो बड़े नेता लोक जनशक्ति पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। शायद यह एक चेतावनी थी जिसे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने ठीक तरह से समझ लिया कि अभी वह समय नहीं आया है कि भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंगा लिया जाए।

विरोधी दलों को तोड़ने की कला में कभी कांग्रेस पार्टी पारंगत होती थी, पर भाजपा का वर्तमान में कोई मुकाबला नहीं है। जेडीयू ने इसकी एक छोटी सी झलक पिछले वर्ष हुए बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक बाद भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में देखी थी, जब जेडीयू के 7 में से 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। नीतीश कुमार ने उस समय उस मुद्दे को वहीं दबा दिया, यह कहकर कि जेडीयू और भाजपा का गठबंधन सिर्फ बिहार तक ही सीमित है, किसी अन्य राज्य में नहीं है। कुछ समय के लिए ही सही, पर इस घटना के बाद जेडीयू और भाजपा के संबंधों में थोड़ी खटास जरूर आ गई थी। एलजेपी का पिछले महीने विभाजन हो गया जब एलजेपी के संस्थापक स्व. रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस ने पार्टी पर कब्जा कर लिया और अपने भतीजे चिराग पासवान को पार्टी अध्यक्ष पद से बेदखल कर दिया। माना जाता है कि पशुपति पारस के विद्रोह के पीछे नीतीश कुमार का हाथ था।

एनडीए में होने के बावजूद चिराग नीतीश कुमार के आलोचक थे। एलजेपी ने बिहार चुनाव में एनडीए से बाहर रहकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। एलजेपी भाजपा का समर्थन कर रही थी और जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। नतीजा, चिराग फ्लॉप हो गए, एलजेपी मात्र एक सीट ही जीत पाई पर जेडीयू का भारी नुकसान किया। नीतीश कुमार की पार्टी 71 सीटों से लुढ़ककर 43 सीटों पर सिमट गई। नीतीश

पीएम मटीरियल नीतीश कुमार



राजनीति में कोई भी फैसला पूर्णकालिक नहीं होता

बहरहाल नीतीश कुमार की कुर्सी सुरक्षित रहेगी, पर यह सोचना कि वह प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना छोड़ देंगे सही नहीं होगा। अभी भी कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो ना तो भाजपा के साथ हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी के साथ। इन दलों में ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति, उप्र के दो बड़े विपक्षी दल सपा और बसपा तथा पंजाब में भाजपा की पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल प्रमुख हैं। इसके अलावा और भी कई छोटे दल हैं जो ना तो भाजपा के प्रशंसक हैं ना ही विरोधी। लिहाजा नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति पर पैनी नजर रखेंगे और संभव है कि अगले लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले वह अपना नॉनसेंस वाला बयान वापस ले लें और अपने सपनों को साकार करने में जुट जाएं। क्योंकि जहां नीतीश कुमार हैं, वहां सब कुछ संभव है। नैतिकता, जनादेश, वगैरह की जंजीरों से उन्होंने बहुत पहले भी अपने आप को मुक्त कर लिया था।

कुमार मुख्यमंत्री तो बने पर भाजपा की बदौलत। पहली बार जेडीयू को भाजपा के मुकाबले कम सीटों पर जीत नसीब हुई और वह भी तब जबकि जेडीयू ने भाजपा से कहीं अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था। एलजेपी में बगावत और चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाने को नीतीश कुमार का प्रतिशोध माना गया। एलजेपी के जिन

दो नेताओं ने कल चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया उनके पास विकल्प था कि वह पशुपति पारस के साथ जुट जाएं या फिर जेडीयू में शामिल हो जाएं। पर उनका भाजपा में शामिल होना एक संकेत था और जेडीयू के लिए चेतावनी भी।

उधर, विगत दिनों पटना में जेडीयू की एक अहम बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने घोषणा की कि नीतीश कुमार का फोकस बिहार है और उन्हें प्रधानमंत्री बनने की कोई चाह नहीं है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने 'नॉनसेंस' शब्द का प्रयोग कर के इस चर्चा पर पूर्णविराम लगाने की कोशिश की। तो क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश कुमार सच में प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे थे और इस चर्चा को खत्म करने के निर्णय के पीछे भाजपा का खौफ नहीं था कि अगर वह एक सीमा से बाहर गए तो बिहार में भी जेडीयू को तोड़ा जा सकता है।

पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की राजनीति में दखल देने की सोची। चर्चा चलने लगी कि मोदी के खिलाफ वह संयुक्त विपक्ष की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन सकती हैं। ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर भी आईं और कई गैर-भाजपा दलों के नेताओं से उनकी मीटिंग भी हुई। लगभग ठीक उसी समय जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई, जिसके बाद जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को 'पीएम मटीरियल' घोषित कर दिया। लेकिन ना तो केसी त्यागी ने उस समय कुछ बोला, ना ही नीतीश कुमार ने उस समय इसे नॉनसेंस करार किया।

ठीक इसके विपरीत वह इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला से भी मिले। चौटाला अपने स्तर पर गैर-भाजपा और गैर-कांग्रेस दलों का तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर भाजपा के कल एक छोटे से झटके के बाद नीतीश कुमार को शायद यह अहसास हो गया कि भाजपा से पंगा लेने का क्या फल हो सकता है। प्रधानमंत्री बनने का सपना पालते-पालते कहीं उनका मुख्यमंत्री पद भी ना चला जाए, यह सोचकर नीतीश कुमार और जेडीयू ने एक कदम पीछे खींचने का निर्णय लिया और इस पूरे चर्चा को नॉनसेंस बताकर खत्म करने की कोशिश की।

● विनोद बक्सरी

तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी नई सरकार का ऐलान कर दिया है। इस सरकार का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा। इसके प्रमुख यानी प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद होंगे। उनके दो उप प्रधानमंत्री होंगे, जिनमें मुल्ला बरादर भी शामिल हैं। तालिबान पिछले दो साल से दावा कर रहा था कि सत्ता में आने पर वह समावेशी सरकार बनाएगा, लेकिन इस सरकार में अफगानिस्तान के अलग-अलग समूहों की हिस्सेदारी नजर नहीं आ रही है। हालांकि तालिबान ने कहा है कि अभी कार्यवाहक मंत्री परिषद की घोषणा की गई है। समावेशी सरकार को लेकर चर्चा चल रही है।

तालिबान ने कुल 33 मंत्रियों की घोषणा की है इनमें से 30 पशतून हैं, 2 ताजिक हैं और एक उज्बेक मूल के हैं। एक ही परिवार (हक्कानी नेटवर्क) के 4 मंत्री हैं। अफगानिस्तान के युवा, महिलाएं, राजनेता इस सरकार में शामिल नहीं हैं। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हजार समूह से भी कोई मंत्री नहीं लिया गया है। तालिबान के मंत्री पदों के बंटवारे से साफ नजर आ रहा है कि तालिबान के अलग-अलग समूहों के आंतरिक मतभेदों को कम करने के लिए आपस में पद बांट लिए गए हैं। तालिबान के सीनियर लीडर्स को मंत्री बनाया गया है, ताकि उनके ग्रुप में पनप रहे असंतोष को कम किया जा सके।

अधिकतर मंत्रियों के पास मंत्रालय संभालने के लिए जरूरी योग्यता या अनुभव नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि नई सरकार के बनने से प्रशासन में शायद ही कोई सुधार हो, क्योंकि तालिबान की इस सरकार को आसानी से अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान अभी बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सरकार को प्रशासन के लिए आर्थिक मदद की जरूरत भी होगी। बिना मान्यता के शायद ही अर्थव्यवस्था को कोई ठोस मदद मिल पाए। तालिबान के प्रमुख शेख हिब्दुल्लाह अखुंदजादा सुप्रीम लीडर होंगे। उन्हें अमीर-उल-अफगानिस्तान कहा जाएगा। उनके प्रधानमंत्री समेत सरकार में शामिल सभी 33 मंत्री तालिबान से ही बनाए गए हैं। पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि तालिबान ने मंत्री पदों की बंदरबाट की है। जिस समावेशी सरकार का वादा किया था, उसके बारे में तालिबान ने इतना ही कहा है कि इस पर चर्चा की जा रही है।

20 साल बाद अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा। 20 साल बाद ही एक बार फिर तालिबान ने हुकूमत का औपचारिक ऐलान कर दिया। तालिबान घोषित आतंकी संगठन है और जाहिर सी बात है कि उसकी सरकार में दहशतगर्दों को ही जगह मिलनी थी, और मिली भी। एक नाम और उसका ओहदा या कहें

आतंक की सरकार



अमी केयरटेकर सरकार

तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि अभी एक केयरटेकर कैबिनेट सरकार की जिम्मेदारी संभालेगी। यानी यह अंतरिम सरकार है। तालिबान का कहना है कि समावेशी सरकार के गठन को लेकर चर्चा चल रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से ठीक पहले तुर्की के विदेश मंत्री यूसुफ एरिम ने अहम बयान दिया है। यूसुफ ने कहा- हमारी दुनिया को यही सलाह है कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता देने में किसी तरह की जल्दबाजी न करें।

पोर्टफोलियो, अमेरिका और दुनिया को चौंका रहा है। ये नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी। वो कितना खूंखार आतंकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने उस पर 50 लाख डॉलर (ईंडियन करेंसी के मुताबिक करीब 37 करोड़ रुपये) का इनाम घोषित कर रखा है। सिराजुद्दीन और उसके पिता ने 2008 में काबुल के भारतीय दूतावास पर भी हमला कराया था। इसमें 58 लोग मारे गए थे। 2011 में अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ रहे जनरल माइक मुलेन ने हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का दायां हाथ और एजेंट बताया था।

फिदायीन हमलों का इतिहास कई दशक पुराना है। माना जाता है कि श्रीलंका में सिविल वॉर के वक्त इनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अफगानिस्तान में फिदायीन या आत्मघाती हमले शुरू करने वाला हक्कानी नेटवर्क और खास तौर पर यही सिराजुद्दीन हक्कानी माना जाता है। अफगानिस्तान में इन हमलों में अब तक हजारों बेकसूर मारे जा चुके हैं। सिराजुद्दीन ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या की साजिश भी इन्हीं हमलों के तहत रची थी। ये नाकाम रही। कहा जाता है कि

सिराजुद्दीन के पिता और हक्कानी नेटवर्क की स्थापना करने वाला जलालुद्दीन हक्कानी 2013 या 2015 के बीच मारा गया, लेकिन सिराजुद्दीन 2001 के बाद से ही हक्कानी नेटवर्क का सरगना बना हुआ है। सिराजुद्दीन पाकिस्तान के वजीरिस्तान में ही रहता है।

शायद कम लोगों को पता होगा कि तालिबान किसी एक संगठन का नाम नहीं है। इसमें कई गुट, कई कबीले और कई धड़े हैं। हक्कानी नेटवर्क को आप इनमें से एक मान सकते हैं। अफगान तालिबान अलग है और पाकिस्तान तालिबान अलग। बस एक चीज कॉमन है। ये सभी कट्टरपंथी और आतंकी संगठन हैं जो शरीयत के हिसाब से हुकूमत चलाना चाहते हैं। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क अपनी सुविधा के हिसाब से एक-दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। अफगान तालिबान को सत्ता में आने के लिए हक्कानी नेटवर्क ने दिल-ओ-जान से मदद की। नतीजा सामने है। उसका सरगना अब अफगानिस्तान का होम मिनिस्टर होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क एक होकर भी अलग हैं, और अलग होकर भी एक हैं।

● ऋतेन्द्र माथुर

अफगानिस्तान में बाइडन ने जो अनर्थ किया है और जिस दिशा में अमेरिकी विदेश नीति जाती दिख रही है उसे देखते हुए अमेरिका विरोधियों का हौसला बढ़ना तय है। वहीं अमेरिका के संगी-साथियों को नए सिरे से आंकलन करना होगा, क्योंकि अमेरिकी रुख अब संदिग्ध लगने लगा है। अब यूक्रेन चिंतित है कि जैसे बाइडन ने अफगान सरकार को दगा दिया, वैसे ही वह उन्हें भी अधर में छोड़ देंगे। चिंता ताइवान को भी सता रही है कि बाइडन की ऐतिहासिक भूल के बाद चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग उसके खिलाफ कोई जंग छेड़ सकते हैं। ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन के बयान में यह ध्वनि भी होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकते।

अमेरिका को लेकर ऐसी आशंकाएं निराधार नहीं हैं। बाइडन ने अफगानिस्तान को जिस तरह आतंकियों को तशरी में परोस कर दे दिया, वह अंतर्राष्ट्रीय जिहादी मुहिम के लिए एक बड़ी जीत है। यह भी एक दुर्योग है कि बाइडन के सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों के भीतर आतंकियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। ऐसे में निश्चित है कि यह बाइडन की आखिरी भूल नहीं साबित होगी। राष्ट्रपति बनने से पहले बाइडन कई अहम पदों पर रहे हैं। उस दौरान उनके सहयोगी रहे तमाम लोग उनकी नीतियों और फैसलों को लेकर सवाल उठा चुके हैं। वे अब सही साबित हो रहे हैं। केवल अमेरिकी ही नहीं, बल्कि उनके दुश्मनों का भी बाइडन को लेकर नजरिया सही साबित होता दिख रहा है। दुनिया के दुर्दांत आतंकी ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर मौत के घाट उतारा था तो लादेन के परिसर से एक चिट्ठी मिली थी। उसमें अलकायदा के लिए यह संदेश था कि वह तत्कालीन उपराष्ट्रपति बाइडन को निशाना न बनाए, क्योंकि उनके एक दिन राष्ट्रपति बनने की संभावना है और चूँकि वह काबिल नहीं तो निश्चित ही अमेरिका को किसी संकट में झोंक देंगे। यानी लादेन का आंकलन भी सभी जिहादियों के लिए खुशी की सौगात वाला साबित हुआ। इस बीच अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को लेकर बाइडन ने 'अच्छे' और 'बुरे' आतंकियों वाला शिगूफा छेड़ा है।

अफगानिस्तान में अपनी अनर्थकारी वापसी को लेकर गलती मानने के बजाय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा उसे वाजिब ठहराने की कोशिश यही दर्शाती है कि यह उनके प्रशासन का ऐसा इफ़लौता फैसला नहीं होने जा रहा। बाइडन इसे अपने नेतृत्व में अमेरिका के रणनीतिक उद्देश्यों के आधारभूत पुनर्संयोजन का प्रतीक बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इराक से भी इस साल वापसी की बात कही है। उनकी इन बातों से यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं से कदम पीछे खींच रहा है?

मुग़लते में अमेरिका

जैसे उन्होंने आईएस-खुरासान को तालिबान का दुश्मन बताया, जबकि इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि चाहे अलकायदा हो या आईएस-खुरासान, सभी अमेरिका और स्वतंत्र एवं उदार विश्व के दुश्मन हैं।

भले ही तालिबान, अलकायदा और आईएस-खुरासान की पहचान अलग-अलग हो, लेकिन उनकी एक साझा विचारधारा है, जो हिंसक जिहाद से जुड़ी है। उनके सदस्यों में आपसी मेलजोल रहा है। वे एक आतंकी धड़े से दूसरे में भी शामिल होते रहते हैं। यहां तक कि उनके सदस्य एक-दूसरे के परिवार में वैवाहिक रिश्ते भी बनाते हैं। हक्कानी नेटवर्क भी ऐसा ही एक आतंकी धड़ा है। इसे तालिबान की स्पेशल फोर्स के साथ ही पाकिस्तानी सरकारी आतंकी मशीनरी का अहम हिस्सा भी माना जाता है। यह उसी व्यापक धारणा को पुष्ट करता है कि अफगानिस्तान में आतंक की असली कड़ी पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आईएस-खुरासान में आतंकियों की भर्ती के लिए हक्कानी का ही इस्तेमाल किया, ताकि आतंकी गतिविधियां भी चलती रहें और उसके दामन पर उनका दाग भी न लगे।

जहां तक अलकायदा का सवाल है तो

काबुल पर कब्जे के बाद से तालिबान के प्रवक्ता ने उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उल्टे उसने यहां तक कहा कि अमेरिका में 9/11 हमले में लादेन की संलिप्तता के कोई सबूत नहीं। जो लोग तालिबान और अलकायदा को जुदा समझते हैं, उनके लिए यह एक दुष्टांत है। अक्टूबर 2015 में जनरल जान एफ केंपबेल के नेतृत्व में अमेरिकी सेनाओं ने दक्षिणपूर्वी अफगानिस्तान में अलकायदा के सबसे बड़े आतंकी ठिकाने का पता लगाया था जो करीब 30 वर्ग मील के दायरे में फैला हुआ था। मालूम पड़ा कि वहां अलकायदा और तालिबान के रंगरूट एक साथ प्रशिक्षण लेने के अलावा उसका साथ में संचालन कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक हालिया रपट के अनुसार तालिबान और अलकायदा में अभी भी नजदीकियां बनी हुई हैं। ऐसी स्थिति में तालिबान को प्रोत्साहित करने के बजाय उस पर शिकंजा कसना चाहिए था। इसके उलट बाइडन प्रशासन ने न केवल उसके लिए करोड़ों डॉलर के अत्याधुनिक हथियार छोड़ दिए, बल्कि इस आतंकी समूह के साथ साझेदारी का भी ऐलान किया। याद रहे कि इसी क्रूर आतंकी संगठन के हाथ 2,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों के खून से रंगे हुए हैं।

● कुमार विनोद

बाइडन प्रशासन कई मुग़लते पाले हुए है। वह मानता है कि तालिबान और अमेरिका, दोनों आईएस-खुरासान के शत्रु हैं। जबकि तालिबान ने ही खुरासान के कई आतंकियों को अमेरिकी कैद से छुड़ाया। ऐसे में वे कैसे दुश्मन हो सकते हैं? इसी तरह वह तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को अलग संगठन मानता है। जबकि इसी हक्कानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान के शीर्ष नेताओं में शुमार है और उसे नई अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला है। यही हक्कानी नेटवर्क मानव बम बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी दस्ता

अमेरिका की नीतियां दोषपूर्ण

है। इसके बावजूद बाइडन प्रशासन ने काबुल से अपने और सहयोगी देशों के नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए इसी हक्कानी नेटवर्क पर भरोसा किया और अफगान में शेष रह गए लोगों को इन विक्षिप्त धार्मिक उन्मादी तानाशाहों के रहमोकरम पर छोड़ दिया। बाइडन भले ही अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध की समाप्ति का श्रेय लेना चाहते हों, मगर उन्होंने अफगानिस्तान को बड़े खतरे की आग में झोंक दिया है। बाइडन ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख को जो नुकसान पहुंचाया है, उसका सिलसिला लंबा खिंच सकता है।

शां ति का टापू कहा जाने वाला मद्रास अब रेप की लगातार बढ़ती घटनाओं की वजह से दहलने लगा है। यहां महिलाओं पर लगातार बढ़ रहे अपराध ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते

4 महीनों के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मासूम बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक सुरक्षित नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में यहां 40 फीसदी रेप के केस बढ़े हैं। यह खुलासा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के आंकड़ों के तहत हुआ है।

साल 2021 के पहले 4 महीने में रेप के मामले साल 2020 की तुलना में बढ़कर 40 फीसदी हो गए हैं। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2020 के 4 महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में 1321 मामले सामने आए और साल 2021 में इन महीनों में यह संख्या बढ़कर 1841 हो गई। 2019 की तुलना में साल 2020 में रेप के मामलों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई थी। 2019 में जहां राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में रेप के 2485 मामले सामने आए थे। वहीं 2020 में यह संख्या बढ़कर 4553 हो गई थी। साल 2021 में 4 माह में महिलाओं के शील भंग का कृत्य 2908 और वर्ष 2020 में 2580 था।

हाल ही में पुलिस महानिदेशक विवेक चौहरी ने पुलिस मुख्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, जोनल एडीजी, आईजी से चर्चा कर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, ऊर्जा डेस्क, महिला थाना और महिला डेस्क के कार्यों की समीक्षा की थी। उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की तत्काल जांच, अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी, समय पर चालान पेश करने समेत कई सख्त निर्देश दिए थे। इस तरह की मीटिंग पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग से लेकर सरकार और जिले तक में समय-समय पर होती है, लेकिन यह तमाम मीटिंग उस समय जीरो साबित होती हैं, जब महिलाओं को लेकर इस तरीके के आंकड़े सामने आते हैं।

प्रदेश में लगातार रेप केस बढ़ने पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। कांग्रेस नेता केके मिश्रा कहते हैं कि प्रदेश देश की रेप कैपिटल बन गया है। यहां पर महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। भाजपा सिर्फ आरोप लगाती है। लेकिन यह आंकड़े सरकार के दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। महिलाओं पर अपराध के साथ

मद्रास में अभी भी महिलाएं असुरक्षित!

साल

2021 के पहले चार महीने में रेप के मामले साल 2020 की तुलना में बढ़कर 40 फीसदी हो गए हैं। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2020 के 4 महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में 1321 मामले सामने आए और साल 2021 में इन महीनों में यह संख्या बढ़कर 1841 हो गई।

राजधानी में 190 दिन में 3 करोड़ के 500 वाहन चोरी

वाहन चोरों ने भोपाल पुलिस की नाक में दम कर दी है। 6 महीने में राजधानी भोपाल से 3 करोड़ के 500 से ज्यादा वाहन चोरी जा चुके हैं लेकिन बदमाशों को पकड़ना तो दूर पुलिस उनका सुराग भी नहीं लगा पाई है। अब चोरों का सुराग देने वाले को साढ़े पांच लाख का इनाम देने की घोषणा की है। शहर में 67 डार्क पाइंट्स की पहचान की गई है और वाहन चोरों के जगह-जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। नाकों-चौराहों और पड़ोसी जिलों हर तरफ चोरों को तलाशा जा रहा है। भोपाल में पिछले 190 दिन यानि करीब सवा 6 महीने में एक के बाद एक 500 वाहन चोरी चले गए। इनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई। पुलिस पिछली वारदात का पता भी नहीं लगा पाती कि चोर अगली जगह से गाड़ी उड़ाकर रफूचककर हो जाते हैं। भोपाल पुलिस ने बढ़ती वारदातों पर लगाम लगाने के लिए इलाके चिन्हित किए तो वाहन चोरी के 67 डार्क स्पॉट सामने आए। ये चोर उन इलाकों में लगे सीसीटीवी में भी कैद हुए लेकिन फिर भी पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पा रही है। नए शहर में सबसे ज्यादा 52 वाहन गोविंदपुरा इलाके से चोरी हुए।

भ्रष्टाचार और माफिया का राज चरम पर है। वहीं भाजपा के महामंत्री भगवानदास सबनानी कहते हैं कि कांग्रेस के समय में महिला अपराध बढ़े थे। अब कांग्रेस भाजपा से सवाल-जवाब कर रही है। भाजपा सरकार में महिलाओं की सुनी जाती है। उनकी शिकायतों पर एफआईआर दर्ज होती है, इसलिए जरूर मामले बढ़े हुए आए हैं। सरकार महिला अपराध को लेकर संवेदनशील है।

21 अप्रैल 2020 से राज्य में जनता कर्फ्यू लगा दिया गया था। हैरानी की बात ये है कि उसी महीने राज्य में 666 अपहरण हुए। पिछले साल भी 22 मार्च से मई 2020 तक देश में पूर्ण तालाबंदी की गई थी। लेकिन, अपहरण की घटनाएं जारी रहीं। राज्य में अप्रैल में 207 और मई में 381 महिलाओं और लड़कियों का अपहरण किया गया। साल 2020 में कुल 6,887 लड़कियों और महिलाओं का अपहरण किया गया। साल 2019 में यह आंकड़ा 9,812 था। जून के महीने में कर्फ्यू में ढील के बाद अपहरण की संख्या 624 तक पहुंच गई और उसके बाद

यह बढ़ती रही। जबकि अपहरण की संख्या 2019 की तुलना में कम है। लेकिन यह संख्या अभी भी चिंता का विषय है। साल 2020 में अपहृत व्यक्तियों में लगभग 73 प्रतिशत लड़कियां और शेष महिलाएं थीं। जानकारी के अनुसार पिछले 8 साल में 2013 से 2020 के बीच 67,125 बच्चे लापता हुए हैं। इनमें बालिकाओं की संख्या 48,389 है। इस हिसाब से 8 सालों में हर रोज 22 बच्चे प्रदेश से लापता हो रहे हैं। इनमें 30 फीसदी बच्चों की बरामदगी नहीं हो पाती। पुलिस इन मामलों में मानव तस्करि के एंगल से जांच करती है। आदिवासी बहुल जिले बैतूल, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, मंडला आदि से बच्चों के लापता होने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। पिछले साल चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान में प्रदेश के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, उप्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना, बंगाल और राजस्थान से बालिकाओं की बरामदगी हुई थी। सीआईडी लापता बच्चों की मॉनिटरिंग करती है।

● ज्योत्सना अनूप यादव



भोपाल विकास प्राधिकरण

क्रमांक 631/सम्पदा/भोविप्रा/2021

भोपाल, दि. 9.09.2021

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित सम्पत्ति के ऑफर एवं नियत मूल्य पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित सम्पत्ति के ऑफर एवं नियत मूल्य दर पर ऑनलाईन आमंत्रित रिक्त सम्पत्ति जैसे:- भूखण्ड/ प्रकोष्ठ / डूप्लेक्स / हॉल / पीओएसपी भूखण्ड/दुकानें, जो कि निम्न तालिका में वर्णित होकर ऑन लाईन ऑफर वेबसाइट <https://vikspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से नियत दर, प्रस्ताव दिनांक 13.9.2021 से दिनांक 26.9.2021 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर / आवेदन पत्र दिनांक 27.9.2021 को खोले जावेंगे।

निम्न सम्पत्तियों का विस्तृत विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाइट www.bda.org.in पर देखे जा सकते हैं।

क्र.	योजना का नाम	ऑफर/नियत दर	सम्पत्ति का विवरण	संपत्ति की संख्या	रिमार्क
1.	लक्ष्मी नारायण एयरोसिटी चरण-1	ऑफर	भूखंड	137	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी. पी.एल.-17-246
2.	नबी बाग व्यवसायिक भूखंड	ऑफर	भूखंड व्यवसायिक	13	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी. पी.एल.-17-837
3.	स्वामी विवेकानंद परिसर, कटारा हिल्स	ऑफर	भूखंड	04	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
4.	मिसरोद फएस-1	ऑफर	भूखंड	16	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी. पी.एल.-20-2629
5.	सरदार वल्लभ भाई पटेल मिसरोद-2	ऑफर	भूखंड	07	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी. पी.एल.-17-1018
6.	सरदार वल्लभ भाई पटेल मिसरोद-2	ऑफर	नर्सरी एवं प्राईमरी स्कूल	03	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी. पी.एल.-17-1018
7.	गुरु रविन्द्रनाथ टेगौर, साकेत नगर	ऑफर	प्रकोष्ठ	02	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
8.	अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स	ऑफर	हॉल	02	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
9.	इंद्रपुरी सेक्टर-सी	ऑफर	भूखंड	01	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
10.	सोनिया गांधी परिसर	ऑफर	प्रकोष्ठ	01	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
11.	अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स	ऑफर	प्रकोष्ठ	01	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
12.	विद्या नगर	ऑफर	प्रकोष्ठ	01	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
13.	एम.जी. रूसिया नगर पीपलनेर	ऑफर	डूप्लेक्स	04	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
14.	अजंता कॉम्प्लेक्स	ऑफर	प्रकोष्ठ	02	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
15.	कटारा हिल्स सेक्टर-ए एवं सी	ऑफर	दुकानें	31	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
16.	आई.एस.बी.टी.	ऑफर	दुकानें	01	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
17.	गुरु रविन्द्रनाथ टेगौर, साकेत नगर	ऑफर	दुकानें	03	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
18.	अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स	ऑफर	दुकान	01	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
19.	पंचशील नगर	ऑफर	दुकानें	05	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
20.	महर्षि पतंजलि	ऑफर	दुकानें	35	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
21.	पंडित भीमसेन जोशी परिसर, साकेत नगर	ऑफर	दुकानें	03	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
22.	माता मंदिर	ऑफर	दुकान	06	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
23.	आमेर कॉम्प्लेक्स, नाले के ऊपर, एम.पी. नगर, जोन-2	ऑफर	दुकान	01	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
24.	बस स्टॉप नं. 7	ऑफर	दुकान	01	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
25.	बस स्टॉप नं. 2	ऑफर	दुकान	01	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
26.	स्वामी विवेकानंद परिसर कटारा हिल्स (भवन)	ऑफर	भवन	33	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी. पी.एल.-21-2845
27.	अमरावद खुर्द योजना	ऑफर	शाला भूखंड	02	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
28.	स्वामी विवेकानंद परिसर कटारा हिल्स	ऑफर	प्रकोष्ठ	45	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
29.	महर्षि पतंजलि, गोदरमऊ	नियत दर	प्रकोष्ठ	22	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
30.	अमरावद खुर्द	नियत दर	एल.आई.जी. डूप्लेक्स	21	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
31.	विनायक नगर गौदरमऊ	नियत दर	ई.डब्ल्यू.एस.	02	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित
32.	नबीबाग योजना	नियत दर	2 बीएचके प्रकोष्ठ 1 बीएचके प्रकोष्ठ	22 08	वर्ष 2017 से पूर्व निर्मित

सम्पदा अधिकारी,
भोपाल विकास प्राधिकरण

जनता के सेवक



मा ननीय नेताजी! क्या कहुँ उस सिरफिरे पत्रकार से? किसी भी तरह से टलने का नाम ही नहीं ले रहा। कह रहा है आप हमारे प्रतिनिधि हैं तो आपको हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। नेताजी के मुख्य सचिव ने कहा।

‘हूँ’ एक काम करो। उसे अंदर भेज दो। आज उसे इंटरव्यू दे ही देते हैं।

जी ठीक है...लेकिन वह बड़ा शातिर पत्रकार है, ध्यान रखिएगा।

कुछ देर बाद पत्रकार अपनी टीम के साथ नेताजी के कक्ष में पहुंचा। कैमेरा व माइक वगैरह की उचित सेटिंग के मध्य ही नेताजी कुनमुनाये, पत्रकार महोदय! जो करना है जल्दी कीजिए। अधिक समय नहीं है हमारे पास... हम...!

ओह, अच्छा!.. शायद इसी व्यस्तता की वजह

से आपको नौ महीनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे किसानों से सीधे बात करने की फुर्सत नहीं मिली? नेताजी की बात बीच में ही काटकर पत्रकार ने व्यंग्य बाण चलाए।

आप गलत बोल रहे हैं पत्रकार महोदय! हम और हमारी सरकार रात-दिन किसानों के हित के लिए काम कर रही है। हम उनके उज्वल भविष्य के लिए कृतसंकल्प हैं। नेताजी हल्का सा रोष प्रकट करते हुए बोले। कुछ पल रुककर वह अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, और आप जिन किसानों की बात कर रहे हैं, वह क्या सच में किसान हैं?

जी महोदय! सही कहा आपने... सच में इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वह सभी किसान ही हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सभी नेता वाकई जनता के सेवक हैं?

- राजकुमार कांडु

नारी



नारी, तुम इतना क्यों सहती हो, क्यों दो धारे में बहती हो, तेरे आंचल में गंगा जल, मन में तेरे अमृत है, पावनता सी माया तेरी, कोमल सहृदय काया तेरी, तन-मन के इस बंधन को, तर्पण करदो अर्पण करदो।

नारी...

गुमसुम सी तुम सोचमयी हो, मीरा सी तुम भक्तिमयी हो, राधा सी तुम चहक छबीली, मन की धारो में बहती हो, क्यों तुम इतना सहती हो?

नारी...

पग-पग पर सब कांटे हैं, क्षेत्र फूलों ने बांटे हैं, प्यार तो बाजार नहीं है, नहीं-नहीं व्यापार नहीं है, मन संताप क्यों रखती हो?

नारी...

- डॉ. मीरा त्रिपाठी पांडेय

ज ब से नेहा का दाखिला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ माईस में हुआ था, उसकी मां के आंखों से नौद उड़ गई थी।

लड़की जात! ऊपर से सहशिक्षा कैसे बेटी अपने दामन को बचाते हुए उड़ान भरेगी। सोच-सोच कर पागल हुई जा रही थी। बेचैनी में करवट बदलने से बेहतर लगा कि अपनी आशंकाओं पर खुलकर चर्चा अपनी बिटिया से ही कर लूं। यही सोचकर वह सूर्योदय से पहले ही बिस्तर छोड़ते हुए नेहा के संग प्रातः कालीन भ्रमण के लिए घर से निकली।

रास्ते में कहां से बातें शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नेहा शायद उसके मनोभावों को समझ रही थी। थोड़ी कि, कोयले की खान में तू हीरा है।

‘मां ऊपर आकाश में देखिए परिंदों के झुंड में आप बता सकती हैं कि नर



हीरे की खान

परिंदा कौन है, या मादा परिंदा कौन है या फिर कुछ ही दिनों पहले जन्म लिया सबसे छोटा परिंदा कौन है?’

बिटिया! यह कैसे सवाल हैं तुम्हारे? मुझे क्या किसी को इनकी उम्र का अंदाजा नहीं होगा। ‘बिल्कुल सही कहा आपने मां। बस एक ही सच है कि हर परिंदा अपने पंखों की क्षमताओं को समझते हुए स्वयं भी उड़ान भरता है एवं अपने बच्चों को भी उड़ने की कला बचपन से सिखाता है। बेटी की गूढ़ बातों को समझते हुए उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली- ‘मेरी बिटिया तो अभी से माइनिंग इंजीनियर बन गई है। मैं ही भूल रही

- आरती राँय

बचपन में जंगल से लकड़ियां उठाकर लाने वाली मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलिंपिक में 202 किलो वजन उठाया। उन्हें वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल मिला। जीत के बाद एक इंटरव्यू में मीराबाई ने कहा कि घर लौटने के बाद वो पिज्जा खाना चाहती हैं। डोमिनोज ने इस पर फौरन प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें पूरी जिंदगी फ्री पिज्जा देने का वादा किया। लौटने पर डोमिनोज ने न सिर्फ पिज्जा भिजवाया बल्कि चानू के साथ एक कॉमर्शियल डील भी की। ब्रांड्स की तवज्जो पाने वाली मीराबाई चानू अकेली ओलिंपिक मेडलिस्ट नहीं हैं।

नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, पीवी सिंधु, रवि दहिया और अन्य मेडलिस्ट को दर्जनों ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस खिलाड़ी ने किन ब्रांड्स के साथ करार किया है? ओलिंपिक से पहले और बाद की एंडोर्समेंट फीस में कितना अंतर आया? इन एथलीट्स के साथ ब्रांड्स लंबे वक्त का करार क्यों करना चाहते हैं?

पीवी सिंधु: टोक्यो ओलिंपिक के पहले भी पीवी सिंधु कई ब्रांड्स की फेवरेट रही हैं। सिंधु को मैनेज करने वाली कंपनी बेसलाइन वेंचर्स के यशवंत बियाला के मुताबिक कई नए ब्रांड्स ने सिंधु को अप्रोच किया है और कम से कम 2-3 साल का करार करना चाहते हैं। सिंधु इकलौती भारतीय महिला हैं जिन्होंने 2 ओलिंपिक मेडल जीते हैं। उनकी सालाना एंडोर्समेंट फीस में 60-70 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी जा रही है।



नीरज चोपड़ा: नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू में 10 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। नीरज को मैनेज करने वाली फर्म जेएसडब्ल्यू के सीईओ मुस्तफा गौस का कहना है कि ये बढ़ोतरी उनकी मेल और नॉन क्रिकेटिंग अचीवमेंट की वजह से हुई है। अभी तक मार्केट में या तो क्रिकेटर्स का दबदबा था या पीवी सिंधु, मैरी कॉम और सानिया मिर्जा जैसी महिला एथलीट्स का। नीरज ने इस धारणा को तोड़ा है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि नीरज की सालाना ब्रांड एंडोर्समेंट फीस करीब ढाई करोड़ रुपए है। ओलिंपिक के पहले ये 20-30 लाख होती थी।

10 गुना महंगे हो गए भारतीय एथलीट्स



मीराबाई चानू: मीराबाई चानू को मैनेज करने वाली कंपनी आईओएस स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राहुल त्रेहन का कहना है कि मेडल जीतने के बाद चानू के पास कई ब्रांड्स के ऑफर हैं। इनमें स्टील, इश्योरेंस, बैंकिंग, एडुटेक, एनर्जी ड्रिंक्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर शामिल हैं। फिलहाल चानू ने एम्बे इंडिया, मोबिल इंजन ऑइल, एडिडास ग्लोबल के साथ करार किया है। त्रेहन के मुताबिक चानू की मौजूदा एंडोर्समेंट फीस 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा है। टोक्यो ओलिंपिक से पहले ये 10 लाख के आसपास थी।



बजरंग पूनिया: टोक्यो ओलिंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने से पहले बजरंग पूनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कमाल कर चुके हैं। वहां तीन मेडल जीतने वाले वो भारत के इकलौते रेसलर हैं। ओलिंपिक से पहले भी उनके पास कई ब्रांड्स थे, लेकिन मेडल जीतने के बाद दर्जनों कंपनियों कतार में हैं। नीरज चोपड़ा की तरह उन्हें आईओएस फर्म मैनेज करती है। बजरंग पूनिया की ब्रांड वैल्यू में करीब 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

● आशीष नेमा



रवि दहिया युवा खिलाड़ी हैं। सिल्वर मेडल जीतने के बाद उनके पास भी कई ब्रांड्स का ऑफर है। रेसलर सुशील कुमार ने जब ओलिंपिक मेडल जीता था, तो उनके पास भी कई बड़े ब्रांड्स के ऑफर आए थे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी ब्रांड वैल्यू करीब 60 प्रतिशत तक बढ़ गई है। इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन ने बाक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनकी ब्रांड वैल्यू में भी करीब 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश की ब्रांड वैल्यू में करीब 150 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ओलिंपिक के इतर भी एथलीट्स को ब्रांड्स का साथ मिल रहा है। एशियन गेम्स 2018 में तीन मेडल जीतकर स्टार बनी स्प्रिंटर हिमा दास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एडिडास के साथ जुड़ी हैं। टोक्यो ओलिंपिक की 100 मीटर में क्वालिफाई करने वाली दुती चंद को ज्वेलरी रिटेल चैन सेन्को गोल्ड एंड डायमंड का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।



सिद्धार्थ शुक्ला की असमय मृत्यु के बाद से उनके जीवन के बहुत से किस्से खुलकर सामने आ रहे हैं। हर कोई किसी न किसी बहाने उन्हें याद कह रहा है। जिस भी उनसे जुड़ी कोई बात या कोई किस्सा याद आता है, वह उसे शेयर करता है।

सिद्धार्थ शुक्ला थे अपने पापा से इन्सायर, खुद भी बनना चाहते थे पिता



सिद्धार्थ का एक और स्टेटमेंट प्रकाश में आया है जिसमें उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वे पापा बनना चाहते हैं और वे दुनिया के सबसे अच्छे पापा बनेंगे। सिद्धार्थ ने बिग बॉस 14 के दौरान साथी गौहर खान और हिना खान से अपने दिल की बात शेयर की थी। बिग बॉस 13 के विजेता, हिना खान, गौहर खान के साथ सिद्धार्थ ने अगले सीजन में तूफानी सीनयर के तौर पर एंट्री ली थी। इस दौरान इन तीनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थी और वे तीनों एक-दूसरे से अपनी बातें शेयर करते थे। सिद्धार्थ ने अपने जीवन के बहुत से खास अनुभवों को हिना और गौहर के साथ साझा किया था। इसी दौरान उन्होंने दोनों को बताया था कि वे अपने पिता के बहुत करीब थे। कैसे उनकी डेथ हुई और कैसे सिद्धार्थ को आज भी उनकी कमी खलती है। अपने पिता से रिश्तों के चलते ही सिद्धार्थ खुद भी एक अच्छा पिता बनना चाहते थे। उनका मानना था कि वे जब भी पापा बनेंगे दुनिया के बेस्ट पापा होंगे। सिद्धार्थ के पिता की मृत्यु उस समय हुई थी जिस समय वे मॉडलिंग कर रहे थे। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ था। लेकिन परिवार को सपोर्ट करने के लिए उनके पिता ने काफी सालों तक बीमारी से संघर्ष किया।

आशा भोसले को अपनी बहू बनाने से आरडी बर्मन की मां ने कर दिया था इनकार

वकील न ऑफ हिंदी पॉप उर्फ आशा भोसले ने महज 10 साल की उम्र में अपने सिंगिंग कैरियर की शुरुआत की थी। अपने कैरियर में वे 20 भाषाओं में करीब 16 हजार गानों को अपनी खूबसूरत आवाज से सदाबहार बना चुकी हैं। सिंगिंग कैरियर के अलावा आशा और आरडी बर्मन की लव स्टोरी भी काफी सुर्खियों में रही है। आशा और आरडी बर्मन शादी करना चाहते थे लेकिन उनके लिए ये आसान नहीं था। जब आरडी अपनी और आशा की शादी की बात लेकर अपनी मां के पास पहुंचे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनकार का एक कारण ये



भी था कि आशा आरडी बर्मन से 6 साल बड़ी थीं। आरडी बर्मन की मां दोनों के रिश्ते से इतनी खफा थीं कि उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक वो जिंदा हैं, तब तक दोनों की शादी नहीं हो सकती और अगर वो ये शादी करना चाहते हैं तो आशा को अपनी मां की लाश के ऊपर से घर में लाना होगा। ये सुनकर आरडी बर्मन बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। दोनों शादी करना चाहते थे, हालांकि मां की नाराजगी के चलते ऐसा मुमकिन नहीं था। कुछ सालों के बाद आरडी बर्मन की मां बेहद बीमार रहने लगीं और उन्होंने किसी को भी पहचानना बंद कर दिया, जिसके बाद आरडी बर्मन और आशा ने शादी कर ली। शादी के महज 14 सालों बाद ही 1994 में आरडी बर्मन का निधन हो गया, और आशा फिर एक बार अकेली हो गईं।

जब आमिर ने भाई से कहा था- तुम अच्छे एक्टर नहीं हो, कुछ और काम देख लो

आमिर खान के भाई फैजल खान ने खुलासा किया है कि उनके भाई आमिर उन्हें अच्छा एक्टर नहीं मानते। फैजल ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हुए कहा, जब साल 2000 में मेला फ्लॉप हुई तो आमिर ने मुझसे कहा, फैजल तुम अच्छे एक्टर नहीं हो, मेला भी फ्लॉप हो चुकी है, अब क्या? अब तुम्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए।

फैजल ने आगे कहा, जब मैंने आमिर से कहा कि मेला फ्लॉप होने के अन्य कई और भी कारण



हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस डिस्कशन में नहीं पड़ना कि फिल्म क्यों फ्लॉप हुई वो तो जो सोच रहे थे, वही उन्होंने कहा। उन्होंने कहा तुम एक्टर

नहीं हो, तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कोई और कैरियर ऑप्शन तलाशना चाहिए।

फैजल ने आगे कहा कि जब आमिर उन्हें एक्टर ही नहीं मानते थे तो भला कैसे वो उनसे मदद मांग सकते थे हालांकि उन्होंने आमिर की प्रोडक्शन कंपनी में कुछ समय तक स्क्रिप्ट पढ़ने का काम किया। फैजल आमिर के साथ फिल्म मेला (2000) में नजर आए थे। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद फैजल इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए।

कुछ लोग अफवाहों की ऐसी एकल फैक्ट्री चलाते हैं कि पूछिए मत। उससे निकलने वाला झूठ देखते ही देखते ऐसा वायरल होता है कि लोगों की खोपड़ी घूम जाती है। अफवाहों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे बड़ी प्रामाणिक भी लगती हैं। उनमें तारीख होती है। किसी पत्र या पत्रिका का जिक्र भी होता है। बाकायदा पृष्ठ संख्या भी होती है, जिसे पढ़कर व्यक्ति को लगता है, बात तो सही है। पिछले दिनों इसी फैक्ट्री से निकले एक समाचार पर मेरी नजर पड़ी। खबर चिरकुटलाल जी की फैक्ट्री में तैयार हुई थी। समाचार यह था, '1920 में अमेरिका के पेंसिलवेनिया में रहने वाले राबर्ट डिकोस्टा ने अपनी पुस्तक-प्यूचर वर्ल्ड के पेज नंबर सत्रह में साफ-साफ लिख दिया था कि इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में क्योरोना नामक वायरस पूरी दुनिया में फैलेगा, जिसके शिकार होकर करोड़ों लोग मर जाएंगे। यह वायरस दो साल तक अपना असर दिखाएगा। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।'

इस समाचार को जब रामलाल ने वाट्सएप पर पढ़ा तो उसने श्यामलाल को फारवर्ड कर दिया। श्यामलाल ने उसे रामस्वरूप को भेज दिया। रामस्वरूप ने फलस्वरूप तक पहुंचा दिया। फलस्वरूप ने देवानंद को भेज दिया। देवानंद ने कलाकंद को और कलाकंद ने परमानंद के पास भेजकर कहा कि 'देखो पार्टनर, कोरोना के बारे में सौ साल पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी।' इसके बाद उनके द्वारा बनाए कई और झूठ पक-कर बारी-बारी से देश-भ्रमण के लिए निकले। धड़ाधड़ वायरल होने लगे। अब किसको फुरसत है कि गूगल में जाकर उनकी सच्चाई को खंगाले।

उस दिन चिरकुटलाल जी से हमारी भेंट हो गई। हमने उनसे पूछ लिया, 'आप तो गजब की फैक्ट्री चलाते हैं। कमाल है।' मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, 'मगर, मेरी तो कोई फैक्ट्री नहीं है। मैं तो बेरोजगार संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। गांव में खेती-बाड़ी है। सालभर का अनाज आ जाता है। उसे खाकर मगन रहता हूँ और मुन्नाभाई और सर्किट के माफिक दिनभर लगा रहता हूँ वाट्सएप में।' हमने कहा, 'लगे रहते हैं, यह तो बड़ी दुर्लभ घटना है। लगे ही रहना चाहिए, लेकिन अफवाह फैलाना ठीक बात नहीं। ऐसी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखनी चाहिए, जिसे पढ़कर लोगों में भ्रम की स्थिति बन जाए। किसी की छवि खराब हो। इस काम से बचना चाहिए। किसी दिन लेने-के-देने न पड़ जाए।' चिरकुटलाल मुस्कराते हुए बोले, 'आज तक तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सका। होता भी कैसे? हम तो गंजे हैं। कहिए तो आपके बारे में भी कोई स्टोरी बना दूँ।' मैंने उनको नमन किया और कहा, 'भगवान के लिए यह सब बंद करो। अफवाह फैलाना सबसे बड़ा पाप है।'



अफवाहों का आनंदलोक

'एक मछली भी सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक झूठ दिल्ली से चलता है और पूरे देश में धीरे-धीरे फैल जाता है। अगर वायरल करने का शौक ही है तो अच्छी-अच्छी बातें वायरल कीजिए। मेरी बात सुनकर चिरकुटलाल जी सिर खुजाने लगे और बोले, 'बाप रे! यह सब तो मुझसे न हो सकेगा।'

एक अफवाह के सिलसिले में जब मैंने चिरकुटलाल जी से पूछा, 'यह जानकारी आपको कहां से मिली', तो उन्होंने कहा, 'एक अखबार है-कैम छे सारो छे। उसके पेज नंबर तीन पर यह खबर है।' मैंने गूगल में सर्च किया तो इस नाम

का कोई अखबार ही नजर नहीं आया। मैंने डपटते हुए कहा, 'ऐसा तो कोई अखबार नहीं है!' इस पर चिरकुटलाल जी ने मुस्कराते हुए कहा, 'कल सपने में मैंने यह अखबार देखा था। और वह खबर भी मैंने देखी थी। यह सपना मैंने सुबह-सुबह देखा था और सुबह का सपना सच होता है, इसीलिए खबर बनाई है।'

मैंने कहा, 'एक मछली भी सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक झूठ दिल्ली से चलता है और पूरे देश में धीरे-धीरे फैल जाता है। अगर वायरल करने का शौक ही है तो अच्छी-अच्छी बातें वायरल कीजिए।' मेरी बात सुनकर चिरकुटलाल जी सिर खुजाने लगे और बोले, 'बाप रे! यह सब तो मुझसे न हो सकेगा। हम ठहरे उलटी खोपड़ी के आदमी और आप मुझे सीधी खोपड़ी का काम करने को कह रहे हैं।' इतना बोलकर वे श्याममुख हो गए। यानी चले गए। हम भी अपने काम में लग गए। कुछ दिनों बाद अखबार में छपी खबर देखी कि 'फर्जी खबरें वायरल करने वाले चिरकुटलाल पुलिस की गिरफ्त में।' यानी जिसका डर था बेददी, वही बात हो गई।

PRISM[®]
CEMENT

प्रिज़्म[®] चैम्पियन प्लस

जिम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.



दूर की सोच[®]

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in



**For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us**

D-10™ Hemoglobin Testing System

for HbA_{1c}, HbA₂ and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
β-thalassemia and
diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; it's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System combines diabetes and β-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or HbA₂/F/A_{1c} testing using primary tube sampling—so you can accomplish more in fewer steps. With the D-10™ System, it's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress—and that can be the difference for the people who count on you most.

Science House Medicals Pvt. Ltd.

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023

GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5  **Email : shbpl@rediffmail.com**

 **Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687**